हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक, बुधवार, दिनांक 06 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

06-02-2019/1100 /NS/HK /1

प्रश्न संख्याः 898

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें अधिकतम धनराशि कॉलेज भवन के लिए स्वीकृत हुई थी और इस प्रश्न के उत्तर में उसकी ही जानकारी दी गई है। मेरे क्षेत्र जिला बिलासपुर, घुमारवीं में अमरपुर सीनियर सेकैंडरी स्कूल है और इसके लिए वर्ष 2015-16 में लगभग 01 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि भवन निर्माण के लिए स्वीकृत हुई थी। लेकिन अभी तक इस भवन के लिए केवल 26 लाख रुपये ही मिले हैं और इस भवन का सारा कार्य अधूरा पड़ा है। वहां पर ठेकेदार द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, उसके कारण वहां पर अफरा-तफरी जैसा वातावरण बना रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लोक निर्माण विभाग को स्कूल भवन के लिए पैसा मिल जाता है तो इसका काम सुचारू रूप से हो सकता है और जल्दी हो पायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि यह धनराशि लोक निर्माण विभाग को कब तक उपलब्ध होगी ताकि यह काम जल्दी हो सके।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। इस स्कूल भवन के लिए वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में पैसों की डाइवर्शन हुई है और कुछ नहीं हुई है। इसमें कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यह सारा मामला लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा विभाग से पैसा उनको चला जाता है।

06.02.2019/1105/RKS/HK-1

शिक्षा मंत्री ___ जारी

उसके बाद डाइवर्सन वगैरह की जानी है। शिक्षा विभाग ने उन्हें डाइवर्सन के बारे में लिखा है लेकिन वह करे या न करे यह उन पर निर्भर है। लेकिन अभी जो सप्लीमैंटरी की गई है वह डिफरैंट है। इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के महाविद्यालय के बारे में सप्लीमैंटरी की है।

यदि धन की उपलब्धता होगी या कहीं से डाइवर्सन होगी तो उस कॉलेज में जो काम चल रहा है उसके लिए पैसा आबंटित किया जाएगा।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय, रामशहर भवन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है जबकि उस कॉलेज को शुरू हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। इस कॉलेज के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग के नाम जमीन भी ट्रांसफर करवा दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस भवन का निर्माण कब शुरू होगा और इस भवन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था यह प्रश्न मुख्य रूप से किसी और विषय पर है। इन्होंने पूछा है कि जो पैसा शिक्षा विभाग ने पी.डब्ल्यू.डी. को दिया है उसकी डाइवर्सन की जानी थी और जो डाइवर्सन नहीं की गई क्या उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? यह इनका प्रश्न था लेकिन जो सप्लीमैंटरी की गई है वह अलग है। जितने भी कॉलेज फाइनैंस की सहमति के बिना खोले गए थे उन 21 कॉलेजों में से 16 कॉलेज क्रियाशील हैं। इन कॉलेजों के लिए पहले 5 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी जबकि बाद में एक लाख रुपये ही जारी किए गए। जैसे-जैसे फाइनैंस की उपलब्धता होगी वैसे-वैसे विभाग विभिन्न कॉलेजों को पैसा स्वीकृत करेगा और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्ज क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तहर श्री राजिन्द्र गर्ग जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कॉलेज के बारे में कहा या जो रामशहर वाला कॉलेज है, इन दोनों कॉलेजों के लिए जैसे-जैसे फंड्स उपलब्ध होंगे, विभाग इन कॉलेजों के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करेगा।

श्री नन्द लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि जो पांच महाविद्यालय हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि विभाग के पास इनके लिए धन की उपलब्धता नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ज्यूरी में एक महाविद्यालय खुला है जहां पर बच्चे भी हैं और क्लासिज भी चल रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि

जिस तरह बाकी 16 कॉलेजिज के लिए स्कीम बनाई गई है उसी तरह इन पांच कॉलेजिज के लिए जिनमें ज्यूरी कॉलेज भी शामिल है, के बारे में क्या सरकार विचार करेगी?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ज्यूरी कॉलेज की बात कर रहे हैं। जब वर्ष 2017 में विधान सभा चुनाव होने वाले थे तो उस वर्ष सरकार ने 21 कॉलेज खोले जिनमें से से अधिकांश कॉलेजों की घोषणा मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट लगने के दो दिन पहले की गई। किसी भी कॉलेज के लिए फंड्स का प्रावधान नहीं था और किसी प्रकार की वित्त सहमति नहीं थी। उन कॉलेजों में कोई बच्चा दाखिल नहीं था। कई स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों के दो कमरों में महाविद्यालय का बोर्ड लगा दिया गया और वहां पर एक अध्यापक और एक नॉन टीचिंग स्टॉफ नियुक्त कर दिया गया। इसी तहर ज्यूरी महाविद्यालय की भी ऐसी स्थिति थी। वहां पर भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है और बच्चों का दाखिला भी संभव नहीं है। इसलिए जहां-जहां बच्चों के दाखिले नहीं हुए वहां पर विभाग ने कार्य शुरू नहीं किया। जिन कॉलेजों में कुछ-न-कुछ फंक्शनिंग प्रारंभ हो गई थी, बच्चे दाखिल हो गए थे, उन 16 कॉलेजिज को चला दिया गया है। यदि नॉर्म्ज की पूर्ति होगी, जमीन की उपलब्धता होगी या वहां पर बच्चों का दाखिला होगा तो हम बाकी कॉलेजिज को भी चलाएंगे और यदि नए कॉलेज खोलने की आवश्यकता होगी तो नए कॉलेज भी खोले जाएंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सप्लीमैंटरी के जवाब में कहा कि पिछली सरकार ने कॉलेज तो खोले लेकिन कॉलेजों के लिए पैसों व जमीन का प्रावधान नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो नैना देवी में डिग्री कॉलेज खुला है,

06.02.2019/1110/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 898 क्रमांगत

श्री राम लाल ठाकुर जारी....

वह नया नही खुला है, उसे खुले हुए 3-4 वर्ष हो गए हैं और उसके लिए 5 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र भी चला गया है। लेकिन उसके बाद जब बजट में शिक्षा विभाग द्वारा पैसा दिया गया वह 1 करोड़ 15 लाख रुपये दिया गया। इसका टोटल प्राक्कलन ज्यादा है। उस कॉलेज का कार्य इसलिए शुरू नहीं हो रहा है। इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जब तक 40 प्रतिशत बजट का प्रावधान नहीं होगा तब तक उस भवन की नींव का पत्थर नहीं रखा जाएगा और न ही भवन का कार्य शुरू होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप इकट्ठे यह न कहें कि सारे-के-सारे कालेजिज का पैसा नहीं दिया गया है। हमारे कॉलेज के लिए स्वीकृति पत्र भी 5 करोड़ रुपये का जा चुका है । इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 1 करोड़ 10-15 लाख रुपये उस भवन के लिए दे रखा है। वह पैसा 40 प्रतिशत नहीं है इसलिए भवन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को पढ़ ही लेता हूं। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र गर्ग जी का प्रश्न है, गत तीन वर्षों में लोग निर्माण विभाग द्वारा किन-किन भवन निर्माण कार्यों के बजट को किस-किस कार्य हेतु शिक्षा विभाग की अनुमति से स्थानांतरिक करने हेतु आदेश जारी किए गए, ब्यौरा वर्षवार आदेशों की प्रति सहित दें? जो हमने दे दिया है। इनमें कौन-कौन से कार्य थे जिनमें धनराशि को स्थानांतरित नहीं किया गया ब्यौरा स्थानांतरित न करने के कारणों व अधिकारियों के नाम सहित दें। यह भी सत्य है कि उन अधिकारियों के पास उन स्वीकृत कार्यों की एए एण्ड ईएस से अधिक धनराशि पड़ी रही और उससे शिक्षा विभाग के खातों में धनराशि आबंट की प्रविष्टियां गलत हो गई है और यदि हां तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई ब्यौरा दें ।

माननीय सदस्य ने जो नैना देवी कॉलेज के बारे में विशेष प्रश्न किया है उसकी जानकारी अभी मेरे पास नही है। मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को भेज दूंगा। ...(व्यवधान).....

श्री राम लाल ठाकुर : मैं कह रहा हूं कि पैसे का प्रावधान कर दिया गया था उसकी स्वीकृति का पत्र भी चला गया था। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिया है मैंने उसी पर अपना प्रश्न किया है।

06.02.2019/1110/बी0एस0/वाई0के0-2

शिक्षा मंत्री : जो 21 कॉलेज खुले हैं उसमें नैना देवी जी का कॉलेज नहीं आता और यही जवाब मैंने दिया है। जो 21 कॉलेज बिना वित्तीय प्रावधान के खोले गए उनका कोई पैसा नहीं आया है। माननीय सदस्य रिकार्ड देख सकते हैं।

प्रश्न संख्याः 1145

श्रीमती आशा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का काफी विस्तृत उत्तर दिया है मगर मैं इनसे यह जानना चाहूंगी कि इन्होंने जो मैडिकल ऑनकोलॉजी का अलग से यूनिट बनाने के लिए विभाग का एक अलग से प्रस्ताव है और जो टरसरी केयर सैंटर है। क्या यह सही है कि उसके लिए 45 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है? इसके अलावा एक प्रश्न और है जिसके उत्तर में आपने कहा है कि जो स्थान आपने चयनित किया है वह कोर एरिया में पड़ता है। उसके निर्माण हेतु अनुमति नही मिल रही है। मगर क्या यह सही है कि चमियाना में भी 52 बीघा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम से ट्रांस्फर हुई है क्या आप वहां पर कैंसर अस्पताल या जो टरसरी केयर सैंटर बनाने का प्रयास करेंगे ? क्योंकि वह ऑलरेडी विभाग के नाम से है और वहां पर कोई ग्रीन एरिया या एन.जी.टी. या कोर एरिया का कोई इश्यू नहीं है। अन्यथा यह 45 करोड़ रुपया लैप्स हो जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसका काफी विस्तार से उत्तर दिया है और आज जो तीन स्वास्थ्य विभाग

के प्रश्न लगे हैं वह लगभग आपस में जुड़े हुए हैं। जहां तक हमारा इस टरसरी कैंसर केयर सैंटर की बात है यह वर्तमान में आई.जी.एम.सी. में चल रह है । माननीय सदस्या ने कहा भी है कि भारत सरकार ने जो हमारा हैल्थ विभाग है उसने 45 करोड़ रुपये प्रदान किया है।

06.02.2019/1115/DT/YK/-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणा मंत्री .....जारी...

और ये हमें 90:10 में प्राप्त हुआ है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो यह राशि मिली इसमें से लगभग 30 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 70 प्रतिशत मशीनरी पार्टस पर खर्च होगी। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग का टरसरी केयर सेंटर है या कैंसर का अस्पताल है, उसके बिल्कुल साथ में इस कैंसर अस्पताल को बनाने के लिए जमीन स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज, शिमला को दे दी है। ये 5 मंजिला भवन 2295 वर्ग मीटर पर बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दिए हैं। कैंसर अस्पताल के नक्शे को अनुमोदन के लिए निदेशक, टी0सी0पी0 के कार्यालय में दिनांक 27.09.2018 को जमा किया गया और निदेशक टी0सी0पी0 ने मामले को आयुक्त, नगर निगम को भेजा है। आयुक्त, नगर निगम, शिमला ने प्रिसिंपल, आई0जी0एम0सी0, शिमला को दिनांक 20.10.2018 को सूचित किया और उन्होंने जो दस्तावेज़ मांगे थे, वे हमने नगर निगम, शिमला में पहुंचा दिए हैं। इस सम्पूर्ण मामले को कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, शिमला में 01.11.2018 को जमा किया गया था, क्योंकि चयनित भूमि कोर एरिया में आती है। ये सारे दस्तावेज अब हमने एन0जी0टी0 के पास भेज दिए हैं और एक हेयरिंग भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मामले को प्रस्यू कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें इसकी अप्रूव्ल शीघ्र ही मिल जाएगी। इसके लिए धनराशि भारत सरकार ने दी है। अभी तक कैंसर अस्पताल हेतु कुल 16.52 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है

जिसमें 14.87 करोड़ रुपये भारत सरकार और मु0 1.65 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार का शेयर जमा करवा दिया है। ये मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता था।

दूसरा, आपने सुपर स्पैशलिटीज जोकि चमयाणा में बन रही है के बारे में जानना चाहा है। वहां पर 14 सुपर स्पैशलिटीज बन रही हैं। इस सारे मामले को हमने एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किया है और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें इसकी अनुमति मिल जाएगी। हम शीघ्र ही इसका काम शुरू करेंगे।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय,मन्त्री जी ने बहुत अच्छा विस्तृत जवाब दिया है और इनके जवाब का हम स्वागत भी करते हैं। क्योंकि यह हिमाचल के लिए एक अच्छी सुविधा मिलेगी। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये पांच मंजिला अस्पताल बनाने जा रहे हैं और उसकी तैयारिया कर रहे हैं और इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि at present one Assistant Professor in IGMC Shimla is trained in Medical oncology. तो जब आपके पास इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तथा आपके पास ट्रेंड डॉक्टर एक ही है तो तब तक क्या आप कुछ डॉक्टरर्ज को ट्रेंड करने के लिए कुछ कदम उठएगें ? ताकि जब आपका सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो आपके पास उसके लिए डॉक्टर्ज और स्टाफ भी ट्रेंड उपलब्ध हो ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत समय अनुकूल प्रश्न पुछा है और मैं इस माननीय सदन के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं। की जो हमारा रेडियो थैरेपी का विभाग है यह कैंसर का जो विभाग है इस समय उस में लगभग एक प्रोफैसर है और एक एसोसिएट प्रोफैसर है असिस्टैंट प्रोफेसर्ज हैं और तीन एस.आर. हैं । जब वहां पर किमों थैरेपी होती है या रेडियो थैरेपी होती है तो ट्रेंड नर्सज भी वहां पर हैं ।

06-02-2019/1120/ए.जी./एन.जी./1

प्रश्न संख्याः 1145.... जारी....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ....जारी.....

जहां तक आपने मैडिकल ओनोकोलोजिस्ट की बात की है, वह अभी तक हमारे पास केवल एक है । क्योंकि रेडियेशन का काम कुछ प्रोफैसर्स अलग करते हैं और जो किमो थेरेपी होती है उसके लिए ये मैडिकल ओनोकोलोजिस्ट की बात है । हमारा प्रयास है कि कुछ डाक्टर डी.एम. की पढाई कर रहे हैं, डी.एम.डी की पढाई कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उनको यहां इस काम के लिए लगाया जाएगा । जहां तक आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी 14 सूपर स्पैशिलिटी चम्याणा में बन रही हैं, जब यह शिफट हो जाएगी तो स्थान खाली हो जाएगा तो इसलिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है वह पूर्ण हो जाएगी । यह मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा ।

श्री राकेश पठानिया : माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने पूछा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । माननीय मन्त्री जी भी कांगडा से सम्बन्ध रखते हैं और कांगडा के टाण्डा मैडिकल कालेज में इस समय किमो थेरेपी बिलकुल भी नहीं हो रही है । मैं आज आपके आई.जी.एम.सी. के कैन्सर अस्पताल से ही आ रहा हूं । मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही 8 पेशन्ट इस समय वहां पर एडमिट है और एक बिस्तर पर दो पेशन्ट हैं क्योंकि केवल 40 बैड का अस्पताल है । The people of Himachal Pradesh and the cancer patients cannot wait for that five storey building to come up. और ये जो आप ऐनेकोलोजिस्ट की बात कर रहे हैं और आपने लिखा है कि केवल दो मरीजों को रैफर किया गया है । 7 पेशन्ट तो पिछले 15 दिनों में मैं यहां से भेज चुका हूं । आपके पास वो बेसिक फैसेलिटीस नहीं हैं और टाण्डा में यदि आप

इसे हाई स्केल पर शुरू कर देते हैं और आपके पास बिल्डिंगस भी हैं, आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है, then why you are waiting for this building to come up. आप इसे लार्जर लेवल पर टाण्डा में शुरू क्यों नहीं करते हैं ? आपको यह पता होगा की कैन्सर के पेशन्टस आज बहुत तेजी से बढ रहे हैं । In last couple of years इतना स्पर्ट आया है कैन्सर पेशेन्टस में

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रश्न पूछीए ।

श्री राकेश पठानिया : हम लोग अभी इतने सफीशियन्ट नहीं है इस रश को डील करने के लिए ।

अध्यक्ष : श्री राकेश जी आप अपना प्रश्न पढिए ।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से यह चाहा रहा हूं कि क्या आप इसे टाण्डा मैडिकल कालेज में इस फैसेलिटी को हाई स्केल पर शुरू करेंगे ? ताकी हमारे पेशन्टस को शिमला न आना पडे ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : माननीय सदस्य ने टाण्डा के बारे में जानना चाहा है या आई.जी.एम.सी के बारे में जानना चाहा है क्योंकि आप कह रहे थे कि आप अभी आई.जी.एम.सी . गए थे ।

श्री राकेश पठानिया : आपने लिखा है कि आईजीएमसी में 40 से 60 । जबकी आई.जी.एम.सी. में 200 से 300 पेशन्ट हर रोज आता है । आपने जबाव गलत दिया है । टाण्डा में आपने 12 से 14 पेशन्ट लिखे है, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता । अगर टाण्डा में पूरी फैसेलिटीस शुरू हो जाए तो टाण्डा will be sufficient to deal with it.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, अब मैं दोनो मैडिकल कालेजों की वास्तुस्थिति आपके माध्यम से इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं । यदि हम आई.जी.एम.सी. के कैन्सर अस्पताल की बात करें तो वहां पर हमारे पास 50 बैड हैं और

जहां पर आईपीडी होती है । डेकेयर में हमारे पास 21 बैड हैं और मैं जिम्मेवारी के साथ यह कह रहा हूं । माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो जानकारियां यहां पर दी गई हैं, जैसे यहां पर 100 और 120 के बीच में रेडियोथेरेपी होती है, यहां पर 50 और 60 के बीच में किमोथेरेपी होती है । मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि टरशरी केयर सैन्टर में लगभग 2200 और 2500 के बीच में लोग रजिस्टर्ड होते हैं । माननीय सदस्य कह रहें हैं कि कुछ पेशन्ट को ट्रान्सफर किया गया है । हमारे पास आंकडा है और हमारे पास एक माकूल व्यवस्था है, यहां पर हमारे पास प्रोफैसर्ज है, एसोसिएट प्रोफैसर्ज हैं, यहां पर एस.आरर्ज. हैं, यहां पर हमारे पास टैली कोवालट के माध्यम से उपचार होता है । हमारे पास ट्रेन्ड डाक्टरज हैं । अध्यक्ष महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब बिमारी डायग्नोसिस्ट होती है तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 स्थानों पर किमोथेरेपी हो रही है

06/02/2019/1125/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1145---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----जारी

और यहां से प्रेसक्राइब किया जाता है कि कौन सा कैन्सर है और इसके उपचार के लिए कीमोथैरेपी की या रेडियेशन्स की जरूरत है। तो यह सलाह लेने के बाद उसका उपचार किया जाता है। कीमोथैरेपी के लगभग दस हस्पताल हैं, जैसे चम्बा माननीय सदस्य के उत्तर में आया भी है। चम्बा में यह हो रहा है, बिलासपुर और हमीरपुर यह हो रही है। इसलिए दो-तीन लोगों के एक ही बिस्तरों पर होने की बात मुझे कोई जायज़ नहीं लग रही है। यह कुल्लू, मण्डी, ऊना, नाहन, रोहड़ू और सोलन में भी कीमोथैरेपी हो रही है और इसके लिए ट्रेंड डॉक्टर्ज हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई एम.बी.बी.एस. डॉक्टर आ जाए। उन डॉक्टर्ज ने इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि रोगी को कितनी कीमोथैरेपी दी जानी है। इसमें लगभग ट्रेंड नर्सेज भी हैं। ऐपैक्स सेन्टर इन्स्टीटियुट, बम्बई की गाइडेन्स में यह सारी ट्रेनिंग हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने टांडा के बारे में जानना चाहा है तो उस दिशा में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। वहां पर 30 बैड हैं और वहां रेडियोथैरेपी वगेरह का काम भी हो रहा है। वैसे इस बारे में अगला सपलीमेंट्री प्रश्न भी आ रहा है। इसलिए मैं Linear Accelerator के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब कोबाल्ट का जमाना नहीं है, अब तो Linear Accelerator का जमाना है, प्रोक्योरमेंट हो गई है और उसकी इन्स्टालेशन शुरू हो चुकी है। जो हमारा भाभा ऐटौमिक रिसर्च सेन्टर, बम्बई है, वे उसका चैक अप कर रहे हैं, हमने उसके लिए मैडिकल स्टाफ रिक्रूट कर लिया है। मैं अगले प्रश्न के उत्तर में यह कहूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं कमी है लेकिन अगर कमी होगी भी, जैसे Linear Accelerator की है, तो अप्रैल में वह शुरू हो जाएगा। जहां माननीय सदस्य ने शिफ्टिंग की बात की है कि यहां जो आंकड़ा आया है तो यहां हमारे डॉक्टर्ज इलाज करने में बिल्कुल सक्षम हैं। हां, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर चार मरीज़ बच्चों को हमने शिफ्ट किया है तो उसका उपचार यहां नहीं था। उनको myeloid leukaemia नाम की बीमारी है। इसका इलाज चण्डीगढ़ पी.जी.आई. में होता है। तो माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री राकेश पठानिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष : राकेश जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दे दिया है। अन्य माननीय सदस्यों के भी इसमें प्रश्न हैं।

श्री राकेश पठानिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। मैं अभी अस्तापल से आ रहा हूं, वहां एक बिस्तर पर दो-दो रोगी लेटे हुए हैं। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं और टांडा में कीमोथैरेपी नहीं हो रही है। पहले बायोप्सी होगी, उसके पश्चात उसका सिटी-स्केन होगा, फिर उसके पश्चात कौन सा कीमो किस रोगी को दे देना है, it all varies from patient to patient. यह सुविधा आप टांडा में नहीं दे पा रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत ही क्लीयर है। इस मैटर को जो डील कर रहा है और जैसा आपने oncology के बारे में बताया है। जब तक PET scanning नहीं कराएंगे तब तक आपको कैंसर की स्टेज का पता कैसे लगेगा? किस किस्म

की डोज़ कब कहां देनी है? I agree कि आई.जी.एम.सी. में जो डॉक्टर्ज हैं, they are very good and very competitive. इसमें कोई शक नहीं कि वहां बहुत बढ़िया डॉक्टर्ज हैं। लेकिन बहुत understaffed हैं, पेशन्ट्स का रश वहां बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग यहां पहली कीमो होने के पश्चात वापस ही नहीं आते। क्योंकि यहां रश बहुत ज्यादा है।

अध्यक्ष : राकेश जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है।

श्री राकेश पठानिया : मेरा यह बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न है कि टांडा में आप यह सुविधा कब तक देंगे ताकि हमारे मरीजों को यहां न आना पड़े।

अध्यक्ष : राकेश जी, दो ही प्रश्नों पर पूरो दिन थोड़े ही खत्म हो जाएगा। माननीय मंत्री जी वैसे तो आपने इसका सारा उत्तर दे दिया है लेकिन फिर भी यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य भी कांगड़ा से संबंध रखते हैं इसलिए वहां के बारे में ये चिन्तित रहते हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल माक़ूल हैं और हमारे डॉक्टर्ज भी सक्षम हैं। टांडा की बात मैंने अपने रैफेरेन्स में दी है कि वहां पर भी हमारे पास स्टाफ है और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कैन्सर कई प्रकार का होता है और कैन्सर का उपचार करने के लिए जो डॉक्टर्ज होते हैं, वैसे तो आप भी डॉक्टर हैं, इसलिए अब मेरा भी यह धर्म बनता है कि मैं भी अब सारी बातों को विस्तार से यहां बताऊं। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वैसे तो हमारे शरीर में जितने भी हमारे अंग हैं,

06/02/2019/1130/MS/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-------

उन तमाम अंगों में कैंसर हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 5 या 10 प्रकार का कैंसर होता है। कैंसर लगभग 80 प्रकार का होता है। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप माननीय सदस्य को उत्तर से संतुष्ट करवाइए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैं अपने उत्तर से आपको भी संतुष्ट करना चाहता हूं और कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कैंसर के ट्रीटमैंट में सर्जरी भी इन्वोल्व होती है, उसके माध्यम से भी इसका उपचार होता है और रेडियोथैरेपी/किमोथैरेपी के द्वारा भी इसका उपचार होता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर केसिज लंग कैंसर और ब्रैस्ट कैंसर के ध्यान में आ रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो बैड की संख्या के बारे में जानना चाहा है तो हमारे पास माकूल बैड हैं। एक ही बैड पर तीन-तीन मरीज़ कहां पर हो गए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु सब ठीक है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि जो आप यह कह रहे हैं कि आपका सारा सिस्टम सही ढंग से चल रहा है, यह आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों का जो उपचार हो रहा है, इसकी क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न है। आप कह रहे हैं कि एक दिन में 50-60 मरीजों को किमोथैरेपी दे रहे हैं जबकि प्राइवेट अस्पताल में एक किमोथैरेपी के लिए कम-से-कम पांच दिन मरीज़ को एडमिट करते हैं और तब जाकर उसकी किमोथैरेपी शुरु होती है। आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 अस्पतालों में किमोथैरेपी हो रही है। यह मंत्री जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यह गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री जी, आप यह बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत मरीज़ इस ट्रीटमैंट से ठीक हो रहे हैं? मेरा यह कहना है कि 99.99 परसेंट यहां पर इसका फेल्योर है और यहां अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा गन्दगी है। आपके अस्पतालों में पैट स्कैनिंग और लैब टैस्ट्स नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप बड़े-बड़े लैक्चर देने के बजाए यह बताइए कि कैंसर अस्पताल को कब क्वालिटी अस्पताल बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कैंसर से निजात दिलाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य, जब मैं उत्तर दे रहा था उस समय आपने मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुना। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उत्तर ध्यान से सुना कीजिए। प्रश्न के लिए प्रश्न करना और इस तरह सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज़

करवाना सही नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा और कहा कि विस्तार से उत्तर दे दिया है। उनके मन में जो प्रश्न थे उनका मैंने उत्तर दे दिया है। अब क्या एक ही प्रश्न के उत्तर को हम बार-बार दें? यह बात सही है कि हमारी जिम्मेवारी है, ...(व्यवधान)...

श्री अनिरूद्ध सिंहः आप प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्षः अनिरूद्ध जी, आप बैठिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य, आपने प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैं उसका उत्तर दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अनिरूद्ध सिंहः आप गलत सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्षः अनिरूद्ध जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, आप संक्षेप में उत्तर दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैं सही सूचना दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संक्षेप में उत्तर दे दिया है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मंत्री जी, उत्तर को घुमा-घुमाकर जलेबी मत बनाइए। आप सीधा उत्तर दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर दे दिया है।

अध्यक्षः अंतिम अनुपूरक प्रश्न श्री राकेश सिंघा जी पूछेंगे।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से संक्षिप्त सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सभी Oncology कैंसरस है? यह बात सही है कि कैंसर बढ़ रहा

है। इसके अलावा, हमारे डॉक्टर्ज जो पोस्ट डॉक्टरेट्स का अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें जो आपने 10 लाख रुपये की कण्डीशन लगा रखी है, क्या यह उचित है या नहीं?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, यदि प्रश्न क्लीयर है तो उत्तर दे दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न क्या किया, वह मुझे समझ नहीं आया है।

06.02.2019/1135/जेके/डीसी /1

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा हूं कि यह सारा कैंसरस है या नहीं, जो टयूमर्ज़ हैं। Oncology का जो हमारा अध्ययन है यह सारा कैंसरस है या नहीं?

दूसरे, no doubt कैंसर बढ़ रहा है। अब उस कैंसर को रोकने के लिए आपको ज्यादा डॉक्टर्ज़ भर्ती करने के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्ज़ पोस्ट डॉक्टरेट में जाने चाहिए, तो पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए ये जो इतनी बड़ी कंडिशन हम लगा देते हैं कि 10-10 लाख आपको जमा करना पड़ेगा as a guarantee, so are we encouraging them or discouraging them? मेरा आपसे यह प्रश्न है।

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सदस्य के पूछने का मतलब यह है कि जो 10 लाख की गारंटी है, वह डॉक्टर्ज को डिस्करेज करती है या इनकरेज करती है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय राकेश सिंघा जी ने जानना चाहा कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा वातावरण बनाया जाए कि ज्यादा-से-ज्यादा डॉक्टर्ज Oncology, मैडिकल ऑनोकोलॉजी में पढ़ाई करें और फिर यहां पर अपनी सेवाएं अधिक-से-अधिक दें। मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे कैंसर को छोड़ दिया जाए, दूसरे डिपार्टमैंट्स में भी बहुत से डॉक्टर्ज़ पी0जी0 या एडवांस पढ़ाई कर रहे हैं और वे अपनी सेवाएं आई0जी0एम0सी0, शिमला में, टांडा में या अन्य छः मैडिकल कॉलेजिज़ में

दे रहे हैं। मेरे तो ध्यान में यह भी है कि अच्छे डॉक्टर्ज़ एम्ज से, पी0जी0आई0 से एडवांस कोर्स या पी0जी0 वगैरह करके यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक अच्छे माहौल की बात है, हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर वर्तमान में है और जितने मरीज वहां पर आ रहे हैं, उनको वे सर्विसिज़ दे रहे हैं। जहां तक इन्होंने मनी बाँड की बात की कि उसको कुछ कम किया जाए, ये भी सरकार के विचाराधीन है परन्तु यह भी जरूरी है कि यहां इस हिमाचल प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहां का जल है, पैसा है और दूसरी चीजें हैं, उन पर हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च करती है। उसके बाद कई बार ऐसे डॉक्टर्ज़ जिनकी संख्या हमारे पास 35 के लगभग है, वे बिना जानकारी के दूसरे स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उसके लिए भी हम व्यवस्था बना रहे हैं कि जो यहां से पी0जी0 कर रहे हैं, वे अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में ही दें।

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी, अपनी बात आप आधे मिनट में कह दें क्योंकि यह प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास यहां पर टैस्ट नहीं होते हैं, जैसे लंग के अन्दर biopsy नहीं आती तो , EBUS (Endobronchial Ultrasound) of lungs है वह टैस्ट पी0जी0आई0 में जा करके करवाना पड़ता है। ये छोटे-छोटे टैस्ट हैं which are not available in Himachal Pradesh. आप पिछले एक वर्ष में कितनी बार कैंसर हॉस्पिटल में गए हैं, पहले आप मुझे यह बताएं? How many times you have visited Cancer Hospital?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप काम की बात पूछें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत बुरा हाल है और मैं अभी वहां से आया हूं। ये टैस्ट वहां पर कब तक शुरू किए जाएंगे?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप शॉर्ट में बताएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट में तो बता नहीं सकते क्योंकि यह प्रश्न ही लम्बा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कब किस अस्पताल में गया ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी क्या आप उत्तर दे रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है अपना कंसर्न शो करना है, यह आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें साफ दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कैंसर के रोगियों के प्रति, उनके इलाज के प्रति कतई भी गम्भीर नहीं है। मैं देख रहा था कि जितने भी माननीय सदस्य इस पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, उनमें से कोई ठंडे इलाके से है और कोई गर्म इलाके से है लेकिन उन सबकी तासीर एक जैसी ही है। अपना कंसर्न शो करना, आखिरकार अपने संस्थानों के प्रति यदि हम इस प्रकार से बोलते रहेंगे और जो डॉक्टर्ज़ इतनी मेहनत करने के बाद यहां पहुंचते हैं, उनके बारे में हम इस प्रकार से बातें करें तो ठीक नहीं है। व्यवस्थाओं से सम्बन्धित तो ठीक है, उनमें कमी है लेकिन

मुख्य मंत्री क्रमागतः

सुधार कैसे करना है, यह एक विषय आ सकता है। जबकि आपका विषय सिर्फ विरोध करना और गलत बात की जानकारी देना होता है। हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। प्रश्न का जवाब जितना डिटेल में दे दिया है, मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने पी0जी0 डॉक्टर्ज़ के बारे में बात कही कि 10 लाख रुपये की एफ0डी0 बनवाते हैं और बॉंड भरवाते हैं। हमारी कुछ विवशताएं भी हैं। आखिरकार आप एक डॉक्टर को तैयार करते हैं और डॉक्टर तैयार होने के बाद वह अपने प्रदेश में सेवाएं देने के लिए तैयार ही नहीं है। वह दूसरे प्रदेश में चला

जाए तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। आखिरकार उसको यहां रोकना पड़ेगा। आप यहां पर हाउस में चिल्लाते रहेंगे कि डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बन कर वह आदमी दूसरे प्रदेश में जा रहा है या प्राइवेट सैक्टर में नौकरी कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए आवश्यक है कि उसको यहां किसी तरह रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्ज़ ऐसे हैं जो पी0जी0 करने के लिए स्टडी लोन लेते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण नरम रहना चाहिए। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि पिछले कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक की जानकारी हाउस में दी जा सकती है, हमने इसके बारे में कल निर्णय किया है। जो 10 लाख रुपये की एफ0डी0 का विषय था, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा करने के बाद हमने उसको आधा करके 5 लाख रुपये किया है। उसके अलावा जो बॉंड वाला इश्यु है उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्हें सरल करने की कोशिश की है ताकि डॉक्टर्ज़ हिमाचल प्रदेश में रहें, बाहर न जाएं। ऐसा साइक्लोजिकल इम्पैक्ट हमको अपनी नीतियों के माध्यम से देना पड़ेगा। उस दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूं। जहां तक डॉक्टर्ज़ की कमी की बात है, हम इस बात से सहमत हैं। डॉक्टर एक महीने या दो महीने में नहीं बनता, बल्कि वह निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बनता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में पूरी तरह से गम्भीर है। पिछले अरसे से कैंसर के मामले पूरे देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लगभग ऐसी मान्यता है कि अगर यह बीमारी एक बार हो जाए तो उसके बाद इसके पूर्ण रूप से ठीक होने की सम्भावनाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन ट्रीटमैंट में व्यवस्था निकली है, गुंजाइश निकली है कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की आयु को लम्बा कर सकते हैं। उसके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। ऐसा करने में रिसर्च काफी हद तक सफल हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यह जानलेवा बीमारी है। ऐसी परिस्थिति में सभी माननीय सदस्यों का जो विषय यहां पर आया है, उस कंसर्न में हम भी शामिल हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी-से-जल्दी चाहे वह पैट-स्कैन की बात है, चाहे वह कीमोथरैपी की बात है, चाहे वह रोडियोथरैपी की बात है, तमाम सुविधाएं ज्यादा-से-ज्यादा जगह हो सकें, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे और उसके साथ-साथ बेहतरीन इलाज देने की हमारी कोशिश होगी।

प्रश्न संख्याः 1146

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति उप-योजना के अधीन जो धनराशि आबंटित होती है क्या विभाग कोई ऐसी नोडल एजैंसी बनाने का विचार रखता है जो समय-समय पर चैक कर सके कि आबंटित धनराशि सही जगह लग रही है या कहीं उसको डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है या क्या वह निश्चित समय में लग रही है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के आर्टिकल-46 से तारतम्य रखते हुए और उसकी भावना से सहमत होते हुए 1979-80 में पहली बार स्पेशल कम्पोनैंट प्लान, जिसे वर्तमान में 'शिडयूल्ड कास्ट कम्पोनैंट प्लान' के नाम से जाना जाता है, उसकी क्रियेशन हुई थी। 1979-80 में पहली बार 4.61 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुसूचित जाति बहुल गांव, जहां पर विकास की बहुत आवश्यकता है, उन गांवों के विकास हेतु इस राशि का प्रावधान हुआ था।

6.2.2019/1145/केएस/एजी/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी----

बाद में उत्तरोतर इस राशि में वृद्धि होती गई लेकिन वर्ष 2007 में पहली बार बजट में एक अलग मद के रूप में कम्पोनेंट- 32 एक स्वतंत्र मद क्रिएट की गई जिसके पीछे माननीय सदस्य की प्रश्न पूछने की जो मंशा है, यह पैसा सिर्फ अनुसूचित जाति बाहुल गांवों में और जो प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, उनके कल्याण के कार्यों हेतु यह पैसा खर्च हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग मद के रूप में हमारे बजट में इसकी क्रिएशन हुई थी। माननीय सदस्य ने सुझाव भी दिया है और आश्वासन भी चाहा है कि हम प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी नोडल एजैंसी या कोई मोनिटरिंग सिस्टम डिवाइस कर सकते हैं जो यह सुनिश्चित करें कि जितने भी काम इस योजना के तहत चले हैं, उनका निष्पादन ठीक प्रकार से हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय

सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सम्माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात और सम्माननीय मुख्य मंत्री जी अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए विशेषतौर पर गम्भीर हैं । उनके अनुमोदन के पश्चात हम प्रयास करेंगे कि एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन हो जो समय-समय पर इस योजना के तहत चलने वाले कामों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि बजट में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति बाहुल गांव के लिए, लोगों के लिए जो पैसे का प्रावधान होता है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो।

श्री नन्द लाल (रामपुर)ः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें "क" भाग में इन्होंने लिखा है कि "विभागाध्यक्षों द्वारा बजट आबंटन अनुसार व्यय करने का प्रयास रहता है।" पहली बात तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट आबंटन अनुसार व्यय करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये यह कन्फर्म क्यों नहीं करते कि जो बजट अलॉटिड है, वह खर्च हो गया है? फिर इन्होंने कहा है कि किन्हीं कारणवश अगर नहीं हो पाया तो वह कारण भी हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्कीम पर किस कारण से वह बजट ये खर्च नहीं कर पाते?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, प्रयास किया जाता है, मुझे भी लगता है कि यह शब्द थोड़ा गलत लिखा गया है। प्रयास ही नहीं किया जाता अपितु यह बजट किसी भी योजना के अगेंस्ट उसको एलोकेट किया जाता है और काम हो, विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है। कुछ कार्य जो नहीं हो पाए उसके कारणों से भी माननीय सदस्य ने अवगत होना चाहा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम विचार करें तो अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत हमारी सिंचाई योजनाएं बनती हैं, सड़के बनती हैं, विद्यालयों के भवन बनते हैं और उसमें अगर कोई टैक्निकल खामियां हैं, मान लो जैसे कोई सड़क बननी है उसके लिए अगर भूमि उपलब्ध न हो या लोग गिफ्ट डीड न करवाएं, पैसा चला जाता है लेकिन उसकी औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण कई बार कार्य नहीं हो पाता और मैं समझता हूं कि उसके पीछे यह कारण है।

श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो शैड्यूल कास्ट कम्पोनेंट प्लान की आप रूप-रेखा बनाते हैं, यह साल में कब बनाते हैं और क्या विधायकों को भी जो कार्य हमने आपको इस प्लान में देने हैं, क्या हमें भी आप इसमें सम्मिलित करते हैं? अगर नहीं करते तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर विधायकों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं और प्रत्येक वर्ष विधायकगणों से प्राथमिकताएं मांगी जाती है। दो योजनाएं उसमें प्रति निर्वाचन क्षेत्र मांगी जाती है। ...(व्यवधान)...

14.2.2019/1150/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 1146 ---------- क्रमागत

---(व्यवधान)--- डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक मोनिटरिंग एण्ड रिव्यू कमेटी बनी है। उस कमेटी के अध्यक्ष जिला के मंत्री होते हैं और बाकी सभी विधायकगण उसके सदस्य होते हैं। ---(व्यवधान)--- इसकी क्वार्टरली मीटिंग होती है जो कि आवश्यक है और उसी के माध्यम से सारी योजनाएं आती हैं।

14.2.2019/1150/av/yk/2

प्रश्न संख्या : 1147

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चम्बा के एक सीमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसका दो बार टैंडर कर दिया है। एक टैंडर दिनांक 21.8.2018 को और दूसरा दिनांक 1.12.2018 को किया गया मगर दोनों ही बार कोई नहीं आया। इसलिए अब इन्होंने डेट बढ़ा दी है और तीसरी बार टैंडर नहीं किया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने टैंडर ही नहीं किया था तो आप पिछले 6 महीनों से सार्वजनिक मंचों से यह अनाऊंसमैंट कैसे करते रहें कि इसका अक्तूबर माह में

शिलान्यास हो रहा है। यह मसला जब इतना अहम है कि टैंडर में कोई आ नहीं रहा है और टैंडर फाइनेलाईज नहीं हुआ है तो आप पर कौन सा दबाव है कि आपने इसका अक्तूबर महीने में शिलान्यास करने बारे बारम्बार एलान किया। आप जब बोलते हैं तो मंत्री के बोलने की कोई वैल्यू होती है। जब टैंडर ही फाइनेलाईज नहीं कर पाये तो अब आप शिलान्यास कैसे करेंगे? मुझे मालूम है कि आपकी थोड़ी-बहुत मजबूरी है क्योंकि आपके सांसद ने आपके गले में अंगूठा दिया हुआ है और कह रहे हैं कि पत्थर ऐसे ही रखवा दो। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जब सिकरीधार चुनाव आता है तो उससे पहले यह करना ही करना है और मेरे हिसाब से यह माननीय उपाध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। आप अनावश्यक दबाव में आकर ऐसी अनाऊंसमैंट कैसे करते हैं? सीमेंट के कारखाने से प्रदेश को फायदा पहुंचना चाहिए मगर आपने कहा कि आप उनको सड़क बनाकर देंगे। यह बात कहां से उठी कि सीमेंट कारखाने जो कि काफी मुनाफा कमाने वाले होते हैं उनको आप 25-26 किलोमीटर सड़क बनाकर दें?

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक पिछली सरकार में उद्योग मंत्री थे और यह प्रक्रिया बड़े लम्बे समय से चल रही है। उस समय इन्होंने भी इसमें बहुत इन्ट्रस्ट दिखाया था और कोशिश की थी कि वह सिरे चढ़े। इन्होंने जो पहला प्रश्न किया कि यह बार-बार बोला जा रहा था कि इसका अक्तूबर माह में शिलान्यास हो जायेगा तो इस बात की हमें सम्भावना थी क्योंकि हमने इसका टैंडर लगाया हुआ था। यह सम्भावना होती है कि जब किसी प्रोजैक्ट का टैंडर लगता है तो कोई-न-कोई आयेगा और हम इसका शिलान्यास करेंगे। यह कोई पोलिटिकल विषय नहीं है जैसे आप कह रहें हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव है। दूसरा प्रश्न आपने सड़क बनाने के बारे में किया कि हमें उनको सड़क बनाकर नहीं देनी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने जब इसका पहली बार टैंडर किया तो कोई नहीं आया। हमने फिर विचार किया कि सीमेंट की कम्पनियों को बुलाया जाए और उनसे इसके बारे में बातचीत की जाए। इसलिए दिनांक 30.10.2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें

ए0सी0सी0,रिलायन्स और अल्ट्राटैक सीमेंट कम्पनियां आईं। उनसे इस बारे में बातचीत हुई, उन्हें कहा गया कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सीमेंट प्लांट है। आप कृपा करके इसमें आइए और अपना इन्ट्रस्ट शो कीजिए तो

06/02/2019/1155/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

उन्होने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन्ज़ दी, जिसमें यह भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर वहां पर सरकार हमें सड़क देती है तो हम वहां पर इसके लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमने अपने टेंडर दस्तावेज़ में इसको अमेंड किया है। हमने इसमें कहा कि वहां पर यह एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट लगना है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत राजस्व प्राप्त होगा। इसमें कोई भी पॉलिटिकल मंशा नहीं है। हमने तो इसका कार्य शीघ्र करने के उद्देश्य से शिलान्यास करने का विचार किया। हम बिल्कुल साफ-सुथरी बात कर रहे हैं। हमने एक बार टेंडर लगाने की कोशिश की और उसके बाद दूसरी बार इसको लगाने के लिए एक्सटेंड किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका शीघ्रातिशीघ्र कोई-न-कोई हल निकलेगा। आप इसे पॉलिटिसाइज न लें।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उनकी कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं थी। लेकिन यदि पॉलिटिकल मंशा नहीं थी तो आप ऐसा जवाब भी न देते। आपकी सिर्फ पॉलिटिकल मंशा थी और कुछ भी नहीं था। ये इलाका मेरी और माननीय उपाध्यक्ष जी के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इन्होंने प्रश्न के 'ग' भाग में कहा है कि खन्न पट्टा क्षेत्र तक की सड़कों की आधारिक संरचना उपलब्ध करने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकरीधार बिल्कुल मांउटेन के टॉप पर है और जैसा श्री मुकेश जी ने कहा कि ये 25-26 किलोमीटर सड़क बननी है। क्या आपने इसका कोई सर्वे करवाया है या कोई डी0पी0आर0 बनाई है? आपका एक सरकारी बयान आया था कि आपने इस कार्य के लिए 15 करोड़

रुपये रख दिए हैं। लेकिन 15 करोड़ रुपये में तो उसकी ट्रेस कटिंग भी नहीं होगी। वह 25 किलोमीटर की सड़क है और अधिकतर बैकवर्ड एरिया है। इन्होंने जो सीकरीधार के टेंडर की बात रखी है, इसके टेंडर को कोई भी नहीं लेगा। ये हो ही नहीं सकता है। It is not possible. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीकरीधार ऊपर है, उसके नीचे पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है और उसके नीचे पूरी प्राइवेट ज़मीन है। आपने न तो उसकी डिमार्केशन की है, जोकि उसकी पहली शर्त है और न ही लोगों को पता है कि यह सड़क कहां से बननी है। जो सड़क बननी है, वह पूरी प्राइवेट लैंड से बननी है और आप इस तरह की बयानबाजी करके क्यों चम्बा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप यह बताईये कि क्या आपने सड़क का सर्वे किया है, क्या यह सड़क 70-80 प्रतिशत् प्राइवेट लैंड से नहीं जानी है? आपने यह अंदाजा लगाया है कि एक्चुअली सड़क बनाने में कितनी धनराशि लगेगी?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने काफी ज्यादा प्रश्न एक ही बार में कर दिए हैं। सड़क के कार्य को सिरे तक पहुंचाने के लिए यदि सरकार गम्भीर है और अगर हम चाहते हैं कि वहां पर प्लांट लगे तो उसके लिए जितनी भी सड़क बननी है, जितना भी पैसा लगेगा, वह आदरणीय ठाकुर श्री जय राम जी की सरकार लगाएगी। उसमें आपको क्या परेशानी है? ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी को पहले उत्तर देने दीजिए।

उद्योग मंत्रीः आपने प्रश्न किया है तो अब उत्तर सुनिए। हमारी ये मंशा है और इस विषय के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बात हुई है। इन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वहां पर सड़क हिमाचल प्रदेश सरकार बनाएगी। हमने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जहां तक आप कह रहे है कि क्या भूमि अधिग्रहण कर दिया गया है? हम अभी तक इस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यह हमारी मंशा है कि वहां पर सड़क बने। आप कह रहे हैं कि वहां 15

करोड़ रुपये से सड़क नहीं बनेगी। वहां पर सड़क बनाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा, वह सरकार देगी और वहां पर सड़क बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सड़क की बात की है और उत्तर में यह भी कहा कि इससे राज्य को बहुत राजस्व आता है। हिमाचल प्रदेश में जे0पी0, अम्बुजा और ए0सी0सी0 इंडस्ट्रीज़ के तीन सीमेंट प्लांट लगे हैं। लेकिन बड़ी विडामना है कि सड़क बनाने के लिए सरकार सर्वे करवाएगी, पैसा उपलब्ध करवाएगी, सड़क बनाकर देगी और जो हिमाचल प्रदेश की जनता को सीमेंट का रेट है, वह और राज्यों से महंगा है। वह 370 रुपये प्रति बोरी है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या आप इन निविदाओं में ये शर्त लगाएंगे क्योंकि हिमाचल में जो माइनिंग लगती है, उससे हिमाचल प्रदेश के

06-02-2019/1200 /NS/AG /1

लोगों का स्वास्थ्य सीमेंट प्लांट से खराब होता है। तकरीबन जहां भी सीमेंट प्लांट लगे हैं, टी0बी0 के सबसे ज्यादा रोगी वहां आए।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य जल्दी से अपना प्रश्न पूछें। समय हो रहा है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : टी0बी0 के सबसे ज्यादा रोगी उन जगहों पर पाए गए हैं और हमारे लोगों को ट्रक ड्राईवर और छोटा-मोटा काम मिलता है। माइनिंग हमारी और लीज़ मनी कितनी मिलती है, क्या ऐसी शर्त लगेगी कि सीमेंट प्लांट से हिमाचल प्रदेश को सस्ता सीमेंट मिलेगा?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य समय खत्म हो जाएगा, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : दिल्ली में 200 रुपये, पंजाब में 280 रुपये सीमेंट पड़ता है और यहां पर 370 रुपये पड़ता है। क्या आप सीमेंट प्लांट में यह शर्त लगवाएंगे?

उद्योग मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन अभी तक प्लांट लगा नहीं है। इस प्लांट को लगाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है

और अभी तक यह विषय यहां पर आया नहीं है। लेकिन आप सभी माननीय सदस्यों के सुझाव बहुत बढ़िया हैं। ---(व्यवधान)--- इन्होंने जिस विषय पर बोला है, शायद इसमें ये कंडीशन्ज़ लगाई हों। इन्होंने जो बोला है, वह बिल्कुल ठीक बोला है और ये कंडीशन्ज़ होनी चाहिए। जहां तक सीमेंट के रेट की बात है तो यह अलग बात है जो इस विषय के साथ जुड़ा नहीं है।

अध्यक्षः श्रीमती आशा कुमारी जी, आप अपनी बात थोड़ा शोर्ट में कहें क्योंकि समय हो रहा है।

श्रीमती आशा कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने या तो जवाब में गलत बोला है या अभी गलत बोल रहे हैं। इन्होंने जवाब में कहा है कि शर्त लगाई है कि सफलतम बोली के बाद सड़क बनाएंगे और अभी आप इस माननीय सदन में यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। दोनों में से कौन-सी बात सही है?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है इन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। कोई प्लांट लगाने आएगा तभी सड़क बनेगी। जब प्लांट लगाने ही कोई नहीं आएगा तो सड़क कैसे बन जाएगी? हमने यह कंडीशन लगाई है ---(व्यवधान)--- आप एक मिनट सुन लीजिए। ---(व्यवधान)--- वह एक अलग विषय है। हमने यह कहा है कि उनको यह सुविधा हम दे देंगे लेकिन वहां पर कोई प्लांट लगाने आए तो सही। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मित्रों के प्रश्नों से सचमुच में बहुत हैरान हूं और हैरान होने के साथ परेशान भी हो रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं। ---(व्यवधान)--- हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला क्यों? क्या हमें आप सब लोगों से पूछ कर ही बोलना चाहिए कि हमने सीमेंट का प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है? ---(व्यवधान)--- क्या आप हमारे बोलने पर भी पाबंदी लगाना चाह रहे हो? ---(व्यवधान)--- मुख्यमंत्री और मंत्री कुछ बोलें तो कहते हैं बोला क्यों? ---(व्यवधान)--- आपने क्यों बोला? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ---(व्यवधान)--- आप मेरी बात सुन लीजिए। ---(व्यवधान)--- आपने पहली बात जो कही है कि आपने बोला क्यों? ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आप सुन तो लो।

मुख्यमंत्रीः ---(व्यवधान)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कदर यह बेचैनी क्यों है? आखिरकार प्रदेश का विकास हम सबका लक्ष्य है। प्रदेश में इंडस्ट्री आए और जब हमारे पास वहां पर मिनरल्ज़ हैं तथा वहां पर सीमैंट बनाने के लिए चूने का पत्थर माकुल मात्रा में विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति में हमारी मंशा वहां पर सीमेंट का कारखाना लगाने की है तो हमने क्या गुनाह कर लिया? दूसरी बात, जो माननीय सदस्या आशा कुमारी जी कह रही हैं कि सड़क कैसे बनेगी? मैं बताना चाहूंगा कि सड़कें कहां से कहां पहुंच गई हैं। ---(व्यवधान)--- हमें अभी सरकार में आए हुए एक साल ही हुआ है। ---(व्यवधान)--- कहां पहुंचेंगे, सीकरीधार ऊपर है। ---(व्यवधान)--- मैंने आपकी पूरी बात सुन भी ली। ---(व्यवधान)--- बीच में जंगल है और नीचे लोगों की ज़मीन है। सड़क तो ज़मीन से हो करके ही बनेगी, चाहे वहां पर प्राईवेट लैंड है, चाहे वहां पर सरकारी ज़मीन है, आपकी सरकार में भी बनी हैं और हमारी सरकार में भी बनेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी मंशा है। यह चंबा का एक भावुक मुद्दा है कि उस क्षेत्र में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए कारखाने की आवश्यकता है और सीमेंट एकमात्र कारखाना उस क्षेत्र के लिए ऐसा दिखता है जो रोज़गार के लिए बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है तथा प्रदेश के विकास के लिए भी योगदान दे सकता है। ---(व्यवधान)---

06.02.2019/1205/RKS/AG-1

...(व्यवधान)... माननीय मुकेश जी आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप पहले तय कर लो कि पहले किसने बोलना है। ...(व्यवधान)... यह बड़ा मुश्किल काम है। ...(व्यवधान)... बाहर भी लोग देख रहे हैं और अंदर भी देख रहे हैं। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

मुख्य मंत्रीः क्या आपको चम्बा का विकास नहीं चाहिए? ...(व्यवधान)... हर विकास के रास्ते पर बाधा और यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के बीच में नोकझोंक हुई।)

अध्यक्षः कृपया बैठिए। माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी बैठिए।

प्रश्नकाल समाप्त

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति,(वर्ष 2018-19),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर
   सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और
2. समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत

कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

Education Minister: Hon'ble Speaker, Sir, on 4th February, 2019 the Hon'ble Leader of the Opposition raised a point regarding laying of the foundation stone in Government College, Lilah Kothi. I want to make a statement and clarify the position.

Hon'ble Speaker, Sir, the New Modal Degree College was initially approved by MHRD, Government of India during the 3rd Project Approval Board Meeting held on 13th May, 2014 for Chhatrari, District Chamba, H.P. under RUSA. Thereafter, the then local Hon'ble MLA Shri T.S. Bharmouri requested to change the location of NMDC from Chhatrari to Lilah Kothi vide his UO note dated 18.06.2014. Accordingly, the Administrative Department, Government of Himachal Pradesh approved the change of location of NMDC to Lilah Kothi. Thereafter, the proposal of changing the location was sent to MHRD, Government of India for its approval. In 5th PAB meeting dated 10th December, 2014, the shifting of location was approved. The previous Government has laid the foundation stone of NMDC, Lilah Kothi on 1st August, 2016 without any land in the name of this college. The MHRD, Government of India in 12th PAB meeting dated 25th May, 2018 cancelled its approval granted previously

Hon'ble Education Minister continued in english….

in respect of many institutions due to the reason that the Institutions /States did not fulfil certain conditions and so one of the institutions cancelled was this NMDC (cancelled due to late submission of DPR by the State i.e. after exhaustion of the limit and condition for funds release were land transfer and DPR submission). There was no land and neither there was DPR which was submitted to the Government of India so it was cancelled.

Then in the second phase of RUSA, in the 12th PAB meeting dated on 25th of May, 2018, Component 5- the MHRD, Government of India approved this NMDC and Rs. 12.00 crores only was approved for this college. Land has been transferred in the name of New Model Degree College Lilah Kothi on 27th of August, 2018. The MHRD, Government of India has sanctioned Rs.5.40 crores for this college vide its sanction letter dated 21st January, 2019 as Centre -State share (90:10 percent share). After transfer of land in the name of the NMDC Lilah Kothi, the Hon'ble Prime Minister of India has laid foundation stone digitally via video conferencing on 3rd February, 2019. This is for the approved New Model Degree College at Lilah Kothi. Earlier it was sanctioned for Chhatrari, where the foundation stone was laid. But that stone is not existing there and when that foundation stone was laid in 2017 there was no land and no money. So along with other colleges throughout India, even the foundation stone of this College was laid by Hon'ble Prime Minister digitally. Thank you.

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी सफाई दे रहे हैं यह आफटर थॉट है। आपने देश के प्रधान मंत्री जी से एक कलत कार्य करवा दिया है और वह भी कोई बड़ा कार्य नहीं करवाया है केवल 5.40 करोड़ के पीछे यह कार्य किया है। यदि कोई कार्य 5 सौ करोड़ या हजार करोड़ रुपये का कार्य करवाते तो समझ आता कि यह देश की प्रधान मंत्री जी से बहुत बड़े संस्थान का कार्य करवाया है। एक कॉलेज जिसे सिर्फ तकनीकी आधार पर बताया जा रहा है कि लीलह कोठी से चतराड़ी के लिए बदला गया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणी वीरभद्र सिंह जी और मंत्री जी ने नींव का पत्थर रखा था। अब कहा जा रहा है कि वह पत्थर मौके पर नहीं है इसलिए दोबारा से शिलान्यास करवाया गाय है। मैं कहता हूं कि यह परंपराएं बंद होनी चाहिए। अगर एक शिलान्यास अगर किसी ने किया था, सरकार को इतना सम्मान करना चाहिए था कि उसे न हटाते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो पत्थर हटा दिए गए हैं या कहीं तोड़ दिए गए हैं उन्हें उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी था। परंतु उसके बावजूद भी वह पत्थर नहीं लगाए गए है। अभी भी यह कार्य किया जा रहा है। आप प्रधान मंत्री जी से एक छोटे से संस्थान का शिलान्यास करवा रहे हैं यह कार्य आपको शोभा नहीं देता न आपके विभाग को ही शोभा देता है। माननीय मुख्य मंत्री जी का स्तर प्रदेश में कम नहीं है। अगर उन्होंने एक पत्थर रख दिया था तो उसको उठा करके लील कोठी पर लगाया जा सकता था। पैसा तो उतना ही है यह पैसा रूसा का है। यह भी नहीं है कि आपने उस कार्य के लिए कोई विशेष पैसे का प्रावधान किया है। आपने एक चरण में नहीं तो दूसरे चरण में दे दिया। यह परंपरा सही नहीं है । इस पर आप जितनी मर्जी सफाई दो परंतु यह आफटर थॉट कार्य है।

06.02.2019/1215/DT/ DC -1

श्री जिया लाल (भरमौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,जो यहा पर कॉलेज़ का मुद्दा आया है यह मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो बात कर रहे है कि वर्ष 2016 में पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किया है।

वर्ष 2016 में माननीय मुख्य मंत्री जी भरमौर गए ही नहीं थे। जो ये शिलान्यास की बात कर रहे हैं उस दिन आदरणीय भरमौरी जी भी भरमौर में ही थे और कम से कम 40 शिलान्यास और नाम की प्लेटें एक दिवार पर लगाई गई थीं और ओनलाइन उसका शिलान्यास किया गया था । यह जो डीग्री कॉलेज की बात कर रहे है यह उसका शिलान्यास था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मोडल डीग्री कॉलेज है यह वर्ष 2014 में स्वीकृत हुआ था जब केन्द्र में भारतीय जन्ता पार्टी की सरकार थी । माननीय सदस्य श्री अग्निहोत्री जी कहा रहे थे कि यह वह कॉलेज नहीं है । इसके पूर्ण दस्तावेज हमारे पास हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया ही नहीं था।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्लैरिफिकेशन माननीय विपक्ष के नेता ने चाही थी वह मैंने दी थी। लेकिन इन्होने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले प्रश्न काल में इन्होने कहा कि सीमेंट प्लांट के लिए कोई आया ही नहीं तो कैसे वहां पर नींव का पत्थर रखा गया। जब कॉलेज लील कोठी आपको मिला ही नहीं किसी ने एप्रूव ही नहीं किया तो आप वहां पर नींव का पत्थर कैसे रख रहे थे? उस वक्त मोडल कॉलेज रूसा के तहत छतराड़ी के लिए एप्रूव हुआ था । वर्ष 2016 में यहां पर अनेको प्लेट्स लगा दी गई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका शिलान्यास घोषित कर दिया। उसके बाद वहां पर जमीन नहीं थी पैसा नहीं था उसके बाद वह कैंसिल हो गया। यह दोबारा से स्वीकृत हुआ है। जिसके लिए 12 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। साथ में वहां एसपीरेशन जिला चम्बा के लिए मॉडल कालेज प्रदान किया गया। सारे देश भर में 150 स्थानों पर इस प्रकार के कॉलेजिज रूसा -2 के लिए दिए गए हैं। उसमें से एक कॉलेज चम्बा के लिए भी है। ये सभी कॉलेजिज डिजीट्ल हैं इसलिए इसका शिलान्यास डिजीटली रूप से जम्मू से किया है। इस कार्य की विपक्ष को आपत्ति है। यह बिंदु आपने रखा था मैंने इसे क्लैरिफाई किया है। उस दिन हमारे पास रिर्काड उपलब्ध नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इस कार्य के लिए इस तरह के इश्यू बनाने की जरूरत है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : कृपया, अब हो गया। क्लैरिफिकेशन हो गयी , सब हो गया।

शिक्षा मंत्री : उस वक्त कांग्रेस सरकार ने सब गलत किया है। ...(व्यवधान)... माननीयों को शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए । ...(व्यवधान)... हमने इनकी गलती बता दी इसलिए वो पाप हो गया । ये पाप के शब्द हैं क्या ये संसदीय शब्द हैं ? क्या ये इस प्रकार के संसदीय शब्द उपयोग करेंगे ? ये संसदीय कार्यमन्त्री भी रहे हैं और इस समय विपक्ष के नेता हैं ।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप गलत कह रहे हैं कि एक कालेज का शिलान्यास हुआ और आप 5 करोड रूपये के लिए माननीय प्रधानमन्त्री ...(व्यवधान)...

मुख्यमन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत विचित्र लग रहा है । हम यहां पर बहुत सारी चिजों का जिक्र करना नहीं चाहते हैं । क्योंकि जिक्र करेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी । अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण दिया और कल आपने ही यहां पर एक परिस्थिति खडी की कि यह क्यों हो गया ? क्यों हो गया तो माननीय मन्त्री जी ने इसके बारे में जानकारी दी । इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर उस समय ना जमीन थी, न ही वो संस्थान सैन्कशन्ड था और न ही कोई व्यवस्था थी परन्तु उसके बावजूद भी हो गया । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री जी इस देश के प्रधानमन्त्री जी हैं और विपक्ष के लोग जितना सम्मान उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं उससे कहं ज्यादा सम्मान माननीय प्रधानमन्त्री जी के लिए हमारे दिल में है । पूरे देश भर में कुल 150 संस्थानों का डिजीटल माध्यम से शिलान्यास माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा किया गया और यह आपके समय में भी होता रहा है व आज भी पूरे देश भर में हो रहा है । माननीय प्रधानमन्त्री जी ने 150 संस्थानों का शिलान्यास किया लेकिन तब किया जब वहां पर सारी व्यवस्थाऐं तैयार कर ली गई । अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में तो एक दिन ऐसी परिस्थिती हो गई कि कैबिनेट मिटिंग में सैक्रेटरी हैल्थ एक ऐजन्डा आईटम के साथ आते हैं और कहा कि एक पीएचसी है इसको रदद करना है । हम इस बात को लेकर हैरान हो गए कि यदि पी.एच.सी. का नोटिफिकेशन हो गया तो उसे रदद करने का क्या औचित्य है । तो उन्होने कहा कि पूर्व सरकार ने जाते-जाते एक नोटिफिकेशन

की गई और हम इसे ढूंढ रहे हैं कि यह जगह कहां पर है और पूरे मालूम पडा की पूरे हिमाचल प्रदेश में यह जगह कहीं पर है ही नहीं । फिर हमें नोटिफिकेशन रदद करनी पडी । पूर्व सरकार का यह तो आलम रहा है । तभी मैने कहा कि बात दूर तलक जाएगी इसलिए इन बातों को छोड दीजिए ।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपने एम्स का शिलान्यास कब करवाया, 3.10.2017 को करवाया और अगले दिन इलैक्शन एनाउन्स होने वाले थे । आपने ट्रीपल आई टी का फाउन्डेशन कब करवाया, 3.10.2017. को । 4 और 5 को कोड ऑफ कण्डक्ट लग रहा था ।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष : आप सभी प्लीज बैठ जाईए क्योंकि अगली चर्चा शुरू कर रहे हैं हम । मुकेश आपका हो गया है आप बैठ जाईए । मैं अगला विषय शुरू कर रहा हूं ।

...(**व्यवधान**)...

विनोद जी आप बैठ जाईए । ...(व्यवधान)... अरे विनोद जी क्या आप बैठ नहीं सकते ? ...(व्यवधान)... विक्रम जी आप एक मिनट शान्ति रखें ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आगे चर्चा होगी । अब माननीय श्री सुखराम चौधरी जी इस चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री सुखराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने 4 फरवरी, 2019 को इस माननीय सदन में अभिभाषण प्रस्तुत किया था, मैं उसके पक्ष में

बालने के लिए खडा हुआ हूं । हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आज से लगभग 1 साल 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और

06/02/2019/1225/RG/HK/1

आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में बहुत बड़े काम किए हैं। हमारे मित्र साथी जो यहां बैठे हैं, आज से लगभग दस महीने पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो उसके बारे में बहुत लम्बी-लम्बी बातें यहां करते रहे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, यहां कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कुछ छोटी-छोटी बातें इनके सामने रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की सरकार आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार, प्रदेश के आम-आदमी और गरीब की सरकार है। जो ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा इनको बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको यहां सामाजिक सुरक्षा पेन्शन मिलनी चाहिए। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के अन्तर्गत विधवा, वृद्धावस्था आदि पेन्शन 2,09,292 लोगों को मिलती थी और जब इनकी सरकार प्रदेश से गई, तब 4,13,997 लोगों को पेन्शन मिली। पांच वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1,21,076 लोगों को पेन्शन दी और आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक वर्ष में 1,02000 लोगों को पेन्शन दी है। इस प्रकार से पांच साल में 1,21000 लोगों को और एक वर्ष में 1,02000 लोगों को पेन्शन मिली है। जो बुजुर्ग थे, पहले उनके लिए यह अमाउन्ट 650/-रुपये था और अब उनकी पेन्शन का अमाउन्ट लगभग दोगुना होकर 1300/-रुपये कर दिया गया है और उम्र भी 80 से 70 वर्ष कर दी है। इसलिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के आम-आदमी की सरकार है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय में यह निर्णय हुआ। हमें इस सदन में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' शुरू करने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे घर में गैस आएगी, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' में 86,000

लोगों को गैस कनेक्शन मिले और 26 मई, 2018 को हमारी सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना' में एक निर्णय लिया क्योंकि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' में उन लोगों को गैस कनेक्शन मिलते थे जो आई.आर.डी.पी. परिवार के थे, एस.सी. समाज के लोग थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश में जिस व्यक्ति के पास गैस नहीं है, उसको गैस कनैक्शन देंगे और इसमें आय का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। मई, 2018 तक जिसके राशन कार्ड पर गैस का कनेक्शन अंकित नहीं है, उसको हमने गैस देने का निर्णय लिया और आज हमें यह बताते हर्ष हो रहा है कि उसके अन्तर्गत 26 मई, 2018 से आज तक प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 48,962 लोगों को गैस के कनैक्शन वितरित किए गए हैं। प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिनके पास गैस नहीं है, हम आने वाले एक वर्ष में 1,33,637 लोगों को गैस का वितरण करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं सस्ते राशन की बात करता हूं। इनके समय में डिपुओं की क्या हालत थी? मैं इस मंच पर कहना चाहता हूं कि इनके समय में दाल मिल जाती थी, चीनी नहीं आती थी, अगर चीनी मिलती थी तो तेल नहीं मिलता था और होता यह था कि डिपुओं में तीन-तीन महीने राशन नहीं मिलता था। ---(व्यवधान)---यह सफेद झूठ नहीं, सच्चाई है। चाहे तो आप उस समय का रिकॉर्ड देख लो कि उस समय सरकार की क्या व्यवस्था थी? इतनी बुरी हालत थी। कभी चीनी मिल गई तो तेल नहीं, तेल मिल गया तो आटा नहीं और जो मिल गया,

06/02/2019/1230/MS/YK/1

उसमें कंकड़-पत्थर मिलते थे। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दाल और चीनी जब से देनी शुरु की है, तब से इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। आज लोगों को डिपुओं से सारा सामान एक-साथ मिल रहा है और इसमें 89.18 करोड़ रुपये की बचत भी की है। हिमाचल प्रदेश की यह वर्तमान सरकार पारदर्शी सरकार

है। पहले गैस का चूल्हा 1500/-रुपये में मिलता था और आज 808/-रुपये में मिलता है। उसमें भी 692/-रुपये की बचत की है और कुल-मिलाकर 3 करोड़ रुपये की बचत की है। आपकी सरकार के समय में बसों की खरीद पर क्या हुआ? आपने इलैक्ट्रिक बसें खरीदीं और एक बस 1 करोड़ 90 लाख रुपये की परचेज की। उन बसों के रख-रखाव के लिए आपने 5 साल का एग्रीमैंट किया कि हम 36 लाख रुपया 5 साल में रख-रखाव के लिए देंगे जबकि हमारी सरकार ने बसों को खरीदने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित कीं। आपने एक बस 1 करोड़ 90 लाख रुपये में परचेज की थी और 36 लाख रुपया रख-रखाव के लिए 5 साल में देने का एग्रीमैंट किया था और वह एग्रीमैंट भी वर्कशॉप में जाकर किया। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने वही बस 76 लाख रुपये में खरीदी और उस खरीद में एक बस में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्क निकला। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि हम 36 लाख रुपया रख-रखाव का नहीं देंगे बल्कि जिस कम्पनी को ठेका दिया उसको कहा गया कि आप हिमाचल प्रदेश में वर्कशॉप खोलेंगे और हमारे लोगों को ट्रेंड करेंगे और जिस बस की जितनी मैंटीनैंस होगी, हम उतना पैसा देंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार घपलेबाजी की सरकार थी। आपकी सरकार के समय में कोई पूछने वाला नहीं होता था।

अब मैं शिक्षा की बात पर आता हूं कि आपने सरकार के अंतिम समय में कितने स्कूल/कॉलेज खोले और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की बात भी करता हूं। आपने इतने स्कूल खोल दिए कि कई स्कूलों में अध्यापक तक नहीं थे। आपसे प्राइमरी या मिडल स्कूल मांगते थे तो आप जमा-दो स्कूल दे देते थे जबकि बिल्डिंग उपलब्ध नहीं थी। स्कूलों की हालत ऐसी कि कई स्कूल बिना अध्यापकों के चल रहे थे बल्कि जो चले हुए स्कूल थे उनमें भी शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो गई क्योंकि अधिकतर स्कूल डैपुटेशन पर आए अध्यापकों के सहारे चल रहे थे। आपने एस0एम0सी0 के माध्यम से बैकडोर एंट्री की। आज स्कूलों की जो हालत है उसके बारे में मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि आपने लोगों को लाभ देकर एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्ती तो कर दिया और उसमें आपने 5 नम्बर पंचायत के दे दिए, 5 नम्बर पटवार सर्कल के दे दिए लेकिन इस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है। आपने मैरिटी को इग्नोर करके उनको सर्विस दी और आज हालत यह है कि जो एस0एम0सी0 के माध्यम से आपने अध्यापक लगाए हैं वे

नियमित होकर शहरों के नज़दीक जा रहे हैं। आपने भर्ती के समय क्यों सुनिश्चित नहीं किया कि जब वे अध्यापक नियमित होंगे तो उसी स्कूल में रहेंगे? नियमित होने के बाद वे अध्यापक 3-4 साल भी पूरा नहीं करते थे और निचले क्षेत्रों में ट्रांसफर करवाकर चले जाते थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर एंट्री का एक धन्धा खोल दिया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्ती हुए और शिलाई/रेणुका में 4-4 साल भी नहीं रहे तथा सारे लोग पौंटा और नाहन मे सर्विस करने चले गए। ऐसे लोगों को सर्विस तो बैकडोर एंट्री से चाहिए।

06.02.2019/1235/जेके/वाईके/1

1.1.2013 से 31.12.2013 तक केवलमात्र 269 अध्यापकों की एक साल में भर्ती की और स्कूल हजारों खोल दिए। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने जो आपने स्कूल खोले थे, एक साल में 1.1.2018 से 31.12.2018 तक 3,013 अध्यापकों की भर्ती की और वित्त विभाग से 5,502 अध्यापकों की भर्ती की स्वीकृति मिली है। उन पोस्टों को भी हम भर रहे हैं। आप लोग दिहाड़ीदारों के बड़े शुभ-चिन्तक बनते हैं। जब प्रदेश में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी थी, उस समय हिमाचल प्रदेश में मज़दूरों की दिहाड़ी 55 रुपये थी और जब हमारी सरकार गई तो उस समय तक 170 रुपये दिहाड़ी हो चुकी थी । हमने पांच साल में 95 रुपये बढ़ाए और आपकी सरकार ने 170 रुपये से 210 रुपये किए, यानि पांच साल में 40 रुपये बढ़ाए। हमने 95 रुपये बढ़ाए और आपने 40 रुपए बढ़ाए। 170 रुपये से 210 रुपये में आप बड़ी मश्किल से पहुंचे। आपने 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये बढ़ाए। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पहले वर्ष 210 रुपये से 225 रुपये मज़दूरी की यानि 15 रुपये बढ़ाए और इस बजट में जो यह 40 रुपये का गैप है, शायद वह भी पूरा हो जाए। इस तरह से काम करने वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में है। आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ भी काम नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में एक साल में कुछ भी नहीं

किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को डायलासिस करवाने के लिए देहरादून, यमुनानगर, चण्डीगढ़ तक जाना पड़ता था। उसके लिए 2000/- रुपये की गाड़ी करके जाओ, 2000/-रुपये वहां पर दो तो इस तरह से 4000/-रुपये लगते थे। मैं, आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष में शिमला, ऊना, बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, चम्बा और पांवटा में डायलासिस शुरु किया गया। हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति को फायदा हुआ है जो डायलासिस 1000/-रुपये या 1500/-रुपये में होना था, वह भी फ्री में हो रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत में कवर है तो कोई व्यक्ति हिम केयर में कवर है और उसको फ्री में अपना डायलासिस करवाना होता है। गरीब व्यक्ति की वेदना तो देखिए जिसने हर हफ्ते डायलासिस करवाने जाना है। हर हफ्ते उसे 2000/-रुपये चाहिए। महीने का 30,000/-रुपये चाहिए। यह जो सुविधा हमारे प्रदेश सरकार में दी है इसके लिए हम आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कवर किया है। पांच लाख रुपये का इन्श्योरैंस किया है और पूरे भारतवर्ष में ऐसे 1200 हॉस्पिटल हैं जिनमें यह ट्रीटमैंट होगा। मैं, आदरणीय जय राम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो 2,75,000 लोग छूट गए थे और इस योजना में कवर नहीं होते थे, मुख्य मंत्री जी ने उन लोगों को हिम केयर में कवर किया। 53 प्राइवेट हॉस्पिटल और सारे सरकारी हॉस्पिटल्ज़ में 5,00,000/-रुपये की सुविधा दी। बी0पी0एल0 परिवारों को फ्री में यह सुविधा दी है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, प्लंबर हैं, कारपेंटर हैं, मैंसन का काम करने वाला, खिचड़ी बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको 350/-रुपये साल के देने हैं और जो आम आदमी है उसको 1,000/-रुपये देने हैं। इस तरह की योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने लागू की हैं। हैल्थ को हमारी सरकार कितना स्ट्रैंथन दे रही है। हिमाचल प्रदेश को एम्ज़ दिया जिसके लिए हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। बिलासपुर में इसका काम शुरू हो गया है। इतना बड़ा संस्थान हमें मिला है। स्वास्थ्य के

क्षेत्र में जो केन्द्र व प्रदेश की सरकार ने काम किया है, वह सराहनीय है। स्वच्छता के क्षेत्र में आपने महात्मा गांधी का नाम ले कर कुछ नहीं किया। नाम महात्मा गांधी जी का लेना, काम उनके नाम पर कोई नहीं करना। मैं, प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि

06-02-2019/1240/SS-AG/1

9 करोड़ शौचालय पूरे भारतवर्ष में देश के लोगों को 12 हजार के हिसाब से आपने 10 ईयर में बनाकर दिए हैं। यह बहुत बड़ा काम है। प्रधान मंत्री आवास योजना है। क्रांति कहां आती है, कौन क्रांति लाता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश में क्रांति लाए थे जब उन्होंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उन्होंने गांव नहीं देखा और कहा कि यदि इसमें इतनी पापुलेशन होगी तो वहां सड़क बनेगी। प्रधान मंत्री आवास योजना में अभी हिमाचल प्रदेश का सर्वे होकर गया है। उसमें जाति नहीं देखी गई। जिस व्यक्ति का कच्चा घर है, जिसकी टीन है, जिसका छप्पर है, उसका पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वे हुआ है। हजारों घरों का चयन हो कर केन्द्र में गया है, वहां से एकमुश्त पैसा आयेगा। जिस तरह से प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़कें बनीं, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री आवास योजना में 2022 तक हमारे देश के प्रधान मंत्री का सपना है कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के न रहे। उसको केन्द्र की सरकार 130000 रुपया दे रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री आवास योजना में घर बनेंगे। वैल्फेयर में घर बन रहे हैं। ये इस तरह की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार मिलकर हिमाचल प्रदेश को मजबूत कर रही हैं।

उपाध्यक्षः चौधरी साहब, कृपया वाइंड अप करें, बहुत समय हो गया।

श्री सुख रामः जहां तक हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में हिमाचल प्रदेश में हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री ने खुली निविदाएं खनन के लिए लीं। 151 खनन की खड्डें, जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लाई किया, उनको आबंटित की हैं। इससे प्रदेश को 105 करोड़ रुपये की आमदनी होनी है। 3500 करोड़ रुपये की एक वर्ष में इंडस्ट्री में इंवैस्टमैंट कर रहे हैं उससे प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह की योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश को फायदा होने वाला है।

अध्यक्षः प्लीज़ वाइंड अप करें।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आई0पी0एच0 की बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... सबने 25-25 मिनट लिये हैं। आपने (श्री राम लाल ठाकुर) भी 25 मिनट बोला है। मैं आई0पी0एच0 विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश में आई0पी0एच0 के अंतर्गत एक वर्ष में करोड़ों रुपया केन्द्र की सरकार से आया है। उसकी मैं थोड़ी-सी डिटेल इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं। स्वां खड्ड के लिए 356 करोड़ रुपया आया है। छौच खड्ड के लिए 153 करोड़ रुपया, पांवटा सीवरेज के लिए 11.57 करोड़ रुपया आया। पुरानी पेयजल स्कीमों के लिए ए0डी0बी के माध्यम से 798.19 करोड़ रुपया, डी0एफ0आई0 वाटर स्कीम के लिए 4751.24 करोड़ रुपया, ए0एफ0डी0 के लिए 378.30 करोड़ रुपया, बागवानी में 1688 करोड़ रुपया और बाढ़ नियंत्रण में 4893 करोड़ रुपया, पर्यटन में 1892 करोड़ रुपया, राजगढ़ की सीवरेज स्कीम 18.92 करोड़ रुपया, नाहन की 72 करोड़ रुपया इत्यादि, यह कुल मिलाकर 15344 करोड़ रुपया बनता है। अभी तो ट्रायल है, नयी-नयी सरकार है और पैसा आ रहा है, जब यह पैसा धरातल पर लगेगा तो आप कहीं नज़र नहीं आयेंगे। चिन्ता मत करो, आपने पांच साल बाद भी यहीं पर बैठना है जहां पर आप अभी बैठे हैं। क्योंकि अभी यह पैसा आ रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ...(व्यवधान)... काम तो सारे हिमाचल प्रदेश का करना है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मैं सिर्फ अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपके (विपक्ष) पांच साल के बारे में बोलना चाहता हूं। पांच साल पांवटा विधान सभा क्षेत्र की नाबार्ड में 16 करोड़ रुपये की स्कीमें स्वीकृत हुई हैं, बाकी किसी फंड से कोई स्कीम नहीं आई। मेरे पास यह दस्तावेज़ है। आई0पी0एच0 में पेयजल और सिंचाई की कोई भी स्कीम आपके पांच साल के समय में पांवटा विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत नहीं हुई। स्वीकृत होनी तो अलग बात है, नाबार्ड में हमारी कोई स्कीम पहुंची नहीं और कोई काम पांवटा में नहीं किया।

6.2.2019/1245/केएस/एजी/1

एक ब्रिज के बारे में वहां बार-बार बोला जाता था। विकास नगर से बगानी साहब का यमुना नदी पर एक ब्रिज बनना था। हर बार स्टेटमैंट लगती थी कि बस अगली बार मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं, शिलान्यास करके जाएंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पांच साल इंतज़ार ही करता रहा कि मुख्य मंत्री जी कब आ कर उसका शिलान्यास करेंगें। मैंने सोचा बाकी काम हो या न हो, दो कार्यों की बात कर रहा हूं। एक कुलथिना की सड़क थी, जब मैं चुनाव हारा था उस वक्त मुझे वहां से 7 वोट मिले थे और दूसरे को एक सौ कुछ वोट मिले थे। बड़े दुख की बात है, पांच साल बाद सरकार चली गई और जब पांवटा के लोगों ने मुझे यहां चुनकर भेजा तो मैंने जानना चाहा कि उसकी डी.पी.आर. बनी या नहीं लेकिन उस ब्रिज की डी.पी.आर. ही नहीं बनी। अब हमने उसका शिलान्यास करना है। कुलथिना सड़क की भी डी.पी.आर. नहीं बनी, उसका भी काम का शुभारम्भ करना है।

उपाध्यक्षः चौधरी जी, वाइंड अप प्लीज़।

श्री सुख रामः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय जयराम जी की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं । एक वर्ष में केन्द्र से उस ब्रिज की 100 करोड़ रुपये की प्रिंसिपल सेंक्शन मिली है। उस ब्रिज की बहुत जल्दी डी.पी.आर. बन रही है। दो-तीन महीने में डी.पी.आर. बन जाएगी। वे पांच साल में शिलान्यास ही नहीं करवा सके, हम शिलान्यास भी करवाएंगें और पांच साल में उसको लोगों को बनाकर भी देंगे। चिंता मत करो अभी तो हमारी सरकार बने एक साल ही हुआ है। बजट पास हुए अभी दस महीने हुए हैं। बहुत सी स्कीमें पाइप लाइन में है। बहुत से लोगों को सर्विस देंगे। पाइप लाइन में आई.पी.एच है, पी.डब्ल्यू.डी. है, सारे विभाग हैं और ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक लाख कुछ लोगों को पैंशन लगी है । इन सभीमुद्दों को ले कर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे । आदरणीय जय राम

ठाकुर जी के नेतृत्व में हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे और आने वाले समय में इस तरह का हिमाचल प्रदेश बनाकर देंगें जो पूरे भारत वर्ष में नम्बर-1 प्रदेश बनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अभिभाषण दिया है, कर्नल इंद्र सिंह जी ने जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और समर्थन श्री बलबीर सिंह जी ने किया, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं । जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगें। ब्राक्टा जी, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 4 फरवरी, 2019 को राज्यपाल महोदय जी ने यहां अभिभाषण दिया, जिसका कर्नल इन्द्र सिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और माननीय बलबीर सिंह जी ने जिसका अनुमोदन किया, मैं भी उस संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मेरे से पूर्व दोनों तरफ से काफी वक्ताओं ने इस पर डिटेल में बात कर दी है, मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां तक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, यह सरकार का लिखा हुआ डॉक्युमैंट होता है। जो सरकार के अधिकारियों को आदेश थे, उन्होंने वह लिखा । जो भी अभिभाषण में लिखा है, उसको पढ़ने की राज्यपाल महोदय की भी मजबूरी थी। उसमें सरकार के एक साल के कार्यों की तारीफ़ें की गईं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस डॉक्युमैंट में जो भी तारीफें की गई हैं, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय विधायक विनोद भाई कल कह रहे थे कि एक साल में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिल्ली से लगभग 10 हजार करोड़ रुपया लाया है । मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं, जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है, वहां तो एक साल में एक भी पैसा नहीं आया । वह 10 हजार करोड़ कहां गया? या तो वह पैसा माननीय मुख्य मंत्री ने अपने चुनाव

क्षेत्र में भेजा होगा या मण्डी में भेजा होगा लेकिन जहां तक रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र की बात है,

6.2.2019/1250/av/dc/1

मैं तो यह कहूंगा कि पिछले वर्ष के दौरान एक भी विभाग में रूटीन वाले कार्यों को छोड़कर किसी बड़े प्रोजैक्ट पर एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी रोहड़ू निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों व अधिकारियों के निर्देशों पर काफी भीड़ जुटाई गई। वहां पर महिला मण्डलों को आश्वासन दिए गए कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं और आपको पैसे मिलेंगे जिसके कारण वहां पर काफी लोग आए। वहां लोगों को आशा भी थी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय पहली बार रोहड़ू आ रहे हैं और शायद कोई तोहफा देकर जायेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि या तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को मांगना नहीं आया या फिर मुख्य मंत्री खुद नहीं देना चाहते थे। उन्होंने वहां पर रोड्ज के पैसे मांगे और जब मैंने बाद में पता किया तो मैक्सिमम उन रोड्ज के पैसे थे जिनका भारतीय जनता पार्टी से सम्बंधित ठेकेदारों ने काम कर दिया था या करना था क्योंकि उनकी पेमैंट्स रुकी हुई थी। अभी माननीय सदस्य, चौधरी साहब आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट की बात कर रहे थे। पिछले एक वर्ष के दौरान मैंने हर विधान सभा सत्र के दौरान प्रश्न लगाया कि मेरे रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट की ऐसी कितनी बड़ी स्कीमें हैं जिनका काम अधूरा पड़ा है। जिसके बारे में शुरू से लेकर अभी तक जवाब आता है कि कुल 40 स्कीमें हैं और हो जायेगी। उनका काम पूरा हो जायेगा मगर अभी तक उनमें से एक भी स्कीम सिरे नहीं चढ़ी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण में जो घोषणाएं या तारीफें की गईं वे सारी गलत हैं। इसके अतिरिक्त आज यहां अस्पताल के बारे में भी प्रश्न लगा था। मैं तो माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में हमारे प्रदेश में कई नये मेडिकल कालेज खोले गये। इसके अतिरिक्त पी0एच0सीज0 और दूसरे स्वास्थ्य संस्थान खोले गये। पिछले कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री

जी ने यहां पर स्वाइन फ्लू के बारे में एक वक्तव्य दिया था मगर मैं तो कहूंगा कि सरकार उसमें भी फेल हुई है क्योंकि पिछले कल की सूचना के अनुसार इसके कारण अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। आप लोग कहते हैं कि हमने एक वर्ष के कार्यकाल में बहुत कुछ किया है। हमने इतने डॉक्टर, टीचर व अन्य भर्तियां की हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में डॉक्टर्ज की हजारों पोस्टें खाली पड़ी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी रोहड़ू सिविल होस्पिटल है जिसमें केवल रोहड़ू के मरीज नहीं जाते। उस होस्पिटल में साथ लगते जुब्बल-कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र के लोग आते हैं और उत्तराखंड के लोग आते हैं। यहां तक कि वह होस्पिटल रामपुर के कुछ एरिया को भी फीड करता है। हमारे रोहड़ू होस्पिटल की डेली की रजिस्ट्रेशन संख्या यहां के डॉ0 दीनदयाल उपाध्याय होस्पिटल के बराबर है। राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से वहां पर डॉक्टर्ज की 31 पोस्टें स्वीकृत हैं मगर आप देखिए आज वहां पर कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैं इस बारे में बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला हूं। मैं जहां-जहां पर जा सकता था, गया मगर वहां पर आपके एक वर्ष के कार्यकाल में कोई भी पोस्ट नहीं भरी गई। इसके अलावा कल माननीय मुख्य मंत्री जी हैलीकॉप्टर की उड़ान के बारे में कह रहे थे कि इसकी सेवाएं लाहौल-स्पिति, किन्नौर और डोडरा-क्वार इत्यादि दूरदराज के क्षेत्रों में दी जा रही है।

06/02/2019/1255/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

डोडरा क्वार क्षेत्र ऐसा है जो 6 महीने रोड से कटा रहता है। वहां के लिए नोटिफिकेशन्ज हुई है और सर्दियों में वहां के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। इस बार बड़ी मुश्किल से 4 दिन पहले वहां के लिए हेलिकॉप्टर गया था। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मुझे डोडरा क्वार से सूचना मिली है कि अभी तक वहां पर बहुत मरीज़ फंसे हुए हैं, इसलिए जल्दी-से-जल्दी वहां के लिए दोबारा हेलिकॉप्टर सेवा भेजी जाए। इसके बारे में मैंने जब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से बात की तो मुझे उत्तर मिला कि अभी तो हमारे पास हेलिकॉप्टर नहीं है क्योंकि अभी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं जाना है। वैसे मुझे कल की डेट मिली है, अब देखते हैं कि कल वहां के लिए हेलिकॉप्टर सेवा जाती है या

नहीं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि कल डोडरा क्वार के लिए हेलिकॉप्टर भेजा जाए क्योंकि वहां पर हमारे बहुत पेशैंट फंसे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर स्कूलों के बारे में भी बात की गई है। माननीय सदस्य सुख राम जी कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश में स्कूल बहुत खोले। जोकि एक अच्छी बात है। माननीय सुख राम जी मुझे आपके निर्वाचन क्षेत्र का तो पता नहीं है लेकिन हमारे दूर-दराज के क्षेत्रों में,पहले हम प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। यदि प्राइमरी तक पढ़ाई कर ली तो मिडल नहीं कर सकते थे, मिडल तक पढ़ाई कर ली तो मैट्रिक नहीं कर सकते थे। मैं अपनी रोहडू विधान सभा की बात करना चाहूंगा, आज माननीय राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत हम अपने बच्चों को नज़दीक के प्राइमरी, मिडल मैट्रिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं कि राजा साहब ने बहुत स्कूल खोल दिए। आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए कि इन स्कूलों के खुलने से हर गरीब आदमी के बच्चों को आज शिक्षा मिल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जनमंच के बारे में काफी चर्चा हुई। आप इस जनमंच की बड़ी तारीफ़ करते हैं लेकिन ऑफिसरों के लिए तो यह जनमंच नहीं झंडमंच हो गया है। हर जनमंच में ऑफिसरों को लताड़ लगती है। किसी को कहा जाता है कि आपको सस्पेड़ कर देंगे या डिसमिस कर देंगे। इसके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले शिमला में भी जनमंच हुआ, उसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और मेयर के बारे में बड़ी चर्चा अखबारों में आई कि वे आपस में भीड़ गए। ---(व्यवधान)--- हमने तो पेपरों में पढ़ा बाकी हकीकत क्या थी ये तो आपको ही पता होगा। आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने एक साल में यह कर दिया वह कर दिया लेकिन वर्दियां तो आप स्कूल के बच्चों को दे नहीं पाए।

इसी तरह से सड़कों की खस्ता हालत है। पीने के पानी के बारे में आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि पिछली साल शिमला में जो पानी की दिक्कत आई थी, वह मौसम की वज़ह से आई थी। लेकिन हमारी सरकार के समय में तो कभी पानी का ऐसा संकट नहीं आया। इसका मतलब है कि आप इस काम में भी नाकाम हुए हैं।

बिजली विभाग की तो आज की तारीख में इतनी दयनीय स्थिति है कि आप पूछो मत। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, आज बर्फ पड़े 14-15 दिन हो गए हैं और मौसम भी साफ है। लेकिन अभी तक रोहडू विधान सभा के बाजार में भी लाइट नहीं आई है। ये आपकी एक साल के कार्यकाल की कामयाबी है। जब हमारी सरकार थी, उस समय कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। उस समय भी बारिश होती थी, सूखा पड़ता था और बर्फ पड़ती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः कृपया बीच में न बोलें। माननीय विधायक श्री सुरेश जी प्लीज़।

06-02-2019/1300 /NS/HK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा :लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो इसकी स्थिति भी आपके सामने है। आज आप लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल हैं। बागवानी क्षेत्र के बारे में तो मैं यही कहूंगा और यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि एक साल में आपकी सरकार ने जहां तक हमारे शिमला जिले की बात है और इसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है, यहां पर आपने विकास के कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जिसकी मैं तारीफ़ करूं। हो सकता है कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करना चाहते हों। आपकी सरकार ने हमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैंने छः महीने पहले अपने विधान सभा क्षेत्र के एक अधिकारी को एक काम के लिए टेलीफोन किया था तो उस अधिकारी का मुझे जवाब आता है कि आपके पास यहां पर कोई बैठा तो नहीं है। मैंने उसे कहा कि मैं अकेला हूं। अधिकारी कहता है कि आप रोहडू की बात बोलते हैं, यहां पर मंत्री महोदय के ये आदेश हैं कि आपने जिला शिमला में कोई ऐसा काम नहीं करना है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या वाईंड-अप करें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे ड्रग मीनेस के बारे में बोलना चाहता हूं। यहां पर बहुत तारीफ की गई कि हमारी सरकार ने ड्रग माफिया पर नकेल कसी है। इललीगल माइनिंग हुई, 1332 केसिज एन0डी0पी0एस0 में रजिस्टर्ड हुए, 1724 लोगों को अंदर किया गया और इसमें 10 विदेशी भी शामिल हैं तथा सरकार ने इसको टैकल करने के लिए पिछली बार अमेंडमैंट लाई थी। अमेंडमैंट क्या लाई? सिर्फ एक प्वाईंट पर

अमेंडमैंट लाई, बाकी कुछ नहीं किया और न ही कोई सजा बढ़ाई। अमेंडमैंट यह लाई कि जब आप कोर्ट में मुलज़िम को पेश करेंगे तो उस वक्त पब्लिक प्रोसीक्यूटर को नोटिस दे देंगे। इससे क्या होगा? वह व्यक्ति आज नहीं तो कल छूट जाएगा या दो दिन के बाद छूट जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सारी बातें सरकार के ध्यान में लाना चाह रहा था। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण 04 फरवरी को दिया है, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री विनोद कुमार (नाचन)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने मेरा नाम ले करके कहा है कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के आशीर्वाद से और केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लाया है तथा इन प्रोजेक्ट्स का कोई भी पैसा इनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपके रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में जहां पर पब्बर नदी शायद आपके ही विधान सभा क्षेत्र में आती है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं और इस नदी के चैनलाईजेशन को ले करके पिछले पांच सालों तक आप दौड़ते रहे थे। लेकिन आपकी सरकार ने इस पब्बर नदी के चैनलाईजेशन को ले करके कोई काम नहीं किया था। मैं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने पब्बर नदी के चैनलाईजेशन के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाई है। इसके साथ-साथ ---(व्यवधान)--- इन्होंने मेरा नाम कोड किया है।

उपाध्यक्षः माननीय मुकेश जी से मेरा आपसे आग्रह है कि आपको यह सब शोभा नहीं देता है।

श्री विनोद कुमारः ---(व्यवधान)--- इन्होंने मेरा नाम कोड किया है। ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः विनोद जी, आप बैठ जाएं। ---(व्यवधान)--- माननीय सदस्य इन्द्र सिंह जी (बल्ह) आप बैठिए। माननीय मुकेश जी, प्लीज़ बैठ जाईए। ---(व्यवधान)---

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

06.02.2019/1405/RKS/YK-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में 2.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया एक मिनट में अपना विषय रखें।

श्री विनोद कुमार(नाचन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर के जो प्रोजैक्ट्स हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सैंक्शन करवा कर लाई हैं उन प्रोजैक्ट्स के तहत उनके विधान सभा क्षेत्र में कोई भी पैसा नहीं दिया गया है।

06.02.2019/1410/बी0एस0/वाई0के0-1

लेकिन मैं इस माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पब्बर नदी के चैनेलाइजेशन के बारे में चर्चा करते थे। परंतु पांच वर्षों तक इस कार्य को ले करके कुछ नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय ठाकुर जय राम जी का जिनके आशीर्वाद से जो अभी फ्लड प्रोटक्शन का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार से ले करके आए हैं उसके तहत 200 करोड़ रुपये इनके क्षेत्र में चैनेलाइजेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विनोद कुमार जी कोई इसके अतिरिक्त विषय है तो उसे बताएं अन्यथा अगले माननीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी बोलने के लिए तैयार रहें।

श्री विनोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके साथ भेदभाव हुआ है यह बात सरासर गलत है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य विनोद कुमार जी, आप कृपया बैठ जाइए। नॉट टू बी रिकार्डिड।

श्री परमजीत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री कर्नल इन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इसके लिए समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार का जो एक वर्ष का कार्य काल रहा है यह बहुत ही उपलब्धियों भरा साल रहा है। ये उपलब्धियां माननीय मुख्य मंत्री जी की मेहनत और अथक प्रयासों से प्राप्त हुई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 65 विधान सभाओं का दौरा किया और हर विधान सभा क्षेत्र में लोगों के मिल करके उनकी समस्याओं का हल किया और सभी लोगों के दुख को समझा और सभी लोगों से मिलने की कोशिश की है । हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। हम सभी लोग राजनीति से संबंधित है । हम हर प्रकार की खुशी और गम में लोगों के पास जाते हैं । उस वक्त जब हम बुजुर्ग लोगों से मिलते थे वे हम से पूछते थे कि हमारे को सामाजिक सुरक्षा पैंशन कब लगेगी? क्या जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब लगाई जाएगी? मैं आपसे इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल जो कैबिनेट का पहला फैसला लिया उसमें आयु सीमा को 80 वर्ष से घटा करके 70 वर्ष की है । इसमें 1.60 लाख जो पात्र व्यक्ति थे उनको इसका लाभ मिला है। जिन लोगों ने 70 वर्ष की आयु को पार किया है उसमें भी 60 हजार लोग इस पैंशन को लेने के लिए पात्र बने हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्य आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया है।

हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या है वह एक विराट रूप धारण की रही है । लेकिन आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले बजट में जो योजनाएं बेरोजगार युवाओं के लिए चालू की हैं चाहे वह "स्वावलम्बन" योजना है चाहे दूसरी योजनाएं है उसका हमारे प्रदेश के अनेक युवाओं ने लाभ लिया है । यहां तक कि

कुछ युवाओं ने अपना काम करके उसमें और लोगों को भी रोजगार देने का कार्य किया है। इसके लिए में सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेटी है अनमोल योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार की लड़कियों के लिए,

06.02.2019/1415/DT/AG-1

जन्म के उपरान्त दिए जाने वाले अनुदान को भी 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रूपये कर दिया गया है जिससे 21,483 लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं आदरणीय जय राम ठाकर जी का जिन्होंने प्रधान मत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को नये मकान बनाने हेतु वित्त वर्ष में 21 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि जारी की है जिससे 3,158 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इससे निम्न व मध्यवर्गीय परिवारों का फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 2018-19 के दौरान 42 करोड़ की राशि से 3,014 आवासों का निर्माण किया जा रहा है और इससे भी निम्न वर्ग परिवारों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके लिए मैं श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है इससे हमारे देश के अंदर 8000 गैस कनैक्शन्ज हमारी बहनों व माताओं को जो धुएं से बीमार होती थी उनके लिए इसका प्रबंध किया है, जिसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक गृहणि योजना चालू करके लगभग 40 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री श्री किशन कपूर जी का भी धन्यवाद करता हूं । इन्होंने दालों और चीनी की खरीद पर पारदर्शिता लाने की

कोशिश की है उसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने को 99 करोड़ 18 लाख रुपये की बचत हुई है। यह एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां चर्चा हो रही थी कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक वर्ष के भीतर मेरे चुनाव क्षेत्र में इतनी टारिंग हुई है जो पिछले सालों में कभी नहीं हुई थी। ...(व्यवधान)...दून विधान सभा क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के लोग आते थे वे हमें पूछते थे कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है और आप कहते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ। मैं धन्यवाद करता हूं श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार का कि एक साल के भीतर इतनी सड़कें मेरे विधान सभा में टारिंग हुई और यह शायद पिछले पांच साल का रिकॉर्ड है। मजदूरों के बारे में जो मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो मजदूरी 210 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये की है उसके लिए भी मैं जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि जनमंच ऐसा है कि वहां पर अधिकारियों को डांटा जाता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी जनमंच हुए हैं उनमें अधिकतर लोगों के काम जनमंच में हुए हैं। उसमें कांग्रेस के लोगों के कार्य भी हुए हैं। मुझे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपके मुख्य मंत्री जी ने ऐसा काम शुरू कर दिया कि कि हमारे लोग आपके पास काम करवाने आ रहे हैं। इतने काम जो जनमंच में हो रहे हैं उससे शायद मेरे मित्र घबराए हुए लग रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह ऐसा काम शुरू कर दिया है जिमसे हिमाचल प्रदेश का हर बच्चा- बच्चा प्रशंसा कर रहा है। इससे आम गरीब जनता का, जो दूर-दराज के लोग थे, जो अधिकारियों के पास जाने से भी घबराते थे, जो बड़ कार्यालयों में नहीं जाना चाहते थे उनकी शिकायतों का मौके पर निपटारा हो रहा है। यह अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए मैं आदरणीय जय राम ठाकुर की सरकार का धन्यवाद करता हूं।

06-02-2019/1420/ए.जी./एन.जी./1

मैं ज्यादा ना बोलता हुआ किसानों की बात भी करूंगा क्योंकि किसानों के बारे में आज तक हर एक राजनितिक दल ने अपनी रोटियां सेकी है और किसानों के उपर राजनीति की है । मैं इस देश के यश्स्वी प्रधानमन्त्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं ।

2014 से केन्द्र सरकार द्वारा 22 फसलों का समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाया जा रहा है । 2014 के बाद से इन फसलों का जितना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उससे से पहले इतना समर्थन मूल्य कभी नहीं दिया गया । भविष्य में भी सी -2 जैसी व्यवस्था केवल भाजपा सरकार करेगी । जैसे बीज पर सबसिडी, उच्च गुण्वत्ता का बीज, कृषि सयन्त्रणों पर सबसिडी, बैंक ब्याज में 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक सबसिडी आदी । इस प्रकार अनेक उपलब्धियां केन्द्र सरकार की किसानों के प्रति रहीं हैं । जो पिछला अन्तरीम बजट आया है इसमें माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के प्रति एक ऐसा काम किया है कि जो छोटे किसान है उन्हें एकड के हिसाब से 6 हजार रूपये उनके खाते में डालें जाऐंगे । किसानों के लिए किसी ने तो शुरूआत की है और मेरा मानना है कि यह एक बहुत अच्छी शुरूआत है ।

श्री पवन काजल : वायदा तो 15 लाख का किया था ।

श्री परमजीत सिंह : काजल जी 15 लाख भी आ जाएगा । 15 लाख तो आप लोग कहते रहते हैं परन्तु जितना लाभ पिछले साढे चार साल में केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के लोगों को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को दिया है उतना पिछले 60 सालों में कांग्रेस की सरकारें कभी नहीं दे पाई ।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की स्थापना जबसे हुई है इस प्रदेश में बहुत से मुख्यमन्त्री आए और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सभी ने बहुत मेहनत की और सबने काम किया । लेकिन आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एक साल के अन्दर ही हिमाचल प्रदेश में वो छवि बनाई है जो आज तक कोई भी मुख्यमन्त्री नहीं बना सका और इहिास में एक रिकार्ड कायम किया है । आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा-बच्चा श्री जय राम ठाकुर जी के सरल स्वभाव के कारण मुख्यमन्त्री जी को नाम से जानता है । हमारा मुख्यमन्त्री हमारे परिवार का सदस्य है इस लिए आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक साल में इतनी उपलब्धियां हासिल की है । मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि

क्या किया है ? लेकिन ये सब चीजें आप हिमाचल प्रदेश की जनता से जाकर के पुछीए की सारी जनता आज श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार का गुणगान करती है । आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत -बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष : अब चर्चा में भाग लेंगे श्री आशीष बुटेल जी ।

श्री आशीष बुटेल : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, परसों जब माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो छोटी-छोटी बातें उनके भाषण में कही गई । भाषण शुरू हुआ एक श्लोक से 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'। उपाध्यक्ष महोदय, जिस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार के 515 मामले, बलात्कार के 345 मामले, कत्ल के करीब 100 मामले और कुल मिलाकर 1 हजार से उपर क्रीमिनल केसस रजिस्टर्ड हुए हो वो भी केवल एक साल के अन्दर तो वहां की जनता कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सकती है और ऐसा भी कैसे हो सकता है कि जिस हालत में आज यहां के पेशन्टस हैं या हैल्थ को पूरा विभाग यहां पर चलता है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस श्लोक को कैसे आधार मान कर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण शुरू किया । कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमान्त्री जी या किसी मन्त्री जी ने एक्सीडेन्ट, मर्डर और क्राईम के लिए कोई डीओ नोट साईन नहीं करके दिया यह बिलकुल ठीक बात है और ऐसा तो हमने भी कभी नहीं कहा लेकिन एक माहौल बनाने की बात होती है इस सरकार ने इस प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया है । क्रीमिनलस के लिए एक कन्डयूसिव माहौल बनाया है और इसी के विरोध में आज हम यहां पर खडे हुए है । हमने तो सिर्फ यही बात कही कि जो यहां पर क्रीमिनल है वो खुला छुटा हुआ है, उसको किसी का कोई डर नहीं,

06/02/2019/1425/RG/DC/1

उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, किसी और चीज का डर नहीं, वे खुलकर अपने क्राइम को अन्ज़ाम देते जा रहे हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। फिर थोड़ी-थोड़ी और बातें उन्होंने

बीच में लीं। जैसे आप सभी बहुत इतरा रहे हैं और सभी सदस्यों ने पी.एम.ए.वाई.(प्रधानमंत्री आवास योजना) की बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार मेरे विधान सभा के डवलपमेंट ब्लॉक में सिर्फ 9 केस स्वीकृत होकर आए हैं और इससे पहले कम-से-कम 50-60 केस तो आते ही आते थे। यह एक बहुत ही हैरानी की बात है। इस पर इतना इतराना नहीं चाहिए, इस पर तो सरकार को कहीं-न-कहीं शर्म आनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ और बातें भी यहां सांझा करना चाहता हूं। 'यूनिवर्सल हैल्थ स्कीम' की बात यहां कही गई। फिर कहने लगे कि हमने उसको 'हिम केयर' में मर्ज कर दिया, बहुत अच्छी बात कही। 'हिम केयर' में आजकल लाईनें लगी हैं, उनका सॉफ्टवेयर नहीं चलता और जिसके काड्र्स बन जाएं, उसके काड्र्ज अस्पतालों में नहीं चलते। तो उसका क्या किया जाए? यह कौन सी ऐसी स्कीम आप लेकर आ गए या कौन सी ऐसी अचीवमेंट आप लोगों की हो गई जिससे आप यह कहने लगे कि हमने ऐसा करके दिखा दिया। पेशन्ट्स को आपने सपने दिखाए, उनको कहा कि बिना पैसे के आपका उपचार होगा और पांच लाख रुपये तक का आपका मुफ्त उपचार होगा। जब वहां कार्ड ही नहीं चलेगा तो उसका क्या इलाज है, कृपया वह भी बताएं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके पश्चात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि डायलैसिस के सेन्टर्ज खुल गए। यह बहुत अच्छी बात है कि सेन्टर्ज खुल गए। पालमपुर में भी खुला, लेकिन कब खुला, किस समय और कितनी देर बाद शुरू हुआ, यह देखने वाली बात है। पालमपुर का 200 बिस्तरों का अस्पताल हमारी कांग्रेस की सरकार करके गई थी। आपने उसमें अभी डॉक्टर्ज भेजे हैं, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो डायलैसिस की बात यहां की गई है, तकरीबन दो साल से डायलैसिस की दो मशीनें वहां पड़ी हुई थीं जिनको एक एन.जी.ओ. डोनेट करके गए थे। लेकिन आपकी सरकार उसको चलाने में असमर्थ थी, उसको चला नहीं पा रही थी और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वह नहीं आ रहा था। लेकिन उसका श्रेय भी आप लोग लेना चाहते हैं, यह तो बहुत दुःख की बात है। इसके बाद कई स्कीमें आपने दे दीं जो पिछले बजट में अनाउन्स हुई थीं। जैसे कि एक 'मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना'। अभी तक उसका किसी भी अस्पताल में कुछ भी नहीं पहुंचा जिसमें किसी महिला की डिलीवरी होने पर बच्चे को पॉऊडर, साबुन

आदि सामान देना था। ये चीजें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। फिर आपने कहा कि 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना', इसमें आपने एक ऐसी शर्त रख दी कि बीस किलोमीटर के रेडियस में कोई सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए। ऐसी-ऐसी शर्तें रखकर आपने लोगों के सामने जो बातें कहीं, उनको गलत तरीके से पेश किया गया। पिछली बार जब आपने अपने बजट में ये स्कीमें दीं, आप यह चाहते ही नहीं थे कि ये स्कीमें कभी इम्प्लीमेंट हों। इसलिए आप लोगों ने ऐसी-ऐसी शर्तें इन स्कीमों में रखीं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्यटन की बात करें तो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन की बात यहां करुंगा। रोप वे का कितनी बार जिक्र हुआ और आजकल जो हमारे यहां मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने भी कई बार आपकी सरकार को कहा। वे तो आपके ही हैं। कैबिनेट में भी कई बार पास किया, लेकिन आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई। आपने कहा कि धार्मिक सर्किट योजना बनाएंगे। आप बताइए कि चामुण्डा जी, बज्रेश्वरी माता, बगुलामुखी माता, बैजनाथ जी और ज्वालाजी के लिए क्या धन की उपलब्धता करवाई गई? यह समझ से बाहर है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जब आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा तभी टूरिज्म आपके पास आएगा। सड़क, बिजली और पानी के यहां खस्ताहाल हैं। और-तो-और शिमला में आपने पर्यटकों को ऐडवाइजरी जारी की कि आप शिमला न आएं क्योंकि यहां खस्ताहाल है। तो अगर हम पर्यटन के प्रति इस तरह से करेंगे तो यहां किस तरह से पर्यटन का विकास होगा, यह भी समझ से बाहर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात यहां कृषि की बात कही गई। सिर्फ एक स्कीम है जिसके बारे में आप कहते रहते हैं कि 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान', यह सिर्फ एक स्कीम है जिसमें कुछ पैसा आया है। 'सौर सिंचाई योजना' में जीरो बजट, 'कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र' में जीरो बजट, पौली हॉऊस रेनोवेशन स्कीम में आपने पता नहीं कि पैसा भेजा या नहीं भेजा, लेकिन एक आदमी भी ऐसा बता दीजिए जिसने मेरे विधान सभा क्षेत्र से या पूरे कांगड़ा जिले से पॉली हॉऊस रेनोवेशन स्कीम के तहत अपनी पॉली हॉऊस की शीट चेन्ज करवाई हो। ये दुखद बातें हैं। सेन्टर ऑफ ऐक्सीलैंस इन पालमपुर आना था लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। आपने फ्लौवर्ज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए 25% के लिए अनाउन्स किया था

कि आपको 25 परसेंट उसका लाभ मिलेगा। अभी तक उसके ऊपर 25 परसेंट सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी गई बल्कि आपने अभी अपने अभिभाषण में कहा है, हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह सच है या झूठ है लेकिन उसमें कहा है कि हमने सब्सिडी 20 परसेंट कर दी है। इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है।

यहां पर "जनमंच" की बड़ी-बड़ी बातें की गईं। पालमपुर में भी 1 जुलाई को जनमंच का कार्यक्रम रखा गया था। इस बात से इस सरकार की सीरियसनैस का पता चलता है कि वहां मंत्री जी आए और वहां पर पुलिस स्टेशन के पीछे एक फ्लाईओवर ब्रिज है, उसका मुद्दा उठा। जब यह मुद्दा उठाया गया तो मंत्री जी ने अधिकारियों से पूछा कि यह कब तक तैयार हो जाएगा? अधिकारियों ने इसके लिए दो महीने की डैडलाइन दी और मंत्री जी ने कहा कि आपको तीन महीने दिए जाते हैं, क्या यह ठीक है? अधिकारियों ने कहा कि 'हां', यह ठीक है। आज तक वह पुल जनता को समर्पित नहीं हो पाया है। उसके क्या कारण रहे, इसको आप ही बता सकते हैं। फिर आपने जनमंच के बारे में यह भी कह दिया कि हमने लगभग 100 जनमंच कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आपकी सरकार क्या यह कहना चाह रही है कि लोगों के काम सरकारी दफ्तरों में नहीं होते हैं? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि यदि लोग जनमंच में नहीं आएंगे तो उनके काम नहीं होंगे? आपने कहा कि 24 से 25 हजार रिड्रेसल्ज हुए हैं। मतलब एक जनमंच में आपने 250 रिड्रेसल्ज किए। उसमें आपने 2 लाख रुपये धाम के लिए दिए ...(व्यवधान)... आपने यह लिखकर दिया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये का खर्चा अफसरों के आने-जाने और वहां पर सारी चीजें करने का है। इस तरह से एक रिड्रेसल जो आप कह रहे हैं वह तकरीबन 4 हजार रुपये की पड़ती है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री आशीष बुटेलः अगर इस तरह से पब्लिक के पैसे का आप दुरूपयोग करना चाहते हैं तो यह बहुत दुःख की बात है। आप कहते हैं कि हमने वहां पर सर्टिफिकेट और म्युटेशन

करवाई। किस बात के सर्टिफिकेट और म्युटेशन? क्यो वे तहसील में नहीं होते? आपको वहां क्यों जाना पड़ता है? इस जनमंच को किसी ने झण्डमंच भी बताया परन्तु मैं तो इसको लंचमंच कहूंगा। यह लंचमंच है जहां पर आप लंच के लिए आ रहे हैं। वहां पर आप अपने अफसरों को इकट्ठा करके उनकी खड़काई भी कर रहे हैं और उनको सुना भी रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं भी वहां था। मैं स्वयं उस चीज का साक्षी हूं। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य जम्वाल जी, कृपया बीच में न बोलें। बुटेल जी आप अपने भाषण पर कन्सन्ट्रेट कीजिए।

श्री आशीष बुटेलः ...(व्यवधान)... मैंने वहां लंच बिल्कुल नहीं किया। फिर कहने लगे कि इस सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया। आप लोग शायद भूल गए हैं कि जब "मनरेगा" चला और यू0पी0ए0 ने इस प्रोग्राम को शुरु किया, उस समय महिला सशक्तिकरण की बात हुई। तब उनके खातों में पैसे जाने लगे। फिर आप कहते हैं कि मनरेगा में हमने इतने पैसे दिए। आज की स्थिति देखिए कि पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के भवारना और पंचरूखी दोनों जगहों में पैसा नहीं है जिससे वे अपना मटीरियल खरीद सकें। जब पैसा ही नहीं होगा तो मनरेगा भी किस काम की है, यह आप मुझे बताएं? फिर आप 120 दिन दिहाड़ी की बात करते हैं। वहां पर जब लोगों को रोज़गार ही नहीं दे पा रहे हैं तो उसका क्या फायदा है?

आप शिक्षा की बात कर लीजिए और "अटल वर्दी योजना" की बात कर लीजिए। उस योजना में वर्दी आज तक नहीं मिली है। "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" एक स्कीम चली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि यह इस सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार ने क्या किया। मेरे पास 16 जनवरी की एक नोटिफिकेशन है जिसमें एस0एम0सी0 को पावर दे दी कि जिसने बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखवाना है वह 5000/-रुपये देगा। मेरे पास यह प्रति है।(नोटिफिकेशन की प्रति दिखाते हुए) एस0एम0सी0 ऑफ द स्कूल को उन्होंने पावर दी है ...(व्यवधान)... इसमें लिखा है कि गौरव पट्ट पर नाम लिखवाने के लिए निर्धारित 5000/-रुपये की राशि लेने व न लेने तथा फॉरम भरने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति को अधिकृत किया जाता है यानी 5000/-रुपये अगर आप देंगे, तब आपका नाम उस नाम पट्टिका पर लिखा जाएगा अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। ...(व्यवधान)...

यह कॉपी स्कूल की नहीं है बल्कि यह प्रति आपके शिक्षा विभाग की है। यह 16 जनवरी की है। उपाध्यक्ष जी, मैं इसकी प्रति सभा पटल पर ले करता हूं।(प्रति सभा पटल पर रखी गई)।

उपाध्यक्षः ठीक है। आप वाइंड-अप भी कीजिए।

श्री आशीष बुटेलः अब सेंट्रल गवर्नमैंट को जाने के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं। फिर अचानक आपको याद आ गया कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल युनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करना है।

06.02.2019/1435/जेके/वाईके/1

उससे पहले आपने भी कुछ नहीं सोचा। पांच साल चले गए दोबारा आपकी सरकार नहीं आने वाली है। अगर उससे पहले आचार-संहिता लग गई तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार का कोई-न-कोई मंत्री यहां पर शिलान्यास करके चला जाएगा। यहां पर लेंगवेज ऑर्ट एण्ड कल्चर की बात करें, इस डिपार्टमैंट के जरिए आपने कहा कि हम 70 साल व 80 साल के लोगों को भ्रमण करवाएंगे। उसमें आपने फिर से आई वॉश किया। आप लोगों ने कहा कि उनको हम भ्रमण करवाएंगे लेकिन आपने एक लाख रुपये की उसके ऊपर इन्कम की कैप रख दी। अगर एक लाख रुपये की आपने कैप रख दी तो 10 हजार रुपये की जो उसकी कॉस्ट है, वह टूरिज्म ले रहा है। , एक लाख रुपये में से यदि कोई 50 हजार देगा तो एक भ्रमण के लिए वह 5,000 रुपये देगा। वह कहां से पैसा लाएगा जिसकी पूरे साल की इन्कम ही एक लाख रुपये से कम है? वह 5,000 रुपये क्यों और कैसे निकाल पाएगा? यह योजना भी एक आई वॉश थी। फिर आप कहने लगे कि आज पुरानी राहों से कोई स्कीम बनेंगी। इस स्कीम में भी कोई बजट नहीं। इम्पलॉयमैंट की आपने बात कही। मेरे पड़ोस में एक जॉब फेयर लगा। आप पूछिए जिन लोगों ने और जिन कम्पनीज़ ने वहां पर आ करके लोगों को रिक्रूट किया, आज उनकी क्या स्थिति है, क्या वे लोग उनके पास लगे हुए हैं या नौकरी छोड़ करके आ गए है या उनको निकाल दिया गया है? उस जॉब

फेयर ने उन्होंने कह दिया कि हम इतनी नौकरियां देते हैं लेकिन उसके बाद उनको लेना उन्होंने मुनासिब तक नहीं समझा।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप घंटी की तरफ ध्यान दें और अपने विषय को जल्दी से रखें।

श्री आशीष बुटेलः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन डवैल्पमैंट के अन्दर स्मार्ट सिटी की बात की गई। स्मार्ट सिटी में धर्मशाला का नाम था, उसमें छः करोड़ रुपये दे करके आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या छः करोड़ रुपये से आपकी स्मार्ट सिटी बन जाएगी? यहां पर आपने गग्गल एयरपोर्ट की बात की, उसको डिफैंस को दे रहे थे, उसको भी आप कांगड़ा से उठा कर मण्डी ले जाने की बात कर रहे हैं। कांगड़ा के साथ क्षेत्रवाद हो रहा है । ...(व्यवधान)... गग्गल के एयरपोर्ट को आपने डिफैंस के अन्दर देने की बात कही थी लेकिन आज आप मण्डी का एयरपोर्ट डिफैंस के हवाले करने की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्षः मेरा माननीय विधायकों से निवेदन है कि बीच में न बालें ।

श्री आशीष बुटेलः माननीय उपाध्यक्ष जी, मण्डी में देवी-देवताओं के जितने मंदिर हैं, उनकी डवैल्पमैंट की बात कर रहे थे। उसमें आज तक क्या हुआ, कितने पैसे आए और यदि टूरिज्म से आपने कोई पैसा लिया हो तो उसकी बात करें? मैं आपको यह बता दूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिवाय विधायक प्राथमिकता के और इससे पहले मेरे पिता जी वहां से विधायक थे, विधायक प्राथमिकता के अलावा एक भी काम अगर आप गिना देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। एक भी काम वहां पर नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही रिक्वैस्ट करूंगा, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आपका बजट आने वाला है तो इस बजट में हमारे लोगों के लिए कम-से-कम कुछ रोजगार की बात रखें। पालमपुर के टी-टूरिज्म की बात रखें और पूरे कांगड़ा के टूरिज्म की बात रखें ताकि वहां पर रोजगार बन सकें। इसी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण

महा-महिम् राज्यपाल महोदय जी का हुआ है, उसका मैं विरोध करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी चर्चा में भाग लेंगे । कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्तुत किया है, उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जय राम ठाकुर जी की लोकप्रिय सरकार ने एक वर्ष के अन्दर जितने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और आम जनता के लिए जो इतना कुछ किया है, मेरे से पूर्व भी और पिछले कल भी यहां पर बहुत सारे विषय रखे गए हैं। यह प्रदेश पिछले पांच वर्षों से नशे की गर्त में जा रहा था,

उसको रोकने के लिए यह सरकार कृतसंकल्प है और उसने अधिनियम लाने की पहल की। सख्त कानून बनाने की पहल की। युवाओं को नशे से बचाया जाए, उनके लिए जनजागरण किया जाए, उस नाते थाना स्तर पर ड्रग रोकथाम कमेटियां बनाईं। सोशल मीडिया में प्रचार किया। इसकी रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सम्मेलन करके, खुफिया एजैंसियों से जानकारी सांझा करके, ड्रग माफियों को किस तरह से रोका जा सकता है उस नाते एक साल के अंदर जो प्रयास हुए हैं, उसके लिए मैं तहदिल से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 सितम्बर को अचानक भारी वर्षा और बर्फबारी हुई। इसमें कुल्लू जिला में विशेषकर ब्यास नदी में, जब पूरा प्रशासन असहाय था और बाढ़ में लोग फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं पहल की और भारतीय वायुसेना के 7

हैलीकॉप्टर लाकर 252 लोगों को बचाया जोकि जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे। मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। उसके लिए मैं इस देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं।

मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो 23 तारीख की रात को ब्यास नदी में बाढ़ आई। मेरे चुनाव क्षेत्र में हुरला नामक स्थान है। दोनों तरफ बाढ़ आई और नदी के बीच में दो लोग फंस गए। मैं और प्रशासन भी वहां पहुंचा। अंधेरा हो चुका था। दो लोग मौत और जिन्दगी से जूझते रहे कि अब क्या करें। लेकिन सुबह 8:00 बजे भारतीय वायुसेना का हैलीकॉप्टर आता है और उन दोनों युवाओं को बचाया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संवेदना दिखाई है, उसके लिए हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। यह सरकार बहुत पारदर्शिता से काम कर रही है।

जहां प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए खुली बोली लगाई गई। ऑक्शन को ऑनलाइन किया गया, जिससे पारदर्शिता भी आई और प्रदेश के अंदर रेवेन्यू भी बढ़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, जय राम ठाकुर जी की यह लोकप्रिय सरकार प्रदेश के अंदर ग्रामीण स्तर पर अनछूए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से कैसे जोड़ा जाए, उस नाते 'नई राहें नई मंजिलें' योजना लाई है। प्रदेश के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर भी टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं और सबसे ज्यादा होम स्टे मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में चलते हैं, चाहे वह तीर्थन घाटी हो, चाहे जिवि वैली हो, चाहे सैंज या गड़सा वैली हो। आज तक मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर टूरिज्म को डिवैल्प करने के लिए कोई पैसा नहीं लगा। हम 15-20 सालों से देख रहे थे कि लारजी के अंदर सुन्दर झील हमारे पास है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से उस पर किसी की नज़र नहीं गई। पूर्व सरकार ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3.72 करोड़ रुपया उस पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए दिया है। हम प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के आभारी हैं कि वे एक वर्ष के अंदर 68 में से 65 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में गए। हर जगह गए, लोगों से सीधा संवाद किया। लोगों की मांगों को सुना और उनके लिए जगह-जगह घोषनाएं कीं। कल

विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बिना बजट के घोषणाएं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री 23 जून को बंजार आए थे। हमारी वर्षों पुरानी मांग थी कि वहां पर अग्निशमन केन्द्र होना चाहिए। फायर ब्रिगेड कुल्लू या लारजी से आती थी। लेकिन इस लोकप्रिय सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसे तुरन्त कैबिनेट में ला करके समस्या का समाधान करते हैं। 23 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी बंजार आते हैं, अग्निशमन केन्द्र की घोषणा करते हैं और ढाई-तीन महीने के बाद अक्तूबर में हमें अग्निशमन केन्द्र मिल जाता है।

6.2.2019/1445/केएस/वाईके/1

श्री सुरेन्द्र शौरी ....जारी----

और आज बंजार में अग्निशमन केन्द्र है और उसके लिए हमें भवन भी मिला। विपक्ष के साथी जो कह रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्य मंत्री एक साल के अंदर 65 विधान सभा क्षेत्रों में गया हो। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। कल हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि प्रदेश में एक भी लोक भवन नहीं बना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लोक भवन तो हर चुनाव क्षेत्र में बनेगा लेकिन हम एक नहीं, तीन लोक भवन अपनी विधान सभा में बनाने जा रहे हैं जिसकी प्रक्रिया चली हुई है। 15 लाख रुपये हमने उसके लिए अपनी विधायक निधि से दिए और 15 लाख रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी हमें देंगे, उसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरे पूर्व साथी जनमंच की चर्चा कर रहे थे। जनमंच कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। हजारों की संख्या में उसमें लोग आते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें आते हैं। जनमंच की यहां पर बहुत चर्चा हुई । जनमंच इतना सफल कार्यक्रम है जहां पर लोगों के मैडिकल टैस्ट भी हो रहे हैं, इंतकाल भी हो रहा है और जिस सर्टिफिकेट की लोगों को जरूरत है, वह सर्टिफिकेट भी बन रहा

है। उससे पूर्व जो प्री-जनमंच हर पंचायत के अंदर लगते हैं, उसकी अगर बात करुं, जनमंच में तो समस्या हल होती है लेकिन प्री-मंच में पहली बार लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय असल में हिमाचल में राम राज्य आ गया है। ब्लॉक का एस.डी.एम., एस.एच.ओ., ब्लॉक के सारे अधिकारी, उप मण्डल के सभी अधिकारी एक दिन में तीन-तीन पंचायतों में प्री-जनमंच में जा रहे हैं । लोग हैरान हैं कि हमारी लोकप्रिय सरकार घर द्वार जा कर, हर पंचायत हैड क्वार्टर में जा कर लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान कर रही है। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर आम जनता को आपकी इस तरह की बात पता चले, जिनके काम हुए हैं, उनके बीच जाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। यह इतना लोकप्रिय कार्यक्रम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उज्जवला योजना की बात की गई, अगर यशस्वी प्रधान मंत्री उज्जवला योजना लाते हैं तो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को चिंता होती है कि उज्जवला योजना के अतिरिक्त प्रदेश में कितने गरीब लोग रह गए जिनको गैस कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनके लिए गृहणी सुविधा योजना लाते हैं। अगर हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना लाते हैं, उसमें पांच लाख का कवर देते हैं तो प्रदेश के संवेदनशील मुख्य मंत्री को इस बात की चिंता हो जाती है कि इसके अलावा प्रदेश में कितने लोग छूट गए हैं। उनकी चिंता करते हैं और हिम केयर योजना लाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल यहां पर कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि इस बार 12 से 14 जुलाई तक इस प्रदेश के अंदर जन-जागरण का एक अभियान चलाया गया और तीन दिनों के अंदर वृक्षारोपण का 106 स्थानों में कार्यक्रम हुआ और 81 हजार लोगों ने उसमें भाग लिया तथा 18 लाख से अधिक पौधे तीन दिन के अंदर रोपे गए । इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन समृद्धि, जन समृद्धि योजना के तहत हमारे जंगलों में जड़ी-बूटियों को बचाने के लिए निजी जमीन के अंदर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए,

रोज़गार कैसे दिलाया जाए, उस नाते नई योजना की शुरूआत की गई। इसके साथ-साथ प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अभी विपक्ष के मेरे साथी हिमाचल प्रदेश सरकार की लोकप्रिय नीति अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती के बारे में कह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हुई हो। जिन-जिन स्कूलों में हम गए, कहीं भी पांच लाख देने

की बात नहीं हुई। लेकिन जब हम स्कूलों के अंदर जाते हैं, बच्चों के बीच में यह बात कहते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो । पढ़ाई करने के बाद जब आप ऑफिसर बनेंगे, जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे तो आपका नाम आपके विद्यालय के

6.2.2019/1450/av/dc/1

गौरव पट्ट पर लिखा जायेगा। इससे निश्चित तौर पर बच्चों को प्रेरणा मिलती है और उनका मनोबल बढ़ता है कि हमें जीवन में कुछ करना है। इस नाते जो लोकप्रिय योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई उसके लिए हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं। अपने आपको 6 बार का मुख्य मंत्री कहने वाले ---(व्यवधान)--- 6 बार के मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर कई वर्षों से लम्बित टोल टैक्स फ्री करने की मांग जिसके कारण बोर्डर एरिया के अंदर काफी ज्यादा समस्या थी; को पूरा नहीं कर सके। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने 6 महीने के अंदर ही टोल टैक्स फ्री करके दिखाया। हिमाचल के युवाओं की चिन्ता की गई और मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना लाई गई। आज बेरोजगार युवा अगर कुछ करना चाहता है तो उसको सब्सिडी पर लोन मिल रहा है। 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल खेती' योजना द्वारा यह संदेश दिया गया कि हमें इस प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती करनी है। किसानों-बागवानों की आय दोगुनी करनी के लिए किए गए प्रयासों हेतु भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री लगातार यह चिन्ता कर रहे हैं कि यह प्रदेश कैसे आगे बढ़े। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। यहां पर इलैक्ट्रिकल बसें खरीदने की बात हुई। पूर्व सरकार के समय में जो बसें 1.99 करोड़ रुपये में खरीदी गई वही हमारी सरकार के कार्यकाल में 76 लाख रुपये में खरीदी गई। कितना

बड़ा चेंज है ---(व्यवधान)--- मनरेगा के अंदर 600 करोड़ रुपये के काम तथा कई नई योजनाएं जैसे मोक्ष धाम, एम्बुलैंस रोड, पानी के 8-8, 10-10 हजार लीटर के बड़े-बड़े टैंक इत्यादि के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों को लग रहा है कि वास्तव में चिन्ता करने वाली यह सरकार जय राम ठाकुर की सरकार है। मेरे से पूर्व साथियों ने यहां पर हमारी सरकार द्वारा चलाई गई लोकप्रिय स्कीमों की काफी चर्चा की है। माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शौरी जी नये सदस्य हैं और हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन विधान सभा के अंदर कोई पोलिटिकल एजैंडा कैरी नहीं किया जा सकता। ये जो टी-शर्ट पहन कर आए हैं यह सदन की गरीमा के खिलाफ है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य श्री विनोद जी ने भी यही टी-शर्ट पहनी है और ये तो इस सदन के सीनियर सदस्य हैं। ---(व्यवधान)--- नहीं, आप यहां पर कोई राजनैतिक प्रचार नहीं कर सकते और यह आपका राजनैतिक एजैंडा है। ---(व्यवधान)--- आप अपना पोलिटिकल एजैंडा हाऊस के अंदर कैरी नहीं कर सकते। आप विधान सभा के अंदर से फोटो खींच कर फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं जो कि सदन की गरीमा के खिलाफ है।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर रखा और जिसका अनुसमर्थन श्री बलबीर जी ने किया, मैं भी उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं।

आपने अच्छा किया कि इस प्रस्ताव को कर्नल इन्द्र सिंह जी द्वारा मूव करवाया क्योंकि आपकी पार्टी के ये एक कर्मठ सदस्य तो हैं ही मगर शरीफ और नेक इनसान भी हैं। इनकी बात सुनना सभी को अच्छा लगता है तथा ये इंटैलीजैंट भी हैं। -(व्यवधान)---

06/02/2019/1455/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, राज्यपाल महोदय आदरणीय है, हमेशा होते हैं और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक सरकारी दस्तावेज़ होता है। जो कैबिनेट क्लीयर कर देती है, वह उसको यहां पढ़ देते हैं। मुझसे पहले नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने 29 स्कीमों का ज़िक्र किया जिनका ज़िक्र आपने अपने पहले बजट में किया था। यहां पर कुछ सदस्य नए हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन कुछ पुराने होकर भी नये ही बने हुए हैं। परन्तु आप लोग (सत्ता पक्ष)जो सामने बैठे हुए हैं, आप लोग तो पुराने हैं और आप लोग जानते हैं कि जो बजट होता है, उसी की उपलब्धियों का लेखा-जोखा आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देते हैं। हमारी यह आपत्ति है और रहेगी कि 30 स्कीमें आपने अपने पहले बजट में दी थी और उनमें से एक का भी ज़िक्र अभिभाषण में नहीं किया। मैं मान सकती हूॅ- जैसा यहां कुछ वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे कि स्कीमों को टेकऑफ करने में टाईम लगता है। मगर यदि आपने स्कीम फॉर्मूलेट की होती तो उसकी चर्चा तो यहां करते कि वह कहां तक पहुंची उसमें क्या प्रोग्रैस हुई? यहां पर बहुत सारी बातें हुई लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं उनको रिपिट नहीं करना चाहती। पिछले कल जो श्री मुकेश जी ने कहा और जो माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी इस सदन में पहली बार आए है, उन्होंने आज सारी स्कीमों का यहां पर विस्तृत लेखा-जोखा रखा है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट पर जाए तो इन्होंने कहा है कि हमने 'हिमाचल पुष्प क्रांति योजना' चालू की है। मैं जानना चाहती हूं कि ये क्रांति कहां हुई, कहां ये चालू हुई और कहां-कहां इस क्रांति योजना के बाद पुष्प पूरे हिमाचल प्रदेश में उगने शुरू हो गए? ये योजना अगर कहीं थी तो तीसा व बिलासपुर में थी और यह पहले से थी। आपने अगर उसमें एडिशनल किया है तो आप उसका ज़िक्र करते। आपने

सिर्फ ये ज़िक्र किया---(व्यवधान)--- मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ यह पूछ रही हूं कि अगर आपने कोई नई योजना चालू की है तो उसमें आपने कौन सा एरिया so called कहा है that through floriculture 25,268 square meters area will be brought under polyhouses. मैं यह जानना चाहती हूं कि ये पॉलीहाउसिज कहां लगे? इन पॉलीहाउसिज़ को कहां लगाने का प्रस्ताव है? जो पहले लगे हुए हैं, मैं उनका ज़िक्र नहीं करूंगी क्योंकि तीसा में एक revolutionary Idea flout हुआ और यह एक प्राइवेट को-ओपरेटिव सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है। उसके लिए सरकार समय-समय पर अनुदान भी देती रही है। ऐसी ही बिलासपुर में पालीहाउसिज़ लगे हुए है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

आपने कहा कि 25268 square meters area will be brought under polyhouses. आज फरवरी की 6 तारीख है, इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने के लिए पौने दो महीने रह गए हैं। ये जो 25268 वर्ग मीटर एरिया इसमें लाया जाएगा, वह कहां है? Where is it? It was for the current financial year. ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के आगे एक और ज़िक्र भी हुआ है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, यह भारत का एक बहुत बड़ा स्केम है और यह है फसल बीमा योजना। यह हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, मेरे भाई यहां पीछे बैठे हैं, he will agree with me और आप लोग भी एग्री करेंगे that this is a scam. आपने यह कहा कि 1,62,000 horticulturists have been covered under 'Weather Based Crop Insurance Scheme'.

06-02-2019/1500 /NS/AG/1

A sum of Rs. 18.86 crore has been defrayed as subsidy on a premium of 95.86 lac insured fruit plants. सरकार ने यह सबसिडी का अमाउंट दिया है। यह ठीक है। आप मुझे यह बताईए कि क्या किसी किसान को किसी फसल के नुकसान के लिए एक रुपया भी मिला है? This is a scam. यह बड़ी-बड़ी जो इश्योरैंस कंपनीज़ हैं उनको लाखों-करोड़ों रुपये दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। This is a national

scam and you are part of it. आपने गुडविल में किया होगा। लेकिन असलियत यह है कि हज़ारों-करोड़ों रुपये इश्योरैंस के नाम पर फार्मर इश्योरैंस के नाम पर एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर सैक्टर में दिए गए और फार्मर्ज़ को एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। I think the total amount in India is Rs. 65 crores. जोकि फसल बीमा का पूरे भारत में मिला है। कंपनीज़ को प्रीमियम दिया गया है it is over Rs. 50,000 crores. This is a scam. इसको आप देखें कि इस स्कीम से किसानों और बागवानों को कोई फायदा हुआ है। किसी को कुछ मिला भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गऊशालाओं की बात करते हैं। माननीय मंत्री जी आज यहां पर नहीं बैठे हैं। आपने देखा होगा, अभी जब बर्फ पड़ी तो लोगों ने सोश्ल मीडिया पर सैंकड़ो फोटोग्राफ्स डाल दिए, जिसमें हमारी गाय या स्ट्रे कैटल्ज़ सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं यह नहीं कहती कि आपकी मंशा नहीं है। लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर आपने कोई एक भी कदम उठाया है तो आप उसको उज़ागर करते कि other than नूरपुर में है माननीय सदस्य यहां से चले गए हैं। वहां पर एक गऊशाला है और शायद एक कहीं और जगह हो, जिसका मुझे नॉलेज नहीं है। मगर आपने कौन-सी नई गऊशालाएं बनाई जहां पर आपने स्ट्रे कैटल्ज़ को रखा हो। ---(व्यवधान)--- आपने कोटलाबोह में बनाई है। उसमें कितनी गऊएं हैं और अभी यह चल रही है। चलिए, आपने यह तो कहा कि यह गऊशाला चल रही है। आप यही इस दस्तावेज़ में बता देते। आपने ज़िक्र नहीं किया, मैं सिर्फ इस बात को कह रही हूं कि पूरे प्रदेश में आबारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं and that is a fact. कब से घूम रहा है, यह बिल्कुल सही बात है। यह आज की बात नहीं है। ठाकुर साहब, आप दूसरी बार सदन में आ गए और आपके पिता जी लंबे अर्से तक हमारे साथ थे। आप मेरी बात सुनिए। आपने यह लिखा है कि 'cow sanctuaries and big Go Sadans at District level are being established in the State'.
हम यह जानना चाहते हैं कि ये गऊशालाएं कहां एस्टेबलिश हुईं और किस स्टेज़ पर हैं? जब आप इनका ज़िक्र कर रहे हैं तो आप इसकी स्टेज़ भी बताईए। 'Are being established' is a vague term. It's a vague term. फिर वही बात आ गई, इतना लंबा क्या है? इसमें चार नाम ही तो लिखने थे, अगर आपने चार गऊशालाएं बनाई हैं। ...(interruption)... Narinderji, please don't disturb me. आप लोग महिलाओं के

पीछे क्यों उलझे हैं? हमारे माननीय मंत्री जी महिला मेयर के साथ ही उलझ गए। आप बताईए। आप लोग आजकल महिलाओं के साथ उलझने में ही व्यस्त हैं। माननीय मंत्री जी आप तो शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको पिछले 40-50 सालों से जानती हूं। आप शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आजकल यह समझ में नहीं आ रहा है कि एलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आ रहा है? आप हर बात पर गुस्सा हो रहे हैं। आप कॉलेज को ले करके, महिला मेयर को ले करके और एप्लीकेशन को ले करके गुस्सा हो रहे हैं। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं है। आप तो ऐसे न थे। Now I am coming back to this document.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब मत्स्य पालन की बात करना चाहूंगी। इस दस्तावेज़ में आपने ट्राउट फार्म की बात की है। मैं समझती हूं कि यह एक अच्छा कदम है अगर आप इसको करेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि हमारे चुराह क्षेत्र के भांदल में बहुत पुराना ट्राउट फार्म है जिसको रिजूवीनेट करने की जरुरत है। मेरी ऐसी उम्मीद रहेगी कि बाकी हिमाचल के साथ-साथ चंबा जिले के बारे में भी यह बात सोची जाएगी और जिला चंबा का नाम भी ट्राउट फिशिंग के लिए जाना जाएगा। वैसे भी चंबा में बहुत कोल्ड वाटर स्ट्रीम्ज़ हैं तो चंबा में इसको इंप्लीमैंट किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं। सही बात है, भरमौरी जी ने होली में बहुत अच्छा काम किया है।

06.02.2019/1505/RKS/DC-1

होली में ट्राउट फार्मिंग काफी सफल रही है मगर मैं चाहती हूं कि भांधल का बहुत पुराना ट्राउट फार्म जोकि स्यूल में है उसको रिजूवनेट करने के लिए इसमें शामिल किया जाए। मैं जनमंच की बात नहीं करना चाहती। लंचमंच पर पूरी चर्चा हो गई। मैं चाहूंगी कि आप और ज्यादा जनमंच करें। आप जितने ज्यादा जनमंच करेंगे उसका फायदा हमें ही होगा। ...(व्यवधान)... यह मेरी सोच है, सबकी सोच एक जैसी हो यह जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप जनमंच करें। दो-चार जगह और जाकर अधिकारियों को सस्पैंड करो। 10 जगह और जाओ क्योंकि यह लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। ...(व्यवधान)... We are all individuals. ...(व्यवधान)...जहां तक जनमंच का प्रश्न है यह कार्यक्रम किसी के फायदे

का नहीं है। पूरे महीने अधिकारी अपने कार्यालय को छोड़कर जनमंच, प्री जनमंच या पोस्ट जनमंच में लगे रहते हैं। जबकि अधिकारियों को अपना काम अपने दफ्तरों में बैठकर करना चाहिए। अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट या करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उन्हें कहा जाता है कि मंत्री जी आएंगे और यह सर्टिफिकेट आपको जनमंच में मिलेगा। उस बच्चे की एडमिशन कल होनी है और वह बच्चा रो रहा है लेकिन उसको जनमंच का इंतजार करना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं कि जिला का जनमंच उसके इलाके में हो। यह भी हो सकता है कि उस इलाके के व्यक्ति को भरमौर या तीसा जाना पड़े जहां अगला जनमंच होगा। मैं नहीं समझती कि this is a very good idea and I think आप जनमंच कीजिए मगर अधिकारियों को यह कहिए कि वे अपना रूटिन वर्क दफ्तर में बंद न करे। ...(व्यवधान)... रूटिन का काम बंद हो रहा है तभी हम कह रहे हैं। अगर किसी को पानी के नलके की जरूरत है और उसे यह कहा जाए कि आप जनमंच में आना, तो यह गलत है। ...(व्यवधान)... इस जनमंच का जो हश्र होगा यह आने वाला समय बताएगा।

अध्यक्ष महोदय, coming back to the serious issue of drugs, हिमाचल प्रदेश में पहले अफीम और चरस के केसिज पकड़े जाते थे। हिमाचल प्रदेश एक पैसेज स्टेट था, यह यूजर्स स्टेट नहीं था। लेकिन जब से पंजाब में सख्ती हुई है उसके बाद सिंथैटिक ड्रग्स में, जिसे हम चिट्टा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश एक यूजर्स स्टेट बन गया है। ड्रग्स यहां से पैडल की जा रही है, यह तो एक हिस्सा है लेकिन खतरनाक बात यह है कि इसको एक यूजर्स स्टेट बना दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद डॉक्टर हैं और आप इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ड्रग्स का एक्चुअल धंधा अफगानिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान से शुरू होते हुए यह हिन्दुस्तान में पहुंचता है जोकि हमारी जवानी को बरबाद करने के लिए 'lethal weapon' है। हिमाचल प्रदेश पहले यूजर्स स्टेट नहीं था। पहले यहां जम्मू-कश्मीर या तिब्बत की साइड से रास्ता था जो नीचे पंजाब या दिल्ली को जाता था। मगर अब यह यूजर्स स्टेट बन गया है। ऑवर डोज से यहां डैथ्स होने लगी हैं जोकि खतरनाक है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब सरकार कर रही है।

अगर आप हर चीज को इस तरह से लेंगे तो यह गलत बात है। काई भी सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी मगर इसको रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। ...(व्यवधान)... पंजाब में जब से सख्ती हुई है तब से यह यूजर्स स्टेट बना हुआ है। ...(व्यवधान)..

06.02.2019/1510/बी0एस0/डी0सी0-1

ये मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इन्हें कुछ नही कह सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा ड्रग्स का इश्यू है यह बहुत गंभीर मसला है। जैसा यहां पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा था कि to deal with this menace only Law is not enough. इस मेंनिस को डील करने के लिए हमको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे वरना जो पंजाब में पीछे हाल हुआ था ऐसा हाल कहीं यहां न हो जाए।

बेरोजगार युवाओं की जब बात आती है, यहां पर माननीय मुकेश जी ने बहुत सारी स्कीमों के नाम पढ़ कर सुनाएं हैं और आदरणीय आशीष बुटेल जी भी सुना रहे थे। आप सच्चाई को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। National statistical organization NSSO ने आंकड़े जारी किए हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेराजगारी अब हुई है और उसका भारत सरकार ने क्या संज्ञान लिया ? उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। एक और संस्थान को डिस्ट्रॉय किया गया। एन.एस.एस.ओ. के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया और मेम्बर ने भी इस्तीफा दे दिया। मगर सच्चाई यह है कि 6.2 प्रतिशत बेरोजगारी देश में बढ़ी है which is highest in 45 years. I request please don't destroy Institutions of the Country. Your Government has destroyed CBI, Election Commission, RBI etc.---(Interruption)--- आपने भारत सरकार का बार-बार जिक्र किया है यदि हम जिक्र करें तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। आपने लिखा ही ऐसा है । आपके नेता ही कहा करते थे कि जब-जब डॉलर के साथ रुपया गिरता है तो हिन्दुस्तान की साख गिरती है ।

अब तो इतनी गिर गई कि 72 रुपये डोलर पहुंच रहा है। अब तो साख, नाक सब गिर चुके हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आज हिन्दुस्तान की साख दुनिया में बढ़ी है।

श्रीमती आशा कुमारी : आपके लीडर जब विपक्ष में थे यह सब तब उन्होंने स्वयं कहा था। मैं कहना चाहती हूं कि जब आप विपक्ष में थे तो फैक्टर-2 की बड़ी लड़ाई लड़ते थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया समाप्त कीजिए। आप काम की बात पहले कीजिए दोस्ती की बात बाद में करते रहना।

श्रीमती आशा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू ही हुआ है। कृपया मुझे चम्बा की बात करने दीजिए। मैं जिला चम्बा से अकेली ही हूं और मैं नैशलन हाइवे की बात करना चाहती हूं। यहां पर माननीय मुकेश जी ने नैशलन हाइवे का जिक्र किया इस संबंध में बहुत सारी बात हो चुकी है। परंतु फैक्टर-2 के बारे में विपक्ष में रह करके बात करते थे । उस वक्त जो आपने फैक्टर-2 के लिए लड़ाई लड़ी यदि उसका 100वां हिस्सा पक्ष में रह कर भी लड़ सकते थे। अब फैक्टर-2 कहां गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा नैशनल हाइवे जो चम्बा के लिए अनाऊंस हुआ था, उसका क्या हुआ? जो संयुथा से होते हुए, चम्बा से होते हुए, पांगी जाना था। उसका कोई भी जिक्र नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय सीमेंट प्लॉट के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। चम्बा के सीमेंट प्लांट का जिक्र सुबह भी प्रश्न काल में हुआ था। माननीय मंत्री जी का जवाब अभी भी मेरे सामने यहा पर है । जिसमें इन्होंने कहा कि खनन पट्टा अधिग्रहण की प्रक्रिया तब की जाएगी जब बिड हो जाएगी। अब मुर्गी पहले आएगी या ऑमलेट पहले बनेगा? वह कहते हैं कि सड़क नहीं है इसलिए हम बिड नहीं करेंगे आप करते हैं कि पहले वे बिड करेंगे तो हम सड़क बनाएंगे। आप सड़क बनाने की कम से कम प्रक्रिया तो आरंभ कीजिए। सड़क कहां से बननी है उसकी डी.पी.आर.कब बनेगी? उसमें किसकी लैंड जानी है ? उसे

एक्वायर करने की बात कीजिए, फोरेस्ट कलियरेंस लेने की बात कीजिए । आपको आज नहीं कल सड़क तो बनानी ही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीमेंट फैक्ट्री का बहुत पुराना इतिहास है। यह पहले Larsen & Tubro Limited को मिला था। Larsen & Tubro Limited ने इसे नहीं लगाया। माननीय धूमल जी की सरकार ने उसे रद्द करके जे.पी. इंडस्ट्री को दिया था उन्होंने भी नहीं लगाया और वे कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए तो उन्हें स्टे नहीं मिला और उसी दौरान भारत सरकार भी दूसरी आ गई जो वर्तमान में केन्द्र में सरकार है। उन्होंने माईनिंग नीति को बदल दिया है । गलोबल टैंडर इसके लिए मंगवा लिए हैं। अब गलोबल टैंडर की शर्तें ऐसी हैं कि कोई भी ऐजेंसी इस प्लांट को नहीं लगाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसे गंभीरता से लें। ये जिला चम्बा से जुड़ा हुआ इश्यू है।

06.02.2019/1515/DT/HK-1

'आया लोक सभा आई सिकरी धार', वह व्यक्ति इस माननीय सदन में नही है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि चुनाव फलां ने लड़ना है। यह बात क्यों जूड़ रही है जब लोक सभा का चुनाव आता है तो क्यों आप इस बात को लेकर आते हैं। आप इसका सरलीकरण क्यो नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं इसको लगाने के बारे में सिरियस है ? आपने इसी सदन में कहा था कि आशा कुमारी जी अक्तूबर के महीने में यह होगा। अक्तूबर तो निकल गया पर शुक्र है आपने 2018 नहीं बोला। कौन-सा अक्तूबर, कब आएगा यह अक्तूबर? ...(व्यवधान) इग्जैक्टिली वर्ष 2022 के बाद आएगा।

अध्यक्ष महोदय, दो बातें बहुत ही जरूरी है जिनमें से एक मैडिकल कॉलेज चम्बा को लेकर है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है। मैडिकल कॉलेज चम्बा जिसमें पूरे डॉक्टर्ज थे वहां का प्रिंसिपल चेंज किया गया है और जो नया प्रिंसिपल लगाया उसने इस्तीफा दे रखा है। जो डॉक्टर्ज हैं वे सब छोड़ कर चले गए हैं। बच्चो का भविष्य अधर में हैं और वहां के बच्चों ने लिख के भी दिया है कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, हमें यहां से शिफ्ट

कर दिया जाए। आपने यह नोबत क्यों आने दी? आप मैडिकल फैसलिटी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हम मुख्यमत्री जी का धन्यावद करेंगे उन्होंने तीसा में एक सौ बिस्तरीय होस्पीटल किया है। मगर आपको यह भी पता होन चाहिए तीसा में जो प्रेजैंट 50 बिस्तर का हॉस्पिटल है उसमें एक ही डॉक्टर है। पहले आप डॉक्टर बढ़ाइए उसके बाद विस्तर तो बढ़ाते रहिए।

अध्यक्ष महोदय, धार्मिक पर्यटन के लिए आपने सौ करोड़ जारी करने के लिए कहा है। क्या इस धार्मिक पर्यटन में कहीं चम्बा का भी नाम आएगा। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि चम्बा में बनीखेत भी एक पर्यटन स्थल है। खास करके विश्व मैप में डलहौजी पर्यटन के लिए जाना जाता है। बनीखेत जहां से डलहौजी को जाते है वहां टूरिज्म का बोर्ड लगा है की जंजहैली में आइए। जंजहैली लोग जरूर जाएं कोई मनाही नहीं है पर चम्बा में जंजहैली का बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? चम्बा में तो चम्बा का बोर्ड लग जाए। ...(व्यवधान)... आप यह समझते हैं की मैं टूरिज्म मंत्री हूं तो मैं यह बात मान लेती हूं। यह सरकार का बोर्ड लगा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है की चम्बा जिला को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने से यह सीमेंट प्लांट लगने वाला नही है। मगर आप टूरिज्म को बढ़ाव देंगे, अगर आप पदरी को बढ़ाव देगे, आप भांदल किहार हो बढ़ावा देंगे, वेरागढ़ को बढ़ावा देंगे, पांगी, भरमौर को बढ़ाव देगे तो चम्बा जिला को इनडायरैक्टट इम्प्लॉयमैंट जरूर मिल सकती है। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि आप ब्रिक्स में चम्बा जिला के लिए कुछ रखिए। चम्बा जिला में पीछे एक वाटर गार्ड के इन्टरव्यू हुए थें और हमे यह बताया गया की पूरे प्रदेश में जो वाटर गार्ड के इन्टरव्यू हुए थे वह पांच सौ पोस्टें धर्मपुर से ही भर दी गई। अगर यह सच्चाई है तो यह दुख की बात है और आप इसके बारे में कोरेकशन करे या इसके बारे में अपना वकत्व्य दें। जिन-जिन सब-डिविजन में वाटर गार्ड के इन्टरव्यू हुए थे उनके रिजल्ट निकले या नहीं निकले और उनका क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे समय दिया में अपका धन्यावद करना चाहती हूं। मगर एक बात में

आपको बता दूं की जो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने किसानों को 6 हजार रूपये दे दिए उनका धन्यावद करो। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का धन्यवाद करो जिन लोगो ने आपको आइना दिखा दिया। 11 दिसम्बर के बाद जितनी भी स्कीमें आप लोगो ने दिल्ली में अनाउंस की है यह सब डर के की है। जो 17 रूपये रोज देने का वायदा किया है वह अपने डर के किया है। आपको तीनों प्रदेशों ने आईना दिखाया है मई का महीना आने दो मई की गर्मी में आपको पूरी तपीश लगने वाली है और मई में आपको पूरा आईना दिख जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यावद। राज्यपाल महोदय का हम बहुत मान सम्मान करते हैं। माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी का भी बहुत सम्मान करते हैं और बलबीर जी का भी परंतु इस दस्तावेज का समर्थन करने में हम असमर्थ है। अपका बहुत-बहुत धन्यावाद

06-02-2019/1520/एच.के./एन.जी./1

अध्यक्ष : अगले वक्ता श्री राकेश जमवाल जी ।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए मैं यहां पर खडा हुआ हूं । पिछले कल से लगातार यहां पर सभी सदस्यों के विचार सुनने को मिले । इस माननीय सदन में बहुत से नए विधायक चुन कर आए हैं और नए विधायकों को पुराने वरिष्ठ लोगों से बहुत सी चीजें सिखने को मिलती हैं और मिलनी भी चाहिए । हम देख रहे हैं कि आदरणीय श्रीमती आशा कुमारी जी, पीएसी की चेयरपर्सन है और वहां पर मैं मैम्बर हूं और बहुत सी चीजें इनके साथ वहां पर मुझे सीखने को मिलती है । आज इन्होनें कहा कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसी भी स्कीम का जिक्र नहीं है । बडे दुःख की बात है कि इन्होंने या तो सुना नहीं या इस अभिभाण को पूरी तरह से पढा नहीं । सरकार की अनेकों योजनाओं का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है । कल से विपक्ष के हमारे मित्र व बहुत से अन्य वरिष्ठ लोगों ने भी अनेकों बाते यहां पर कही । आदरणीय मुकेश जी ने एन.एच. का जिक्र बहुत ही जोरों से यहां पर किया । केन्द्र सरकार द्वारा जब एन.एच. की सैद्धान्तिक मंजूरी हुई उस समय हिमाचल प्रदेश में सरकार आपकी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ।

लेकिन दो वर्ष तक उस समय की हिमाचल प्रदेश की आपकी सरकार उनकी डीपीआर तक भी नहीं बना पाई । हिमाचल सरकार ने इतना तक कह दिया की हमारे पास डीपीआर बनाने के भी पैसे नहीं है । मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का, केन्द्रीय मन्त्री श्री नितिन गडकरी जी का की जिन्होंने डीपीआर बनाने के लिए भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को डीपीआर बनाने के लिए भी पैसा दिया । हम किन बातों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, सरकार की नीयत उसकी नीतियों से पता चलती है । हिमाचल प्रदेश में जैसे ही श्री जय राम ठाकुर जी ने सत्ता सम्भाली आते ही पहला निर्णय जो लिया उसी से इस सरकार की नीयत पता चलती है । अनेकों प्रदेशों में सरकारे बनती है और उन सरकारों के बनने के बाद कया निर्णय लिए जाते हैं यह हम सब को मालूम है । अभी आप तीन प्रदेशों का जिक्र कर रहे थे वहां पर भी कैसे निर्णय लिए गए हैं यह आप भलिभान्ति जानते हैं । पिछली सरकार की कृतियों को, पुरानी सरकार के लिए गए निर्णय को

अध्यक्ष : प्लीज बीच में मत बोलिए ।

श्री राकेश जम्वाल : और उनकी जांच की जाती है तो मालूम पडता है कि बदला-बदली की भावना से काम किया जाता रहा है । लेकिन हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के गठन के बाद जो पहला निर्णय लिया गया वो प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन में आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर सीधा 70 वर्ष कर दिया गया है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमन्त्री जी का धन्यवाद करते हैं । माननीय विपक्ष के सदस्यों का तो इसमें सुझाव आना चाहिए था न कि आलोचना की जानी चाहिए थी । अभी से आपके दृष्टी पत्र में लिख गया है कि आयु 60 वर्ष की जाएगी । आपको बताना चाहूंगा की प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार पांच वर्ष के लिए बनाई है और अभी तो केवल एक ही वर्ष हुआ है और एक वर्ष में ही सीधे 10 वर्ष आयु सीमा कम कर दी गई है । इस निणर्य पर आपको माननीय मुख्यमन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था और अगर आपको लगता है कि इस निर्णय में कोई सुझाव देने चाहिए थे तो उन्हें देना चाहिए था न की इसकी आलोचना करनी चाहिए थी । पिछले कल अनेकों प्रकार की चर्चा इस माननीय सदन में की गई और यहां कहा गया कि केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं दिया।

06/02/2019/1525/RG/YK/1

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने अनेकों Mother Care Health Centres दिए थे, लेकिन इनकी उस समय की सरकार उसमें एक पत्थर तक नहीं लगा सकी। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र सुन्दरनगर में भी 12 करोड़ रुपये की लागत से माननीय श्री नड्डा जी ने मातृ शिशु अस्पताल दिया, लेकिन आपकी सरकार उसमें दो वर्ष तक एक पत्थर भी नहीं लगा सकी। हां, एक काम जरूर किया कि जाते-जाते उसका शिलान्यास शिमला से बटन दबाकर सुन्दरनगर में कर दिया। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब हम आए, हमने सोचा कि उसका शिलान्यास तो हो गया और अब काम भी शुरू हो गया होगा। जब हमने उसकी सारी जानकारी ली तो पता चला कि जिस साईट पर वह एम.सी.एच. बनना है, उस साईट को भी क्लीयर नहीं किया गया, वहां से सिवरेज लाईन को शिफ्ट करना था, वहां पेड़ कटने थे, बिजली की तारें हटाई जानी थीं और यहां तक कि उसका टैण्डर तक नहीं हुआ था। लेकिन मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आते ही विभाग को आदेश दिए और आज वहां एम.सी.एच. का काम चला है। एम.सी.एच. भवन के तीन लैन्टर भी पड़ गए हैं और एक साल में उसको तैयार करके हम जनता को समर्पित करेंगे। आज जय राम ठाकुर जी की सरकार इस प्रकार के विकास के कार्य कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर्यटन को लेकर भी अनेकों बातें कही गईं। लेकिन जय राम ठाकुर जी की सरकार पर्यटन के प्रति किस प्रकार से गंभीर है कि मुख्य मंत्री जी ने आते ही 6 विधायकों की एक कमेटी को सिक्किम भेजा जिसमें विपक्ष के भी दो माननीय विधायक हमारे साथ थे और एक निर्दलीय विधायक श्री होशयार सिंह जी हमारे साथ थे। वहां हम गए और पर्यटन को लेकर उस प्रदेश में जो-जो हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट बनाकर हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को सौंपी। उसके बाद उस पर अमल भी हुआ है जिसके परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार पर्यटन के लिए कुछ नहीं कर रही है और हमारे समय में पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। हम जानते हैं कि मेरे सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार वर्ष 2007

से 2012 तक प्रदेश में सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुन्दरनगर में एक टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेन्टर, एक रेस्टोरेंट और दो स्यूट वहां बनाए। वे बनकर तैयार हो गए और जब वर्ष 2012 में इनकी सरकार आ गई, तो इन्होंने पांच वर्षों तक उस टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेन्टर और रेस्टोरेंट को नहीं चलाया। वहां ए.डी.बी. का कार्यालय पांच साल तक चलता रहा। इस प्रकार से आप पर्यटन को बढ़ावा देते रहे हैं। लेकिन आज उस कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर्यटकों और जनता के लिए टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेन्टर, रेस्टोरेंट और होटल के दो कमरों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस सुन्दरनगर वाले टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेन्टर, रेस्टोरेंट और होटल को भी जल्दी चला दिया जाएगा। इसके साथ-साथ अन्य बातें भी यहां कही गईं। श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी कहा कि चम्बा में भी जंजहैली का बोर्ड लगा है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि मण्डी में चम्बा के बोर्ड लग जाएं और चम्बा में जंजहैली का बोर्ड लग जाए, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यदि चम्बा में बहुत कुछ अच्छा है, उसको हम मण्डी और सुन्दरनगर में भी प्रचारित करें और उसके बोर्ड लगें। इसी प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से यदि मण्डी या जंजहैली में कुछ अच्छा है, उसके बोर्ड यदि चम्बा में भी लगें तो उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कल से हम यहां सुन रहे थे कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं दीं। मुझे बहुत दुख होता है कि वर्ष 2012 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस समय इन्होंने प्रदेश के युवाओं से क्या वायदा किया था कि हम हर पढ़े-लिखे बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। पांच वर्ष तक हम उन बेरोजगारों को ढूंढते रहे जिनको इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो, लेकिन हमें कोई बेरोजगार ऐसा नहीं मिला जिसको इनकी उस समय की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया हो। लेकिन वर्तमान की हमारी सरकार, सरकारी नौकरियों की जहां तक इन्होंने बात कही, हर दस दिन में सलैक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं और लगातार विभिन्न विभागों में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने कुछ विषयों पर चर्चा की। हम उनकी पीड़ा को भी समझते हैं। उन्होंने यहां कहा कि हम सब लोगों को मिलकर इस विधायक इन्स्टीटियुशन को मजबूत करना चाहिए। यह

बात सत्य है कि हम सदन में नए हैं। लेकिन इसी सदन में क्या होता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है।

06/02/2019/1530/MS/YK/1

चुने हुए विधायकों को यहां पर सरकारी गुण्डा कहा जाता है, टोंडे और मकड़झण्डु कहा जाता है लेकिन हम इस सदन के नेता मान्यवर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, कोई बता दें कि इन्होंने किसी प्रकार की अभद्र भाषा का कभी प्रयोग किया हो। यह इस बात का परिचय है कि वे इस विधायक के संस्थान को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे विपक्ष के मित्र हम पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि जो पिछले कल भूकम्प आया, उसके लिए आप कहेंगे कि इस भूकम्प के लिए भी आदरणीय जय राम ठाकुर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कांग्रेस मुख्यालय में आपके दो गुट आपस में लड़ते हैं और अगले दिन बयान आता है कि यह भी भारतीय जनता पार्टी की टीम की शरारत है। अगर इस प्रकार की बातें हमारे वरिष्ठ साथी लोग कहेंगे तो हम नये लोग इस सदन में क्या सीखेंगे?

यहां पर कानून-व्यवस्था की भी बात की गई कि हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। यह बात सत्य है कि यदि कोई रेप या मर्डर होता है तो उसके पीछे किसी सरकार की मंशा नहीं होती है लेकिन सरकार उसमें क्या कदम उठाती है, वह मायने रखता है। आपकी सरकार के समय गुड़िया की हत्या हुई और उस केस की जांच कर रही पुलिस की सारी टीम आज सलाखों के पीछे है। प्रदेश में निश्चित तौर पर घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम उस बात को स्वीकार करते हैं लेकिन सरकार की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। दोषी को सजा देने के लिए सरकार सख्ती से कदम उठाती है और पुलिस विभाग भी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है। आदरणीय राकेश सिंघा जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने तो कल पुलिस के लोग और अन्य लोग जो इस केस में जेल के अंदर हैं, उन सबको सर्टिफिकेट दे दिए कि सब बरी होने चाहिए क्योंकि ये सब लोग उस केस में दोषी नहीं हैं।

आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार आज हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता को कहीं पर

कोई दिक्कत आएगी या कोई अधिकारी/कर्मचारी गलत करेगा और उनके खिलाफ यदि कोई ऐक्शन लिया जाता है तो उसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

यहां पर जनमंच की बार-बार चर्चा हुई। मुझे लगता है कि अगर आप जनमंच का ज्यादा विरोध करेंगे तो जब आप गांव में जाएंगे, वहां आपको कांग्रेस के ही लोग कोसेंगे और कहेंगे कि जनमंच एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम अपने काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करवा रहे हैं। एक सबसे बड़ी योजना जो इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश की मातृशक्ति के लिए लाई है वह "उज्ज्वला योजना" है। आज से पहले भी प्रदेश में सरकारें रही हैं लेकिन किसी के मन में यह सोच नहीं आई कि हमारी मां/बहनें गांव में किस प्रकार से चूल्हा जलाकर परिवार के लिए भोजन बनाती हैं। चूल्हे में भोजन पकाते हुए उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और उन्हें सांस की बीमारी हो जाती है। उस योजना के बाद भी जो लोग बच गए उनको हिमाचल प्रदेश की जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" शुरु की। मैं 3 तारीख को अपने विधान सभा क्षेत्र के डैहर नामक स्थान पर जहां गैस वितरण का कार्यक्रम था, वहां गया था। मैंने वहां अपनी माताओं/बहनों से पूछा कि मैं बड़े खुले मन से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर कांग्रेस परिवारों की भी महिलाएं आई हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं कांग्रेस परिवारों से आई हुई थीं और उन्होंने कहा कि आज तक किसी सरकार ने माताओं/बहनों की पीड़ा को नहीं समझा कि किस प्रकार हम घरों में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मेहनत करती हैं। यह सोच अगर किसी के मन में आ सकती है तो गरीब व्यक्ति के मन में आ सकती है जिसने वह पीड़ा देखी हो और जिसको पता है कि गांव में हमारी मां/बहनें किस प्रकार से खाना बनाती हैं। हम उस योजना को लाए हैं और उस योजना की तारीफ होनी चाहिए। उसमें यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हैं तो बताइए ताकि सरकार उसमें कुछ और सुधार कर सके। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि ये दोनों योजनाएं आज तब आ पाई क्योंकि आजादी के बाद जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने गैस बनाने के लिए प्लांट लगाए थे इसलिए आज आप गैस बांट रहे हैं। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। हम यह नहीं कहते कि जब आपकी सरकार थी, तब विकास नहीं हुआ। देश में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं

लेकिन वर्तमान में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक वर्ष में जो काम किए हैं, वे देश और प्रदेश के इतिहास में आज तक की किसी सरकार ने नहीं किए हैं।

06.02.2019/1535/जेके/वाईके/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात न करता हुआ आज आपने मुझे महा-महिम् राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोलने का मौका दिया। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से मुख्य मंत्री जी चले गए तो अब यहां पर न चीफ सैक्रेटरी है, न कोई अडिशनल चीफ सैक्रेटरीज़ हैं, न कोई प्रिंसिपल सैक्रेटरीज़ हैं और न ही सैक्रेटरीज़ हैं। यहां पर चर्चा चल रही है। गवर्नमैंट इतनी नॉन सीरियस हो गई । यहां पर 5-6 मंत्री बैठे हैं और पूरा हाउस चल रहा है। यह क्या स्थिति है? ब्यूरोक्रेसी ने पूरी अराजकता फैला दी है। ...(व्यवधान)... आप खुद देखो। यहां पर एक भी ऑफिसर नहीं है। इतनी लम्बी-चौड़ी ब्यूरोक्रेसी आपने रखी है। ...(व्यवधान)... यह जरूरी है। इसको आप लाइटली मत लीजिए। यह हाउस की अवमानना है कि इस सरकार के ऑफिसर यहां पर नहीं बैठे हैं।

अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी आपने कुछ बोलना है?

संसदीय कार्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने अधिकारियों के बारे में प्रश्न उठाया, सामान्य चर्चा में वह चाहे बजट की चर्चा हो या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा हो, उसमें सबके नोट्स यहां पर लिए जाते हैं। नोट्स लेने वाले यहां पर भी बैठे हैं और सारे परिसर में अलग-अलग स्थानों में भी बैठे रहते हैं। सभी ऑफिसर्ज़ के जो कन्संर्ड हैं ...(व्यवधान)... सारी की सारी गैलरी ...(व्यवधान)... हम भी इतने अर्से तक रहे हैं। हमने कभी यह मैटर उठाया नहीं। ...(व्यवधान)... हाउस की मर्यादा में

...(व्यवधान)... ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सारे-के-सारे हर टाइम बैठे रहेंगे । जिनको बैठना है वे बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी, प्लीज बैठिए।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी देखा है और इससे पिछले पांच वर्ष भी देखे हैं । तब तो यहां पर नोट करने वाले भी नहीं होते थे। आप यहां पर बैठते थे और आप भी नहीं बोलते थे। ...(व्यवधान)... मैं किसी को डिफैंड नहीं कर रहा हूं। आप अनावश्यक ही कह रहे हैं। यहां पर कुछ ऑफिसर जो बैठने चाहिए, वे आएंगे। वे अपने दफ्तर में बैठे होते हैं।

अध्यक्षः अगले वक्ता श्री राजेन्द्र राणा जी। राजेन्द्र राण जी एक मिनट बैठिए। पहले राकेश सिंघा जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी ने जब अपनी बात इस सदन में रखी, इन्होंने मुझे कोट किया लेकिन मिस-कोट किया। मैंने हरगिज़ यह नहीं कहा कि सारे-के-सारे पुलिस के ऑफिसर जो अन्दर हैं, वे दोषी नहीं हैं। वे बिल्कुल नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं। गुड़िया मर्डर केस में आज मैं खुल कर बोल रहा हूं कि कुछ इनोसैंट ऑफिसर्ज़ अन्दर हैं। मैजोरिटी में जरूर दोषी होंगे। लेकिन मुझे इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। यह मैटर सब-ज्युडिस है। अभी यह मामला कोर्ट के सामने है इसलिए उचित नहीं होगा कि यहां पर मैं चर्चा करूं लेकिन मुझे मिस कोट न करें क्योंकि मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कि किस-किस ने क्या-क्या किया है? इसलिए ज्यादा न कहूं तो बेहतर रहेगा।

अध्यक्षः अब श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर): माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपने समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उस तरफ बैठे दोस्तों ने अपनी सरकार की पीठ खूब थप-थपाई है। यहां पर जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई है और महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण में कहा है वह सरकार ने जो लिख करके दिया है और सरकार की जो एक साल की रिपोर्ट है कि सरकार ने एक साल में क्या किया, वह सारी रिपोर्ट इसमें पेश की गई है। मुझे लगता है कि पिछला जो बजट पेश हुआ था और उस बजट में जो-जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वायदे किए गए थे, कमिटमैंट्स की गई थी, उनमें से बहुत कुछ नज़र नहीं आया है।

06-02-2019/1540/SS-AG/1

श्री राजेन्द्र राणा क्रमागतः

यहां पर नौजवानों की बात चल रही थी तो मुझे लगता है कि इस सारे अभिभाषण में नौजवानों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। आज के इस दौर में किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों की बेरोज़गारी का मसला है। सरकार उस दिशा में क्या करने जा रही है उस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए थी कि सरकार का नौजवानों को लेकर क्या दृष्टिकोण है। अभी हमारे दोस्त चर्चा कर रहे थे कि पब्लिक सर्विस कमीशन/सबोर्डिनेट सर्विस सिलैक्शन बोर्ड से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार में पांच सालों में जितने नौजवानों को रोज़गार दिए गए, मुझे लगता है कि वह पिछले 70 वर्ष में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। यह ठीक है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। सरकारों का दायित्व बनता है कि वे काम करें। कई बार चर्चा करते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। उन्होंने लोक सभा में कहा था कि यह कहना गलत है कि पिछले 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। हमें यह कहना चाहिए कि 60 सालों में हम यहां पहुंच गए और अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों में

सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। परन्तु प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि आप और बढ़िया काम करें। अब चुनाव भी आने वाले हैं। यहां चर्चा राजनीतिक भी हो रही थी। अब आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि आप लोग भी चुनावों में जाने वाले हैं। जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि आपने लोगों के साथ क्या-क्या वायदे किये हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ तो आपकी ही पार्टी के लोगों ने वायदा किया कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। अब आंकड़ें क्या आ रहे हैं! यह बहुत बड़ा बारूद का ढेर खड़ा हो गया है और अब आने वाले चुनावों में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आपने चुनावों में कहा कि आप 15 लाख रुपया लोगों के खातों में डालेंगे, वे 15 लाख रुपये नहीं मिले। आपने कहा कि ब्लैक मनी वापिस लेकर आयेंगे, ब्लैक मनी वापिस नहीं आई। आपने कहा कि हमें सत्ता सम्भालो तो हम 90 दिन के अंदर-अंदर महंगाई को खूंटे के साथ बांध कर रख देंगे, लेकिन वह नहीं बंधी। पैट्रोल/डीजल के दाम कहां पहुंच गए! जो 390 रुपये में गैस का सिलेण्डर मिलता था, वह आज एक हजार रुपये के पार हो गया। आपको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... सबसिडी पता नहीं कब आती है और कब मिलेगी। जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता स्वयं बताती है कि क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति को पहले 390 रुपये में सिलेण्डर मिलता था, आज वह एक हजार रुपये से ऊपर मिल रहा है। ...(व्यवधान)... 1500 रुपये का नहीं मिलता, उसके बारे में लोग जानते हैं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है।

आप किसानों की बात कर रहे थे। किसानों के लिए इस अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है कि आपने उनके लिए क्या किया। अभी केन्द्र सरकार ने कहा है कि 6000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिया जायेगा, जिनके पास दो हैक्टेयर से कम जमीन है। इस पर बड़ी चर्चा हुई कि आप रोज़ाना 17 रुपये एक किसान को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस दौर में 17 रुपये रोज़ाना किसी किसान को देंगे तो वह अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है।

इसमें सड़कों की चर्चा नहीं है। आज प्रदेश में सड़कों की हालत क्या है! पीछे धर्मशाला में जो सैशन हुआ, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि शिमला-धर्मशाला सड़क को तुरन्त ठीक कर देंगे, इसका टैंडर हो गया है। अभी भी उस सड़क की हालत क्या है? अगर आप उस सड़क पर ट्रैबल करें और आप लोग भी अमूमन

इस सड़क से जाते हैं तो जिसको डिस्क प्रॉब्लम न हो, उसको भी डिस्क प्रॉब्लम हो जायेगी। आपकी सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है।

इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस माननीय सदन में चर्चा हो ही रही है। इस प्रकार बहुत सारे इश्युज़ हैं जिन पर सरकार को गौर फरमानी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सुजानपुर की बात कर रहा हूं।

6.2.2019/1545/केएस/डीसी/1

अगर सरकार यह बता दें कि सुजानपुर में एक रुपया भी सरकार ने खर्चा है तो मैं यहां उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। सरकार एक रुपये का काम भी बता दे। तो जो आप समानांतर विकास की बात कर रहे हैं, वह कहां हो रहा है? दूसरे, एम.एल.ए. हैड से जितना पैसा दिया गया, पी.डब्ल्यूडी. विभाग उसको खर्च नहीं कर रहा है। बी.डी.ओ. खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार के कोई ऐसे आदेश हैं कि जो एम.एल.ए. हैड से पैसा दिया जाता है, उसको आप खर्च न करें? पिछली सरकार के समय जो पैसा दिया गया, वहां पर टाउन हॉल के लिए सितम्बर, 2017 में 75 लाख रुपये की किश्त जारी की गई, शिलान्यास किया गया और इस सरकार ने उस पैसे को कहीं नहीं खर्चा । कहते हैं कि जमीन नहीं मिल रही है। अरे, जमीन क्यों नहीं मिल रही है। जहां पर शिलान्यास किया गया, वहां पर जमीन है। ये कहते हैं कि यह जमीन तो ग्राउंड के नाम है तो वहां साथ में जो इससे पहले भवन बने हैं, वे कैसे बन गए? ये काम ही नहीं करना चाहते। वहां पर सिविल हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया गया। बजट प्रोविज़न भी था। वैटरिनरी हॉस्पिटल के लिए बजटरी प्रोविज़न था लेकिन कोई काम नहीं किया गया। बाकी जो छोटे-मोटे काम लगे हुए थे, वे भी ठंडे बस्ते में डाले गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कहा कि प्रदेश में जहां-जहां शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं, उनको दोबारा लगाया जाएगा। मैंने धर्मशाला में सत्र के दौरान फिर से यह प्रश्न किया तो

कहा गया कि एक महीने के अंदर लगा देंगे। अब ये बताएं कि मुख्य मंत्री के आदेश को भी सरकारी अधिकारी न मानें तो हम क्या कहें कि मुख्य मंत्री की बात मानी जा रही है? वहां पर चार शिलान्यास तोड़े गए हैं । उनमें से दो लगाए गए हैं दो बाकी हैं। एक इलैक्ट्रिसिटी का है। औंसला जगह पर 33 के.वी. सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया और एक सड़क का उद्घाटन किया गया उनके दोनों के फाउंडेशन स्टोन तोड़े गए हैं जिनको अभी तक नहीं लगाया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जनमंच के बारे में यहां पर बड़ी चर्चा हुई। अगर जनमंच में जा कर सिर्फ म्यूटेशन की बात करनी है, लोगों को इंतकाल का प्रमाणपत्र देने की बात करनी है तोजनमंच का फायदा क्या है? यहां पर सत्ता पक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि जनमंच में कांग्रेस के लोगों के बड़े काम हो रहे हैं। हमने भी जनमंच देखे हैं, हमने भी पता किया है । जब कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां जाता है तो साथ में बैठे हुए लोग कान में कहते हैं कि जनाब यह तो दूसरी पार्टी का है, जरा ध्यान से करना और ऐसा होता है। चलो, यह तो सरकार का अपना प्रैरोगेटिव है कि कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं परन्तु जनमंच में अगर ऑफिसरों को डांटना ही है और म्युटेशन के या अन्य सर्टिफिकेट ही देने हैं तो मुझे नहीं लगता कि जनमंच का फायदा हो रहा है। किसी की कोई तार टूट गई है, किसी का पोल लगना है। ऐसे छोटे-छोटे काम के लिए तो अधिकारियों को डायरैक्शन्ज़ दी जा सकती हैं कि ऑफिस में बैठ कर लोगों के काम करो।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने चुनाव से पहले दृष्टिपत्र बनाया। आपका जो दृष्टिपत्र है, जिसको पहले घोषणा पत्र कहते थे, उसमें से कितने काम हो गए? कितनी कमिटमैंट्स आपकी थी, कितनी इम्पलिमेंटेशन हुई? मुझे लगता है कि उस दृष्टिपत्र पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसके अलावा यहां पर चर्चा की गई कि कांग्रेस के ऑफिस में बड़ी लड़ाई हुई। यह ठीक है कि लड़ाई हुई। नौजवानों के दो ग्रुप थे। वे आपस में लड़े लेकिन यह पहली बार तो नहीं है। वर्ष 1997 में ज्वालाजी में जो लड़ाई हुई थी, उसको शायद आप भूल गए । वह तो बड़े लोगों में हुई थी और किस तरह हुई थी? इसके अलावा आपकी पार्टी के तो जनता द्वारा चुने हुए लोग अभी हफ्ता पहले ही आपस में लड़

रहे थे। नगर निगम शिमला में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही लड़ाई हो रही है। आपकी पार्टी के लोगों में भी हो रही है। आपके तो चुने हुए लोग लड़ रहे हैं। कहते हैं कि-

न भूल सियासत की कलगियां,
सुजानपुर के सज्जनों का कर्जदार हूं।

6.2.2019/1550/av/dc/1

अगर सुजानपुर के सज्जन न होते, तो फिर हम यहां न होते।
पर यह भी तय है कि अगर हम यहां न होते, तो वहां कुछ और ही होते।

---(व्यवधान)--- कोई बात नहीं, मैं जहां पर हूं बहुत अच्छा हूं।

यहां पर हमारे साथियों ने बहुत सारी चर्चा की हैं। प्रदेश में जो नशे के बारे में आंकड़े सामने आ रहे हैं मुझे लगता है कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है। यह केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं है बल्कि विपक्ष के लोगों को भी साथ मिल कर इस पर काम करना चाहिए। पिछले 365 दिनों में 1342 मामले नशे के दर्ज हुए हैं जो कि हमारे प्रदेश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है इसलिए सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई जबकि इसके कारण पिछले एक साल के दौरान सरकार की काफी फ़जीहत हुई है। यहां पर कितने मामले रेप और मर्डर के हुए, सरकारी अधिकारियों पर हमले हुए; इस बारे में सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। अंत में, मैं एक लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करत हूं कि

यह बात हम जानते हैं और मन-ही-मन आप भी मानते हैं
कि कोरे भाषणों से गरीबों के पेट नहीं भरते।
आपके चुनावी वादों के मुताबिक अगर अच्छे दिन आ गये होते
तो मेरे प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा आज यूं ही सड़कों पर न घूम रहे होते।।

यहां पर जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया है यह मुझे पूरी तरह खोखला लग रहा है और इसमें सरकार की नाकामियां नजर आ रही हैं। आपकी सरकार अपने एक साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य करने में असफल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार अच्छे काम करने की कोशिश करेगी। अभी चर्चा हो रही थी कि दिनांक 26 फरवरी, 2019 को आप सैंट्रल युनिविर्सिटी का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह आदत रही है कि चुनाव आने से 3-4 दिन पहले शिलान्यास कर देते हैं। ---(व्यवधान)--- मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले विधान सभा चुनाव से तीन दिन पहले बिलासपुर में एक शिलान्यास हुआ। जब फाउंडेशन हो जाता था तो उसके बाद सीधे जाकर उसका उद्घाटन किया जाता था। मगर इतिहास में यह पहली बार हुआ कि फाउंडेशन के बाद भूमि पूजन वाला सिस्टम शुरू हुआ है जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यह कोई नई रिवाज शुरू हो गई है। इसी तरह से आप सैंट्रल युनिविर्सिटी का भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से तीन या चार दिन पहले शिलान्यास करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि आप यह शिलान्यास इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जनता आपसे इस बारे में प्रश्न पूछने वाली हैं। इसी तरह से रेल के बारे में चर्चा आई थी। हमीरपुर में तो हमारे सांसद यह क्लेम करते हैं कि ऊना से हमीरपुर के लिए रेल लाइन का सर्वे हो गया है। मैंने पूछा कि अगर सर्वे हुआ है तो उसमें लोग सर्वे करने के लिए आते हैं और जनता को पता लगता है। आप सर्वे दिन के उजाले में कर रहे हैं या रात के अन्धेरे में कर रहे हैं? उन्होंने डेढ़ साल पहले एक स्टेटमैंट रिलीज कर दी कि ऊना से हमीरपुर के लिए 2800 करोड़ रुपये मन्जूर हो गये हैं। मैंने नैट पर चैक किया लेकिन कोई पैसा नहीं था। मैंने बाद में स्टेटमैंट दी कि अगर 2800 करोड़ रुपये जारी हुए हैं तो आप उसके डॉक्युमैंट दें और फिर तीसरे दिन उनकी स्टेटमैंट आई कि कोई पैसा जारी नहीं हुआ। इस बार हमने देखा कि हमीरपुर के लिए बजट में 10 लाख रुपये का प्रोविजन किया गया है।

10 लाख रुपये में कौन-सा सर्वे होगा और कौन-सी रेल लाइन बन जाएगी। 10 लाख रुपये तो आज 20 मीटर का डंगा लगाने में लग जाते हैं। आप लोग चुनाव के लिए लोगों के बीच जाने वाले हैं और लोग आपसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। खासतौर पर 13 लाख रुपये का हिसाब आपसे लेने वाले हैं। इसलिए जब लोगों के बीच जाएं तो ज़रा ध्यान से जाएं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः वैसे माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी बहुत अच्छी शेरो-शयरी करते थे। लेकिन आज थोड़ा-सा चूक गए, अगली बार अच्छी-सी तैयारी करके आना। --- (व्यवधान)--- हमने तो आपसे सीखी है। अगले व़क्ता श्री सुरेश कुमार कश्यप जी।

श्री सुरेश कुमार कश्यप(पच्छाद)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया और उसके ऊपर कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस एक वर्ष के कार्यकाल की बात है, मुझसे पूर्व भी बहुत-सारे व़क्ताओं ने अपने विचार यहां पर रखे। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक वर्ष का कार्यकाल वर्तमान सरकार का आदरणीय ठाकुर जय राम जी के नेतृत्व में एक युवा जोश और नई सोच को दर्शाता है। एक वर्ष का कार्यकाल और एक वर्ष की उपलब्धियां जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रखी, निश्चित रूप से सराहनीय है। उसमें चाहे हम कृषि की बात करें, जहां किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ाया देने के लिए सरकार ने कदम उठाया वहीं 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान' के तहत लगभग 9 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। ताकि हमारे किसान प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर सकें। आज हम देखते है, हमारे किसान जो खेती करते है, उसमें किस प्रकार से चाहे पेस्टिसाइड की बात है या फर्टिलाइजर की बात है, उससे किस प्रकार से हमारी सेहत को नुकसान होता है। इन सब से छुटकारा पाया जा सके इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया और मैं बताना चाहूंगा कि जिला सिरमौर में भी लगभग 180 बीघा के ऊपर प्राकृतिक खेती शुरू की

गई है जिसमें करीब 170 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मेरे पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 60 ऐसे किसान है जो आज के समय में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ताकि हमारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी प्रकार से बागवानी क्षेत्र में भी चाहे 'पुष्प क्रांति' की बात है या 'मुख्य मंत्री मधु विकास योजना' है, इसके तहत भी हमारे बागवानों और किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ ही अन्य बहुत-सारी योजनाएं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले बजट में 3 नई योजनाएं शुरू की थी लेकिन मैं मुख्य रूप से 2-3 योजनाओं का ज़िक्र करना चाहूंगा। एक ऐसी योजना है, जिसका डायरेक्टली हमारे प्रदेश की जनता को फ़ायदा हो रहा है। मैं जनमंच की बात करना चाहूंगा जिसके विषय में यहां हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत-सारी बातें कही। यहां पर जनमंच को कोई लंचमंच या कुछ और कह रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जनमंच एक ऐसी योजना है जिसके तहत जनता का सीधा संवाद सरकार से हो रहा है। विकास के मामले में जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति पर बैठा है,

06-02-2019/1600 /NS/HK/1

किस प्रकार से उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसकी जो भी समस्यायें हैं, उनका मौके के ऊपर ही निपटारा किया जा सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। मैं कहना चाहूंगा आज न केवल भाजपा के लोग बल्कि कांग्रेस के लोग इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और जब हम जनमंच कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं कांग्रेस के लोग लेकर आते हैं तथा यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जनमंच से हो रही है। क्योंकि ज्यादा-से-ज्यादा लोग जनमंच में पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का वहीं पर निपटारा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने यह बहुत अच्छी पहल की है। इसी प्रकार से "मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना" हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और आज बिना किसी जातीय भेदभाव के ---(व्यवधान)--- लोगों को गैस कनैक्शन मिल रहे हैं।

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बीच में न बोलें। जिनको समय दिया गया है, उनको अपनी बात पूरी करने दें। सुरेश जी, आपका समय जा रहा है, आप अपने विषय पर बोलें।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः ---(व्यवधान)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं "मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना" की बात कर रहा था और आज सभी लोगों को गैस के कनैक्शन मिल रहे हैं। इसमें चाहे कांग्रेस या भाजपा के लोग हों। मैं इसके लिए जिला सिरमौर की बात करना चाहूंगा। जिला सिरमौर में पहले फेस में 2322 लोगों को गैस के कनैक्शन मिले थे और अभी लगभग 4,000 लोगों को गैस के कनैक्शन दिए जा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले फेस में 580 लोगों को और अभी तक लगभग 250 लोगों गैस कनैक्शन बांट दिए गए हैं। आने वाले समय में हमारा लगभग 1,000 का टारगेट है और हम इसको पूरा करेंगें तथा जो बच जाएंगे तो आने वाले समय में उनको भी गैस के कनैक्शन दिए जाएंगे। यह बहुत ही अच्छी योजना है और जब यह योजना पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तो हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य होगा जो पूर्ण रूप से धुएं से मुक्त होगा तथा हमारी माताओं और बहनों को धुएं से जो समस्यायें हो रही हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रदेश सरकार विशेष रूप से युवाओं के लिए लेकर आई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने "मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना" हिमाचल प्रदेश में शुरू की। पिछली बार जब सरकार सत्ता में आई थी तो बेरोज़गारों से एक वायदा किया था कि हम बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। अपने घोषणा-पत्र में उन्होंने वायदा किया और सरकार के पांच साल निकल गए। लेकिन कितने लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मिला, इस बात का सभी को ज्ञान है। जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनको मालूम है। हम जब सदन में इस बात की मांग करते थे तो उस समय के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमने वायदा नहीं किया है, घोषणा-पत्र माननीय बाली जी ने बनाया है और मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है तथा इन्होंने पांच साल ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी ने युवाओं के बारे में सोचा कि हमारे युवा साथी स्वाबलंबी बने। वे न केवल अपने लिए रोज़गार अपितु अन्य साथियों के लिए भी रोज़गार उत्पन्न करें। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में 50 लाख रुपये तक के कार्य के लिए 40 लाख रुपये की ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। कल विपक्ष के नेता माननीय मुकेश

जी कह रहे थे कि कितने लोगों को इस योजना का फायदा मिला? मैं जिला सिरमौर के बारे में बात करना चाहूंगा, मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा। जिला सिरमौर में लगभग 46 लोगों को इस योजना का फायदा मिला है और लगभग 1.86 करोड़ रुपये की सबसिडी हमारे युवा साथियों को मिली है। वहां पर तकरीबन 24 ऐसे उद्योग युवा साथियों ने लगाए हैं और इसके तहत बहुत सारे युवा साथियों को स्वरोज़गार का अवसर मिला है। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से हमारे युवा साथी स्वाबलंबी भी बने हैं। वे न केवल अपने लिए अपितु अन्य लोगों के लिए भी रोज़गार उत्पन्न कर सके, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वर्तमान में प्रदेश सरकार ने लाई है। एक अन्य योजना जिसका मैं यहां पर ज़िक्र करना चाहूंगा। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से "अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती" यह योजना प्रदेश सरकार ले करके आई है ताकि उच्च विद्यालय से निकले हुए छात्र जिन्होंने देश और प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल की है,

06.02.2019/1605/RKS/YK-1

उन छात्रों को दोबारा से उसी विद्यालय से जोड़ना ताकि उस विद्यालय के जो बच्चे हैं वे उनके पद चिन्हों पर चल सके और उसी प्रकार देश और प्रदेश में ख्याति प्राप्त करें। उन छात्रों का नाम गौरव पट्ट पर लिखा जाता है ताकि उस विद्यालय के छात्र उनसे प्रेरणा ले सके। यह एक महत्वपूर्ण योजना है कि जो पूर्व छात्र उस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर निकले हैं उनका योगदान उस विद्यालय से जोड़कर उस विद्यालय को और उन्नत किया जाए और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

यदि हम टूरिज्म की बात करें- 'नई राहें नई मंजिलें' जिसमें प्रदेश सरकार 1900 करोड़ रुपये का पैकेज केंद्र सरकार से लेकर आई है ताकि हमारे युवा साथियों को रोजगार मिल सके।

विशेष रूप से युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो पहल की है वह बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों व मुख्य

सचिवों के साथ समन्वय बैठक की है ताकि जो नशा दूसरे प्रदेशों से यहां आ रहा है और जिससे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे छुटकारा मिल सके। सारे राज्य मिलकर नशे के निवारण के लिए काम करे ताकि हमारे युवा साथी नशे से बच सके। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे।

अगर हम वृद्धावस्था पैंशन की बात करें तो जिन बुजुर्गों को 80 वर्ष की आयु में पैंशन लगती थी वह अब बिना किसी आय प्रमाण के 70 वर्ष कर दी गई है। लगभग 1.60 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। यह निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री ने एक बहुत बड़ा कार्य हमारे बुजुर्गों के लिए किया है। एक वर्ष का कार्यकाल जोकि बहुत छोटा-सा कार्यकाल है लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को उन्नति की राहों में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत से कार्य किए हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। अगर मैं पछाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं, चाहे वह सड़कों की ही बात क्यों न हो। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्व सरकार ने जो सड़कों की दुर्दशा बिगाड़ रखी थी उसको सुधारने के लिए मात्र एक साल के कार्यकाल में न केवल प्रयास किया गया अपितु एक क्वालिटी वर्क भी हुआ है। पिछले पांच वर्षों में जिन सड़कों का काम हुआ, वे मात्र तीन महीनों के भीतर ही खराब हो जाती थी। उन सड़कों के ऊपर घास जम जाती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन सड़कों के काम पिछले एक वर्ष के दौरान हुए हैं वे सड़कें वैसी-की-वैसी हैं। उनके कार्य में कोई कमी नहीं आई है। यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन कार्य सड़कों के रूप में हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रवास जिन-जिन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में हुआ है वहां पर करोड़ों रुपये की घोषणाएं हुई हैं। माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी Cow Sanctuary की बात कर रही थी। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के कोटला- बड़ोग में एक

Cow Sanctuary का शुभारंभ किया गया जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह Cow Sanctuary लगभग 104 बीघा पर बन रही है और वहां पर पशुओं को न केवल रखा जाएगा बल्कि वे वहां पर खुले में रह पाएंगे। आवारा पशुओं को इस Cow Sanctuary में रखा जाएगा और मैं समझता हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राजगढ़ में जो 50 बिस्तरीय अस्पताल था उसे 100 बिस्तरीय किया गया है। पझौता कॉलेज जो कि पूर्व सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में खोला था उसके लिए मात्र एक लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्धाज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने न केवल उस कॉलेज को प्रारम्भ किया बल्कि आज वहां प्रिंसिपल से लेकर सारा स्टाफ मौजूद है। उस कॉलेज के भवन निर्माण के लिए

06.02.2019/1610/बी0एस0/डी0सी0-1

3 करोड़ रुपये की घोषणा की थी जिसमें से माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ करोड़ रुपये हमारे लिए स्वीकृत किया है। पूर्व सरकार ने मात्र 1 लाख रुपये का प्रावधान उसके लिए किया था। आज यह कालेज चल रहा है और बहुत जल्दी उस भवन का निर्माण भी आरंभ कर लिया जाएगा। मैं तहे-दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । हमारी सरकार का अभी मात्र एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है अभी चार वर्ष का समय बाकी है। हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा । हम चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, पेयजल की बात करें या अन्य विकास कार्यों की बात करें। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से पिछले पांच साल में पिछड़ गया था। परंतु आज वे विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। पिछले एक वर्ष में

जिस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती की गई वह सराहनीय है जो हमरे स्कूल बिना अध्यापकों से चल रहे थे वहां आज शिक्षक पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश कुमार कश्यप : मेरा जो पच्छाद विधान सभा चुनाव क्षेत्र है वहां भारी शिक्षकों की कमी थी परंतु वर्तमान सरकार ने इस कमी को पूरा किया है। इसमें चाहे सीनियर सेकेन्डरी में प्रिंसिपल की बात हो, चाहे पी.जी.टी. की बात हो, चाहे टी.जी.टी. की बात हो या प्राथमिक स्कूलों में डैपूटेशन पर स्कूलों में टीचर आते थे । वे अध्यापक सुबह तीन बजे आते थे और शाम को 3 बजे स्कूल से चले जाते थे। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो दर्जनों स्कूल अध्यापकों के बिना खाली थे उन सभी में आज अध्यापक आ चुके हैं। पटवारियों की कमी लगातार जो पिछले 5 वर्षों में थी और लगातार हम इस समस्या को यहां पर उठाते रहते थे। परंतु यह कमी भी हमारी सरकार द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल में पूरी की गई है। आज कोई भी पटवार सर्कल मेरे क्षेत्र में बिना पटवारी के नहीं है। प्रदेश ने जो शिक्षको की खाली पोस्टें पड़ी हैं उनकी एस.एस.सी. के माध्यम से भरने का कार्य किया है। उसमें हमारे पी.जी.टी. और टी.जी.टी. की भर्ती की है। विशेष रूप से हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां हमारे रोड़ हैड पर तो अध्यापक आ जाते हैं परंतु जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं वहां पर अध्यापक नहीं आते। प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में "सबका साथ सबका विकास" इस नारे को बल दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश उन्नति की राह पर और आगे बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब चर्चा में माननीय सदस्या कमलेश कुमारी जी भाग लेंगी। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री कर्नल इन्द्र सिंह जी ने रखा और उसका समर्थन भाई आदरणीय बजबीर सिंह जी ने किया। उसमें चर्चा में शामिल होने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुशल संगठन कर्ता भारतीय संस्कृति के पोषक हिमालच प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग और हर गीरब व्यक्ति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। उपाध्यक्ष जी, दो दिन से इस माननीय सदन में जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां है उनके ऊपर चर्चा हो रही है । लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं 20 वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हूं

06.02.2019/1615/DT/AG/-1

और मेरा 20 वर्षो का जो अनुभव रहा है, अगर में उसकी बात करूं तो वर्ष 2000 में मैंने चुनाव लड़ा था। मैं जिला परिषद् की सदस्या और पंचायत की प्रधान रही हूं। आज यहां बुढ़ापा पेंशन की बात हो रही थी। माननीय उपाध्यक्ष जी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो बुढ़ापा पेंशन के लिए तरसते थे। उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो इस दुनियां से भी चले गए लेकिन उनको बुढ़ापा पेंशन नहीं लग पाई। वे सारी जिन्दगी बुढ़ापा पेंशन का राग अलापते रहे। इनमें कुछ मेरी माताएं भी जो विधवा थी, लेकिन उनको भी बुढ़ापा पेंशन नहीं लग पाती थी। जैसे ही इस प्रदेश में सरकार बनी, माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने बिना किसी आय सीमा से सामाजिक पेंशन के लिए जो आयु सीमा 80 वर्ष थी उसको घाटाकर 70 वर्ष किया है। इसके लिए मैं बुजुर्ग वर्ग की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारे बुजुर्ग वर्ग के लिए मान-सम्मान दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इससे एक लाख 60 हजार पात्र व्यक्तियों को लाभ हुआ है। 60 हजार नए व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा 5 लाख 11 हजार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा

पेंशन प्रदान करने हेतु 600 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद्, बी0डी0सी0 और प्रधान थ्री टायर सिस्टम था। मैं स्वयं भी प्रधान रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले समय में जो हमारे ज़िला परिषद और बी0डी0सी0 सदस्य हुआ करते थे, उनका जो बजट था उसको खत्म किया गया था। लेकिन जैसे ही प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमारे जो बी0डी0सी0 सदस्य थे, ज़िला परिषद सदस्य थे उनके लिए फिर से मान सम्मान प्राप्त हुआ। क्योंकि हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में चुनकर आता है उससे लोगों को उम्मीदें होती हैं। चाहे वॉर्ड सदस्य हो, प्रधान हो, बी0डी0सी0 हो, ज़िला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री हो। हर कोई चाहता है कि हमनें अपने विधायक या ज़िला परिषद या किसी को चुना है तो उनसे कुछ न कुछ उम्मीद होती है।

उस उम्मीद को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है । पंचायती राज सस्ंथाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों का जो मानदेय बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं की सशक्तीकरण के लिए एक महत्वकांक्षी उज्ज्वला योजना शुरू की है जिसमें

06-02-2019/1620/ए.जी./एन.जी./1

गृहणीयों को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं । आज मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो देश में आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने और प्रदेश में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने सोचा है । हमारी जो महिलाऐं हैं वह दिन भर चुल्हे चौके का काम देखती है । उपध्यक्ष महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी की यदि एक कप चाय बनाना पड जाए तो चुल्हे में आग जलानी पडती थी । मैं यह ब्यां नहीं कर सकती कि गर्मीयों के मौसम तो कोई समस्या नहीं होती थी परन्तु बरसात के समय में कोई महमान आ जाता था तो उसके लिए एक कप चाय का भी बनाने के लिए तो महिलाओं को कितनी दिक्कत होती थी । मैं अगर अपने गांव की बात बताउं तो हमारी एक चाची-तायी

ही लगती थी उसकी अचानक आंखों की नजर चली गई । वह इतना गरीब परिवार था और उसको चैक करवाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और फिर एकदम से पी.जी.आई. ले जाया गया । जब वहां डाक्टरों की सलाह ली गई तो उन्होने बताया कि इन्हें धूऐं के पास जाने नहीं देना । वह घर की मुखिया थी तो रसोई में उसे जाना ही पडना था । अगर आज ऐसी महिलाओं की समस्याओं को किसी ने सुना है और उज्जवला योजना के अन्तर्गत पूरे देश भर में 6 करोड महिलाओं को गैस कनैक्शन आज की डेट में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी बांट चुके हैं । इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 86 हजार गैस कनैक्शन हिमाचल प्रदेश में जारी किए जा चुके हैं । मैं इस माननीय सदन में कहना चाहूंगी कि देश के माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री श्री जय राम ठाकुर जी का काम करने का ढंग और सोच बिलकुल एक जैसी है । संगठन और गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति ही किसी का दुःख दर्द समझ सकता है । इसी कडी में कहना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री जय राम ठाकुर जी ने भी दो कदम आगे बढ कर काम किया है । हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री जय राम ठाकुर जी ने 25 मई, 2018 को 3 योजनाओं का शुभारम्भ किया । उसमें से जो पहली योजना थी वह है गृहणी सुविधा योजना । उपाध्यक्ष महोदय, इसका शुभारम्भ 25 मई, 2018 को किया गया जिसमें प्रदेश की सभी पात्र गृहणीयों को निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किए जा रहे हैं । कल भी इस माननीय सदन में चर्चा हो रही थी कि और हमारे माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने व वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बात रखी की इस योजना में बंदर बांट हो रही है । मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो गैस कनैक्शन मिल रहे हैं क्या यह केवल एक-दो विधानसभा क्षेत्रों में ही मिल रहे हैं ? यह पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं के लिए गैस कनैक्शन बांटे जा रहे हैं । आज मैं इस माननीय सदन से कहना चाहूंगी कि पूरे देश भर की महिलाओं की और से मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का और माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूं । 31.01.2019 तक प्रदेश में 48962 परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं । इस प्रक्रिया को तब तक निरन्तर जारी रखा जाएगा जब तक की सभी पात्र परिवारों को गैस कनैक्शन नहीं मिल जाते ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अभी बहन श्रीमती आशा जी ने यहां बात रखी है।

06/02/2019/1625/RG/DC/1

जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु 25 मई, 2018 को जनमंच कार्यक्रम के आयोजन की शुरूआत की गई। इसमें 24,424 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। गरीब लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां जो बहन ने बात रखी है कि यदि एक नलका लगना होगा या किसी को कोई प्रमाण-पत्र बनाना होगा तो इसके लिए क्या जनमंच कार्यक्रम का इन्तजार करना पड़ेगा? मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि यह जनमंच का कार्यक्रम रविवार वाले दिन होता है और मैं अधिकारियों एवं कर्मचारियों का इसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूं कि वे अधिकारी एवं कर्मचारी छुट्टी के दिन भी अपनी सेवाएं गरीब लोगों व जनता के लिए दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्रीमती कमलेश कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष : आप एक नहीं बल्कि दो बातें कहें, परन्तु जल्दी कहें।

श्रीमती कमलेश कुमारी : इस कार्यक्रम के शुरू करने से कार्यालयों में जिन फाइलें पर धूल जमी होती थी, उससे भी निजात मिली है। क्योंकि जो हमारा जनमंच का कार्यक्रम होता है, उसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाते हैं, चाहे निशानदेही, इन्तकाल या कोई और काम हो, सात दिन के अन्दर उसको करें और वह काम सात दिन में कर दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपने बजट में देश के सभी किसानों के लिए कई नई सरकारी योजनाओं को शुरू करने का आधिकारिक ऐलान किया है जिसमें एक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' है। इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष सभी निम्न वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 6000/-रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस सरकारी योजना का लाभ देश के सभी छोटे और सीमान्त किसानों को दिया

जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ ...(घण्टी)...दो हैक्टेयर तक की भूमि रखने वाले सभी निम्न वर्गों के किसानों को दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने सिर्फ दो ही बातें और रखनी हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक महिला की आंखों की नजर चली गई और उसको अपनी आंखों का चैक अप
कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना आयुष्मान भारत' का शुभारम्भ किया। पूरे देश में 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। आज मैं इस सदन में माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिए।

श्री कमलेश कुमारी : इसमें गरीब परिवारों के लोगों के उपचार के लिए पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी एक 'हिम केयर' योजना शुरू की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं।
माननीय उपाध्यक्ष जी, दो मिनट के लिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष : आगे बजट पर होने वाली चर्चा में आपने बोल लेना।

श्रीमती कमलेश कुमार : यहां जो बात कही जा रही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार केन्द्र में गए लेकिन वहां से लेकर कुछ नहीं आए। इस बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ और उसमें 28 करोड़ रुपये के शिलान्यास किए गए। इसके अतिरिक्त मैं यहां बताना चाहूंगी कि वर्ष 2014 में मेरे भोरंज क्षेत्र में एक त्रासदी हुई थी जिसमें पूरा-का-पूरा एक इलाका बह गया था और जो उस किनारे पर लोग रहते थे, वे दहशत में रहते थे कि कब बारिश हो जाए और हमें कहीं अपने घरों से फिर से जाना न पड़ जाए। लेकिन जैसे ही प्रदेश में माननीय श्री जय राम ठाकुर जी सरकार बनी

तो इस सरकार के बनते ही हमारी सैंज खड्ड के चैनेलाइजेशन के काम का माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास किया और साढ़े चार करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन किया।

उपाध्यक्षः आपसे अनुरोध है कि कृपया वाइंड-अप करें। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्रीमती कमलेश कुमारीः इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी के साथ मैं एक और बात करना चाहती हूं कि एक वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 68 विधान सभा क्षेत्रों में से 65 विधान सभा क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया और केन्द्र से जैसे पैसा भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए आता है, उसी तर्ज़ पर हरेक विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के लिए इन्होंने पैसा दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा यहां रखे गए अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

उपाध्यक्षः कमलेश जी, धन्यवाद। अब चर्चा में श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा(नालागढ़)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 4 फरवरी, 2019 को इस सदन में अभिभाषण रखा, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार युवा नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो अभिभाषण में कही गई हैं उनमें से कुछ बातें अधूरी हैं तथा इनको पूरा करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

यह सत्य है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर मक्की, गेहूं और धान की फसल पैदा होती है, उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से ऊपर के क्षेत्रों के बागवानों के सेबों का समर्थन मूल्य बढ़ता है उसी प्रकार से हमारे निचले क्षेत्र के किसानों की फसल का भी समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे किसानों को 6 महीने अपने खेत में काम करना पड़ता है। उनके सारे परिवार के सदस्य खेत में काम करते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है यानी जब फसल को बेचने की बारी आती है तो मुश्किल से उस परिवार के सदस्य को मजदूरी भी प्राप्त होती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोई कठोर कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है। पीछे हम सबने देखा है कि पूरे देश में प्याज और आलू के उत्पादकों की क्या दुर्दशा हुई और उन्हें उस प्याज और आलू की पूरी फसल को खेतों से बाहर निकालकर सड़कों पर बिखेरना पड़ा। उनको उस फसल का कोई पैसा नहीं मिला। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कृषि की एक कठोर नीति बननी चाहिए।

यहां पर "हिमाचल पुष्प क्रांति योजना" का जिक्र किया गया। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी पॉली-हाउस और ग्रीन-हाउस लगे हैं ये सारे सब्सिडी खाने का केन्द्र बन चुके हैं। हालांकि हमारे बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो इनको लम्बे समय तक चलाते हैं लेकिन जब सब्सिडी की बात आती है तो औपचारिकताएं ही पूरी नहीं हो पाती हैं इसलिए उनको बीच में ही अपने ग्रीन-हाउस और पॉली-हाउस बन्द करने पड़ते हैं। अतः विभाग को

इसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है। एक "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" है जिसमें 60 और 40 का अनुपात रखा है। उसमें मेरा सुझाव है कि इस अनुपात को बदलकर 70 और 30 परसेंट किया जाए। इसमें 70 परसेंट मटीरियल होना चाहिए और 30 परसेंट लैबर होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि परिवार के लोगों को 100 दिन का काम मिलेगा। इसमें अमैंडमैंट होनी चाहिए और पविार के हरेक सदस्य को 100 दिन का काम मिलना चाहिए। इस योजना में उनकी दिहाड़ी 184/-रुपये है तो इसे भी बढ़ाकर 225/-रुपये जो सरकार ने रेट रखा है, वह होनी चाहिए

06.02.2019/1635/जेके/एचके/1

ताकि वे योजनाएं कारगर ढंग से चल सकें। अभी यहां पर जनमंच की भी बहुत चर्चा हुई। यहां पर बहुत से साथियों ने जनमंच के बारे में अलग-अलग बातें कही। हमारे नालागढ़ विधान सभा में भी दो जनमंच हुए। यहां पर सरकार ने कहा कि वहां पर 24,424 मांग पत्र व शिकायतों का निपटारा किया गया। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मज़दूर हैं उनमें भी पिक एण्ड चूज़ हुआ है। उनकी शिकायतों को जनमंच में नहीं लगाया गया। यह जो जनमंच आपने चलाया है इसको अगर सफल बनाना है तो उसके लिए बड़े ऑफिसर की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मुख्य मंत्री लैवल पर इन जनमंचों की देख-रेख व समीक्षा होनी चाहिए।

यहां पर सिंचाई योजनाओं की बात भी की गई। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों के लिए पानी बहुत आवश्यक है। अगर हमारे सिंचाई के ट्यूबवैल होंगे तो हम अधिक फसल पैदा कर सकते हैं। मैंने पीछे एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में कुछ स्कीमें दी थी। हमारे प्रदेश के जो जियोलोजिस्ट हैं, उनको हमने जो प्वाइंट दिए थे और जिन-जिन जगहों पर सिंचाई के ट्यूबवैल लगने चाहिए थे उन्होंने उन प्वाइंट्स को बहुत कम सलैक्ट किया। यहां पर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जियोलोजिस्ट ने उन प्वाइंट्स को सलैक्ट नहीं किया। वहां पर जब कोई किसान अपना सिंचाई का बोर लगाता है तो वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से पानी निकलता है। इसके

लिए मैं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पीछे हमने जब विधायक प्राथमिकता के तहत अपनी सिंचाई की कुछ स्कीमें रखी थी उनको दोबारा से चैक किया जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। इसी तरह से चालू वित्त वर्ष में कहा गया कि 9,500 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन-सम्वर्द्धन योजना, वन जन समृद्धि योजना इत्यादि योजनाओं को इस दस्तावेज में रखा गया। यहां पर यह भी कहा गया कि जंगली जड़ी-बूटियों के संग्रह व निजी जमीन के उत्पादन से हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, उनका रोजगार बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा कि पीछे वन महोत्सव भी मनाए गए। हर चुनाव क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चले। वनों में पौधे लगाने का काम बहुत ही युद्ध स्तर पर चला। लेकिन इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो पौधे वहां पर लगाए गए उनकी देखभाल के लिए किसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी पौधे लगाए उनमें से आधे पौधे सूख गए हैं। इसकी भी विभाग को निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने नशे को रोकने की बात की। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने कारगर कदम उठाए हैं। हम इस बात की प्रशंसा भी करते हैं लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं। बी0बी0एन0डी0ए0 हमारा क्षेत्र पड़ता है। उसमें हमारे दून का क्षेत्र भी है और हमारे नालागढ़ का भी क्षेत्र है लेकिन वहां पर चिट्टा,अफीम, भुक्की और सिन्थैटिक ड्रग के जो नशे हैं, वहां पर सरेआम बिक रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर का एरिया लगता है। पंजाब के जो नशे के कारोबारी हैं, हरियाणा के जो नशे के कारोबारी हैं, वे वहां पर धड़ल्ले से आ कर नशा बेच रहे हैं। जो हमारे नौजवान युवा हैं, इस नशे की लत में आ कर उनकी रोज़ मृत्यु हो रही है। जो ये नशे के कारोबारी हैं, चाहे हरियाणा से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 में अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है। अतिरिक्त बटालियन वहां पर भेजी जानी चाहिए ताकि इस नशे की लत से राहत मिल सके। इस दस्तावेज में कहा गया है कि खनन के ऊपर बहुत लगाम लगाई गई है लेकिन बी0बी0एन0डी0ए0 में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खनन माफिया बहुत सक्रिय हैं। रात-दिन

धड़ल्ले से हमारी नदियां खनन करके, छलनी करके रख दी है। वहां पर रात-दिन खनन किया जा रहा है।

06-02-2019/1640/SS-HK/1

उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो दो-तीन नदियां पड़ती हैं, जिन लोगों की जमीनें वहां पर साथ लगती थीं, उन्हें खनन माफियों से बचने के लिए कोर्ट से स्टे लेनी पड़ी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जे0सी0बी0/पोकलैंड इस्तेमाल की जा रही है। जो खनन माफिया है, न तो उनको कोई पुलिस का डर है और न कोई माइनिंग डिपार्टमैंट का डर है। इसलिए इन विभागों को चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

इसी तरह दस्तावेज़ में कहा गया कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई है। जिसमें कहा गया कि 5 लाख परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपया निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। फिर भी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बी0बी0एन0डी0ए0 पड़ता है। साढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग फैक्टरियों में काम करते हैं और नज़दीक में रहते हैं। लेकिन नालागढ़ में जो सी0एच0सी0 है वह सिर्फ 100 बैड का है। उसमें केवल 12 डॉक्टर्ज़ हैं। जबकि 100 बैड के हिसाब से वहां पर 18-19 डॉक्टर्ज़ चाहिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। हमारे चंगर क्षेत्र में पी0एच0सी0, जोगो पड़ता है। क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, उसको हमने सी0एच0सी0 में अपग्रेड करने के लिए आवेदन किया था। उसको भी अपग्रेड किया जाना चाहिए।

यहां पर रोज़गार की बात की गई कि हम हिमाचल प्रदेश में रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि कितना रोज़गार यहां पर मिल रहा है। हर विभाग में बहुत पद रिक्त पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि इन पदों को भरा जाए। जो हमारे हलका में बी0बी0एन0 में फैक्टरियां लगी हैं, सरकार ने कानून बना रखा है कि 70 परसैंट हिमाचलियों को उनमें रोज़गार मिलेगा। लेकिन मुश्किल से 30 परसैंट भी रोज़गार हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि विधान सभा से विधायकों की ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो उद्योगों में जाकर चैक करे कि

जो 70 परसैंट हिमाचलीज़ को रोज़गार देने की कंडीशन लगा रखी है उनको उद्योगपति फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। इको-टूरिज्म की बात कही गई कि पर्यटन को सरकार बढ़ावा दे रही है। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही जिलों और तहसीलों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हमने हिमाचल प्रदेश में राजस्व को बढ़ाना है तो हमें ऐसे पर्यटक स्थल तलाश करने चाहिएं ताकि उनको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। हमारे नालागढ़ क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं, उनको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए।

यहां पर हिमाचल प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा 63 नेशनल हाईवे स्वीकृत किये जाने की बात कही गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी दो नेशनल हाईवे स्वीकृत हुए थे। एक घिनौली से लेकर वाया रामशहर-कुनिहार-शिमला नेशनल हाईवे था और दूसरा भरतगढ़-सोवन माज़रा-बघेरी और बिलासपुर के साथ टच करता नेशनल हाईवे था। लेकिन अभी तक उन नेशनल हाईवे का अता-पता नहीं है। उन नेशनल हाईवे का काम शुरू ही नहीं हुआ है और न ही उनकी कोई डी0पी0आर0 बनी है। लेकिन यह दिखावा नहीं होना चाहिए।

इसी तरह यहां पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयुसीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने की बात कही गई। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 80 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में गैप है कितने लोगों को यहां पर पैंशन दी गई? अभी बहुत लोग इस कतार में हैं कि हमारे को यह पैंशन मिलनी चाहिए। इसकी उन्हें उम्मीद है। लेकिन वह योजना भी अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है।

गैस कनैक्शन देने के लिए गृहिणी सुविधा योजना तथा उज्जवला योजना की बात कही गई। नेगी जी ने ठीक कहा कि कई जगह पिक एंड चूज़ की बात हो रही है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी जो गरीब है और आई0आर0डी0पी0 से संबंधित है उनको भी अभी तक गैस के कनैक्शन नहीं मिल पा रहे। इस योजना को भी हिमाचल प्रदेश में अच्छे ढंग से चालू नहीं किया जा रहा।

इसी तरह से हमारे यहां पर जो विधायक निधि है, हम चाहते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख विधायक निधि जो अभी सरकार ने तय की है, क्योंकि विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवाने के लिए बहुत समस्याएं आती हैं अतः इसको बढ़ा कर 2 करोड़ किया जाना चाहिए और जो ऐच्छिक निधि है, इसको 7 लाख से 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री परमजीत सिंह जी रेल की बात कर रहे थे, इन्होंने भी कहा था कि बद्दी के लिए बहुत लम्बे समय से रेलवे लाइन प्रस्तावित है लेकिन अभी तक उसके लिए जमीन का कोई अधिग्रहण नहीं हो पाया। घनौली से ले कर नालागढ़ तक अंग्रेजों के समय में रेल चला करती थी।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

वहां पर रेल की पटरी भी बनी हुई है और जमीन भी रेलवे विभाग के नाम है । हम चाहते हैं कि घनौली से लेकर नालागढ़ तक जो पहले पुरानी रेल लाइन थी, उसको चालू किया जाए। जो यहां पर राज्यपाल महोदय की तरफ से दस्तावेज पेश किया गया, मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं भी उसमें खुद को शामिल करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में नई ऊर्जा एवं दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आरम्भ किया है। प्रदेश के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जा कर लोगों से सीधा सम्पर्क किया एवं

उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से निवारण किया है। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाते हुए गत एक वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है और गर्व का विषय है कि हमारी सरकार ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के आदर्श को अपनाते हुए अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही अधिकतर चुनावी वायदों को प्रभावी ढंग से पूरा किया है। इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख इस प्रकार से हैंः-

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2018-19 के लिए सभी अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा दिया है। चालू वित्त वर्ष में राज्य में एक नई योजना "प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान" शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 9 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक लगभग 3 हजार कृषकों द्वारा इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना" देश के अंदर चलाई है जिसमें देश के हर किसान को 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। आजादी से ले कर आज तक पहली बार देश के अंदर किसानों के प्रति माननीय प्रधान मंत्री जी ने योजना शुरू की है। जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया, उन्होंने आज तक किसानों के प्रति ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिससे सभी किसान दो समय की रोटी आराम से खा सके और पूरे साल का गुजारा कर सके। पहली बार देश में ऐसी योजना आई है। देश में जिन किसानों की जमीन दो हैक्टेयर से कम है, उसमें 12 करोड़ के करीब किसान परिवार आएंगे। किसानों की फसलों को बंदरों, जंगली जानवरों तथा बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए भी मुख्य मंत्री महोदय ने "खेत संरक्षण योजना" के अंतर्गत सौर बाड़ पर अनुदान बढ़ाया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक किसानों को 22 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

6.2.2019/1650/av/yk/1

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में 1.25 लाख कृषकों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानी से प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश को 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व जनरेट होता है। वर्ष 2018-19 में लगभग 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अंतर्गत लाया गया है। राज्य में बागवानी के समग्र विकास में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र में भी 11 ऐसी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिससे 11 पंचायतों के लोगों को फायदा होगा। अगर ये योजनाएं 25-30 वर्ष पहले आतीं तो आज हमारे प्रदेश के किसान अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते तथा उनकी वित्तीय स्थिति भी कुछ भिन्न होती। इन योजनाओं के अंतर्गत उच्च मूल्य के फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए 35,500 वर्ग मीटर क्षेत्र पॉलीहाउस व ग्रीनहाउस, 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र छायादार जाली गृह तथा 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र प्लास्टिक-टनल के अंतर्गत लाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में आठ पशु औषधालयों को स्तरोन्नत करके पशु चिकित्सालय बनाया गया और दो नये पशु चिकित्सालय भी खोले गये हैं। अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के किसानों द्वारा पाली जा रही देसी नस्ल की गायों को गर्भावस्था के दौरान 50 प्रतिशत उपदान पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए 4.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दुग्ध उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 20 प्रतिशत और अन्य नस्लों की गाय खरीदने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त उपदान प्रदान किया जा रहा है। जनवरी, 2019 तक प्रदेश के 63 विधान सभा क्षेत्रों में 96 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में जो ये जनमंच कार्यक्रम शुरू किए हैं, ऐसी योजना आजादी से

लेकर आज तक पहले कभी नहीं आई। इस जनमंच में यह बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया है कि मंत्री और सरकार के सभी ऑफिसर जनता के बीच जाएं और जनता की समस्याएं वहीं पर हल करें। ऐसा देश के अंदर पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी मंत्री मण्डल के सदस्य बधाई के पात्र हैं। पहले जिन लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी और जिन लोगों को अपनी समस्या को लेकर ऑफिसिज के कई चक्कर काटने पड़ते थे उन सभी लोगों को चाहे किसी भी पक्ष के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पार्टी के हो या किसी भी धर्म के लोग हो; उसी समय जनमंच के माध्यम से काम करवाने के लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा मिली है। माननीय मुख्य मंत्री अधिकारियों को आदेश देकर उनकी समस्या को उसी वक्त हल करवाते हैं। प्रदेश में पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने बहुत सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं और कुछ पाईप लाइन में हैं जो जनमंच पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कैम्प भी साथ में लगाए जाते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश के 38 हजार से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। पीछे 23 और 24 सितम्बर, 2018 को भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण लाहौल-स्पिति जिले में काफी पर्यटक फंस गये थे। वहां से भारतीय वायु सेना के 7 हैलीकॉप्टरों द्वारा 252 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसमें अगर सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जल्दी निर्णय न लेते तो 252 लोगों की जान खतरे में हो सकती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानवीय सेवा का परिचय देते हुए इसमें तुरन्त ऐक्शन लिया।

06/02/2019/1655/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के अंदर बहुत-सारी नई योजनाएं लाई है। सरकार ने 'गुडिया हैल्पलाइन' और 'शक्ति बटन मोबाइल ऐप' शुरू की है। गुडिया हैल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2019 तक 1398 शिकायतें मिली, जिनमें से 1344 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। प्रदेश में 'होशियर सिंह' हैल्पलाइन शुरू की गई है और भी बहुत-सारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की हैं। सरकार ने 'प्रधान मंत्री सड़क

योजना' के अंतर्गत जो डी0पी0आर्ज0 तैयार की है, उनमें हिमाचल प्रदेश को 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक 1863 करोड़ रुपये के करीब पैसा मिला है। इससे पूर्व एक साल में प्रदेश को कभी इतनी धनराशि नहीं मिली थी। इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

शिमला की गिरी पेयजल आपूर्ति योजना के स्त्रोत्र में जल की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होना है। विश्व बैंक ने 986 करोड़ रुपये शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना हेतु स्वीकृत किए हैं। पहली किस्त के रूप में 292 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा बिना किसी आय सीमा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई है और बिना किसी इनकम प्रूफ से इस योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। इसके तहत एक लाख तीस हजार लोग लाभान्वित होगें और 200 करोड़ रुपये का बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को गृह निर्माण के लिए भी 1.30 लाख रुपये की राशि प्रदान की की जा रही है। प्रदेश में 1442 मकान बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 18.36 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। भारत में 'उज्ज्वला योजना' माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू की थी। इस योजना के तहत 86 हजार गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश की जनता को मिले हैं और देश में लगभग 6 करोड़ लोगों को ये कनेक्शन मिले हैं। इससे देश के अंदर जो हमारी माताएं, बहनें सैंकड़ों बीमारियों से ग्रस्त हो जाती थी, उनको इनसे निजात मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने Weaker section of society के लिए यह एक ऐसी योजना लाई है, जिसके तहत जिन परिवारों के पास गैस का सिलेंडर व चूल्हा नहीं था, उनको ये फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। इसमें भी 40 हजार से अधिक कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि 6-8 महीने में प्रदेश के अंदर एक भी परिवार इस सुविधा से वंचित रहेगा। सरकार ने बहुत-सारे अस्पताल भी अपग्रेड किए हैं, नेरवा के सिविल अस्पताल को 75 बैडिड किया है और चौपाल के हॉस्पिटल को भी 50 से 100 बैडिड किया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने दूर-दराज़ के क्षेत्र में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, वहां ये सुविधा उपलब्ध करवाई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ जो निर्वाचन क्षेत्र थे, वहां 250-300 बैड के अस्पताल थे। वहां पर पहले 30-31 डॉक्टर्ज़ की वैकेन्सीज़ थी और जो हमारे दूर दराज़ की चौपाल चुनाव क्षेत्र हैं वहां पर 6-8 डॉक्टर्ज़ की पोस्टें थी और 30 बेडिड़ अस्पताल थे।

06-02-2019/1700 /NS/AG/1

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वरोज़गार और युवाओं के लिए "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" के तहत लगभग 80 करोड़ रुपये का बज़ट रखा है। इस योजना के तहत प्रदेश में जितने भी नौज़वान हैं, इनमें से कोई भी युवा साथी बैंक से 40 लाख रुपये तक ऋण ले सकता है। इस योजना से प्रदेश के युवाओं को व्यापार करने का मौका मिला है। वे पहले जैसे नौकरी के लिए घूमते थे, आज वे खुद दूसरे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए यह बहुत अच्छी योजना लाई है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं। अगर एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं तो मुझे समय बढ़ाना पड़ेगा। मैं दो विषय सदन के ध्यान में ला रहा हूं। एक तो पढ़ करके भाषण देने की परंपरा और नये सदस्यों को हम कई बार अलौ भी कर देते हैं। परन्तु इसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। दूसरा, हमारी नियमावली में बड़ा स्पष्ट है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ ले करके यहां नहीं आएंगे, जिसके ऊपर कोई प्रतीक (emblem)लगा हो और विशेष संदेश हो। हमारे दो माननीय सदस्यों से मेरी गुज़ारिश है कि वे इन नियमों को ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे पास तीन सदस्य और बोलने वाले हैं। इस माननीय सदन का समय 45 मिनट और बढ़ाया जाता है। माननीय बलबीर जी दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने "मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र " प्रदेश के अंदर 10 खोलने हैं और इसके लिए बज़ट में 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हिमाचल प्रदेश में इंडोर सभागृहों के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपये का बज़ट में प्रावधान किया है। "सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना" भी बढ़ा करके 750 रुपये प्रति माह तथा विकलांगों के लिए 1300 रुपये प्रति माह की गई है। पहले प्रदेश के अंदर सामाजिक सुरक्षा पैंशन लगभग 20-21 हज़ार होती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में एक साल में लगभग 1 लाख 22 हज़ार के करीब हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के अंदर जो 30 नई योजनाएं लाई थी, उनमें से अधिकतम योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हो गई हैं और कुछ अभी जो समय बचा है, उसमें लागू होनी हैं। वर्ष 2013-14 में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था ग्याहरवें नम्बर पर थी। आज विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था छठे नम्बर पर आई है। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरे विपक्ष वाले मित्र कह रहे हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा देश विश्व में एक अलग से अपनी पैंठ बना रहा है और विकास की दृष्टि से भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। इसके लिए देश के सभी वासी अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गरीब या मध्य वर्गीय परिवारों को जो राशन दिया जाता था, वर्ष 2013-14 में देश के अंदर लगभग 92,000 करोड़ रुपये का राशन दिया जाता था लेकिन वर्ष 2018-19 में लगभग 1 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये का राशन दिया जा रहा है। डबल से भी ऊपर गरीब परिवारों के राशन के लिए राशि दी गई है। वर्ष 2014-15 में लगभग 2.50 करोड़ परिवार देश के अंदर बिजली से वंचित थे। लेकिन मार्च 2019 तक सभी परिवार बिजली से लाभान्वित हो रहे हैं। यह भी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के अंदर इस समय 21 एम्ज़ कार्यरत हैं और इन 21 एम्ज़ में से 14 एम्ज़ की घोषणाएं वर्ष 2014 से अभी तक की गई है। यह भी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या वाईंड-अप करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पैंशन योजना " जिससे 15,000 या इससे कम सात वर्ष की आयु से ऊपर 3000/- रुपये प्रति माह

06.02.2019/1705/RKS/DC-1

पैंशन मिलेगी जोकि एक बहुत ही लाभान्वित योजना है। वर्ष 2013-14 में आय कर में दो लाख तक की छूट थी जिसे वर्ष 2019-20 में 5 लाख रुपये कर दिया गया जोकि मंझले व्यापारी व नौकरी पेशे वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत है। माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के प्रति रुचि नहीं ले रही है। मैं इनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने किसानों के ट्यूबवैल्स की बिजली 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपये प्रति यूनिट मंहगी की थी, जिसे हमारी सरकार ने एक रुपये से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश से पूरे प्रदेश के किसानों को इसका फायदा हो रहा है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और इसके लिए सभी किसान बधाई के पात्र हैं। जो प्रस्ताव यहां माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री राजिन्द्र गर्ग जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग(घुमारवीं)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया और जिसके ऊपर कल से यहां पर चर्चा हो रही है उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वर्ष के भीतर जो दिन-रात एक करके कार्य किए हैं उससे प्रदेश के विकास में एक नई इबारत लिखी जा रही है। जब एक वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ा था और उस पर जब चर्चा हुई थी तो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उस बजट

की किताब को ऐसे उठाया जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। उस बजट को इन्होंने कोरी किताब घोषित किया था। लेकिन एक वर्ष बाद माननीय राज्यपाल महोदय जी ने उसी बजट के ऊपर अपना अभिभाषण पढ़ा और अब इस पर जो चर्चा शुरू हुई है उसमें विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि जो उस बजट भाषण में था वह इसमें है ही नहीं। आज विपक्ष को उस पुस्तक में तो बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने करके दिखाया है वह नहीं दिख रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगले वर्ष आप फिर यही कहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक वर्ष के भीतर विकास के बीज बोए हैं उसकी फसल आने वाले समय में आप सबके सामने आएगी और प्रदेश की जनता के हित में जो विकास कार्य किए हैं उसकी इबारत साफ दिखाई देगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना पद संभालते ही पहला काम प्रदेश के बुजुर्गों के लिए समर्पित किया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप बुजुर्गों का सम्मान करना और इसे भली-भांति पहचानते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे बुजुर्गों के दर्द को समझते हुए सत्ता संभालते ही जो सबसे पहला काम किया वह यही किया

06.02.2019/1710/बी0एस0/डी0सी0-1

कि जो हमारे बुजुर्ग पैंशन योजना से वंचित रह जाते थे उनके लिए किया है। हम लोग भी जब जनसभाओं में जाते थे तो कहते थे कि बेटा हमारी पैंशन लगवा दो। लेकिन कोई भी प्रावधान इस बारे में नहीं होता था। इसकी कोई योजना न होने के कारण हम उनकी समस्या का हल नहीं कर सकते थे। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के बुजुर्गों के दर्द को समझते हुए इस सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 80 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु तक करके आज हजारों लोगों को पैंशन की सुविधा प्रदान की है । इस कार्य के लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज हमें कोई यह नहीं कहता कि मुझे पैंशन नहीं मिली परंतु जो लोग मिलते हैं वे यह कहते हैं कि हमारी पैंशन लग गई है । यह परिस्थिति एक वर्ष के अंदर-अंदर बदली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो दूसरा बड़ा निर्णय गौवंश के लिए लिया है। वह गौवंश के संबर्धन, संरक्षण और सम्मान के लिए निर्णय लिया है। प्रदेश के अंदर जो गौ वंश हमारा सड़कों पर बिखरा है, बेसहारा घूम रहा है। हमारी संस्कृति है कि हम गाय को गौ माता कहते हैं उस संस्कृति का उपहास हो रहा है । वहीं हमारे बेसहारा पशुओं के कारण हमारे किसानों की फसल तबाह होती है । किसान अपना खून, पसीना एक करके अपने खेतों में मेहनत करता है और इन बेसहारा पशुओं के कारण उनकी खेती तबाह होती है। उनका दर्द भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने समझा है और निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। जिसकी शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है । इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से जो जन मंच की चर्चा यहां पर चल रही है उसमें विपक्ष के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें जनता के दर्द का सीधा-सीधा जनता के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से सामने हल किया जाता है। वह जन मंच कार्यक्रम है । इस जन मंच की लोकप्रियता को देखते हुए जो सैलाब इन जन मंचो में आता है उसे देखते हुए विपक्ष की नींद उड़ गई है। कोई इसे झंड मंच कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, अशोभनीय और हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर यह झंड है तो यह झंड उन लोगों की है जो लोग पांच वर्ष तक प्रदेश में सत्ता पर रहे। अब मात्र एक वर्ष में लोगों की समस्याओं को कम किया जा रहा है तो स्वाभाविक भी उन लोगों की बेइज्जती हो रही है जिन्होंने वर्षों तक यहां राज किया। वे जनता की समस्याओं की परवाह नहीं करते थे परंतु अपनी कुर्सी बचाते रहे। विधायक भी मंत्रियों की कुर्सियों को खाली होने के इंतजार में रहे। इसी प्रकार पांच वर्ष का समय गंवाने के बाद आज जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिम्मत के साथ ईमानदारी के साथ जनता के साथ सीधा संवाद शुरू किया । अधिकारी जनता की समस्याओं का हल कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें दर्द तो होगा ही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जन मंच का कार्यक्रम शुरू किया है यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और लोगों की सहभागिता भी इसमें है। जिस उत्साह और रूचि के साथ लोग इन जन मंचो में आ रहे हैं वह माननीय मुख्य मंत्री जी का सफल कार्य सिद्ध हो रहा है। इस कार्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र है।

06.02.2019/1715/डी.टी./डी0सी0-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के अंदर चार महीनों में चार मैडिकल कॉलेज खोलना हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी सफलता है। जिसके कारण हमारे डाक्टर्ज भी मैडिकल कॉलेजों में अपने इंटरव्यू देने के लिए गए और उनकी सलैक्शन वहां पर हुई। बहुत सारे अस्पतालों में हमारे डाक्टर्ज के पद खाली थे कुछ विपक्ष के लोगों ने बड़ा हल्ला किया। लेकिन में अपने मानीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सारी समस्या का हल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया । डाक्टर्ज और पैरा मैडिकल स्टाफ की भर्ती जो लगातार प्रदेश के अंदर चल रही है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर AIIMS की चर्चा हो रही थी। एम्स की चर्चा करते वक्त कई सवाल यहां पर खड़े किए गए । अगर पिछली सरकार ने ईमानदारी के साथ कार्य किया होता तो आज एम्स के कार्य को शुरू हुए एक वर्ष का समय हो गया होता और उसका आधा कार्य भी हो गया होता। लेकिन पिछली सरकार के ढुल-मुल रवैये के कारण यह कार्य नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि यह एम्स आदरणीय मोदी जी ने दिया है यदि यह बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप लगातार इस कार्य को लटकाते रहे। परंतु प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनावों में चार में से चार सीटों को भारतीय

जनता पार्टी के पक्ष में डाल दिया और पूर्ण बहुमत दिया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक वर्ष के भीतर एम्स के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई है। उस भूमि को प्रदान कर आज एम्स का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए मैं माननीय नड्डा जी, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही मैं इनको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओं का नारा दे दे कर वोट लिए थे। लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि किसी ने करीबों के बारे में सोचा है तो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने सोचा है। इन्होंने सोचा ही नहीं परंतु करके भी दिखाया है। पहले चुनाव होते थे बड़े-बड़े पोस्टर छपते थे, उनमें कहा जाता था कि गरीबी हटाओ के लिए वोट दीजिए यह नारा ही दिया जाता था। परंतु जैसे ही वोट मिल जाते थे उसके बाद नेताओं के दर्शन तक नहीं होते थे। लेकिन बन्धुओ आज उज्ज्वला जैसी योजना चला कर आरणीय प्रधान मंत्री जी ने यह बता दिया है। उन्होंने कभी अपने लिए वोट नही मांगा और न पोस्टर छपवाए कि गरीबी हटाओ। लेकिन बिना कहे गरीबों के उत्थान का कार्य किया। आदरणीय मोदी जी ने गरीब के स्वाभीमान के लिए कार्य करके दिखाया । हमारी माताएं जो वर्षों से धुएं से अपनी आंखे खराब कर रही थी उस दर्द को यदि किसी ने समझा तो वह आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने समझा और उज्ज्वला योजना के तहत हर ऐसे घर में गैस कनैक्शन दिया जो कनैक्शन नहीं ले सकता था। हम बधाई देते हैं अपने आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को जिन्होंने उज्ज्वला योजना से दो कदम आगे बढ़ कर जो गरीब लोग इस योजना में शामिल नहीं हो पाए वे लाभ से वंचित न रह जाएं उन्हे भी गृहणी सुविधा योजना चला कर सुविधा प्रदान करने की कोशिश है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ शब्दों में यह ऐलान किया कि मेरे प्रदेश के अंदर कोई भी माता और बहन बिना गैस कनैक्शन के नहीं रहेगी। इस कार्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने टारगेट फिक्स किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी नारों से नहीं हटती, गरीब के घर के अंदर सुविधा पहुंचाना गरीब को सक्षम करना तभी गरीबी हट सकती है। गरीब का स्वाभीमान तभी बढ़ सकता है और गरीब का स्वाभीमान बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अनेक योजनाए चलाई हैं, चाहे वह प्रधान मंत्री दुर्घटना योजना हो, चाहे वह प्रधान मंत्री जीवन ज्योती योजना हो। मेरे विपक्ष के बंधु कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आपको 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे, कब दिए किसको दिए ? यह प्रश्न करते रहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने कभी यह नहीं कहा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि देश का जो काला धन है यदि वह बाहर आ जाए तो एक-एक व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख रुपये आ सकता है। लेकिन विपक्ष ने इस बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करके जनता को गुमराह करने का प्रसास किया

06-02-2019/1720/एच.के./एन.जी./1

और मोदी जी ने इन सारी योजनाओं को गरीब के उत्थान के लिए इस धरातल पर उतारने का काम किया है। मजदूर व्यक्ति जो पत्थर तोड़ता है, खेती करता है, तशला-तिगाड़ी उठाता है, वह व्यक्ति जिस का मकान बना रहा होता है वह दूर से देखता है कि जिस बाबू जी का मैं मकान बना रहा हूं , ये बाबू जी अपने लिए बीमा खरीद रहें हैं, अपनी पत्नी के लिए बीमा खरीद रहें हैं, अपने बच्चों के लिए बीमा खरीद रहें हैं, क्या मैं भी कभी बीमा खरीद पाऊंगा, ऐसा प्रश्न मजदूर व्यक्ति के दिल में आता है लेकिन वह कुंठित रहता है किसी से कह नहीं पाता। अगर किसी ने इस दर्द को समझा है तो वह हैं देश के माननीय प्रधान मन्त्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी । अगर मान लें कि दो लाख का जीवन बीमा है, जिसका पन्द्रह हज़ार या बीस हज़ार रूपये प्रतिवर्ष प्रिमियम देना पड़ता है, इतना प्रिमियम एक गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। मोदी जी गरीब के इस दर्द को समझा और प्रधान मन्त्री जीवन ज्योती बीमा योजना लेकर आये और उस बारह हज़ार प्रिमियम वाले बीमा को 330 रूपये का प्रिमियम वाला बीमा बनाया। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना बीमा

करवाने के लिए सक्षम किया और उनके स्वभिमान को जगाया। यह गरीबों के स्वाभिमान और गरीबों के लिए काम करने का एक उदाहरण है। इसे आपको (विपक्ष की ओर संकेत करते हुए) समझने की जरूरत है। इसलिए गरीब के उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमन्त्री जी ने और हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कार्य किये हैं उसके लिए हम उनको बहुत-बहुत बधाई देते है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विकास के कार्य किये हैं वह सराहनीय है। जब बजट बुक आई थी तब मरे विपक्ष के मित्रों ने कहा था कि इसमें तो कुछ नहीं, बजट बुक के बाद जब हमारे बीच में उपलब्धियों की बुक आई तो यह कह रहें हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है और उसमें तो बहुत कुछ था। ऐसा ही आने वाले बजट में भी मिलेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। मै माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का इस सदन में आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने विकास के लिए जो कदम उठाये हैं उसमें मेरे घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए भी इन्होंने दिल खोल कर विकासात्मक घोषणाऐं की हैं, उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उसमें चाहे घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र देने की बात हो, चाहे वहां मिनी सैक्ट्रीएट देने की बात हो, चाहे वहां के सिविल हॉस्पीटल को 50 बैडेड से 100 बैडेड करने की बात हो, चाहे वहां के संस्कृत कॉलेज को सरकार के अधीन लाने की बात हो, चाहे हमारे भराड़ी के अस्पताल को 30 से 50 बैडेड करने की बात हो, ऐसी अनेक सौगातें आपने हमको दी हैं और एक बड़ी सौगात धधोल से लदरौर की जो सड़क है उसके लिए विश्व बैंक से 82 करोड़ रूपये धनराशि आपके द्वारा स्वीकृत करवाई गई है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह से जो धन्वाद प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा उसका मैं पूरजोर समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी - अनुपस्थित ।

श्री राजेश ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा और जिसका श्री बलवीर जी ने समर्थन किया उसके लिए मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मै इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। दो दिन से इसी पर चर्चा चल रही थी। वर्तमान सरकार की योजनाओं के बारे में सत्तापक्ष के लोग जब बोल रहे थे तो विपक्ष के लोग कह रहें थे कि कुछ भी अच्छा नहीं। हमें भगवान ने इस विधानसभा में आने का मौका दिया पहले तो हम अख़बार में पड़ते थे कि विधानसभा में यह होता है, विधानसभा में वो होता है, परन्तु यह विपक्ष किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक वर्ष में कुछ भी अच्छा किया। एक वर्ष पहले जब माननीय प्रधानमन्त्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी वर्तमान सरकार के गठन के समय शपथ समारोह में आकर माननीय मुख्य मन्त्री, श्री जय राम ठाकुर जी के हाथों में इस प्रदेश की बागडोर दी थी और फिर एक वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद जब 27 दिसम्बर को धर्मशाला में प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए उन्हें प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया, यह वह निर्णय थे जो धरती पर उतारे गये, उन निर्णयों को माननीय प्रधानमन्त्री महोदय ने देखा और पूरे प्रदेश की जनता के सामने

06/02/2019/1725/RG/YK/1

उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री जी की पीठ थपथपाई और वे इनको बधाई देकर गए कि जय राम ठाकुर जी आपने प्रदेश में वह कर दिया जो पांच साल सरकार नहीं कर सकती थी।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक स्वास्थ्य के बारे में बात होती है तो हमने डायलैसिस की सुविधा दी, लेकिन ये कहते हैं कि देर में यह सुविधा दी। पहले तो यह सुविधा थी ही नहीं। गौसंवर्धन की बात आती है तो ये कहते हैं कि 15% मंदिरों का क्यों दिया? एक रुपया शराब पर टैक्स लगा। जो यह काम करते होंगे, यह पुण्य कार्य करने का मौका हमारे मुख्य मंत्री जी ने आपको भी दिया है। लोग कहते हैं कि पहली रोटी गौ-माता के लिए निकाली जाती है तो वह पहला ग्रास देने का मौका हमारे मुख्य मंत्री जी ने आपको भी दिया है और इस पुण्य कार्य के भागीदार आप भी बने हैं। गृहिणी योजना, आपके लिए बुरी है, जनमंच कार्यक्रम योजना आपके लिए अच्छा नहीं है, पेन्शन के लिए आयुसीमा 80 वर्ष से घटाकर

70 वर्ष कर दी, वह भी ठीक नहीं, खनन नीति पर हमारे मंत्री जी 121 खदानों के ऊपर ऑन लाईन टैण्डर करते हैं जिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा धन सरकार को आएगा, आपके लिए तो वह भी ठीक नहीं। नशा रोकने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी तीन मुख्य मंत्रियों के साथ पंचकूला में बैठक करते हैं, वह भी आपके लिए ठीक नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। यहां हमारे सारे विधायकगण बैठे हैं परन्तु सात बार जीते हुए हमारे बीच ठाकुर महेन्द्र सिंह जी बैठे हैं। इन्होंने बड़ा कालखण्ड देखा है। इन्होंने विधायक होते हुए जेल भी देखी है और विधायक होते हुए मंत्री पद भी देखा है। परन्तु मैं इस सदन में बोलना चाहता हूं कि पहली बार अगर प्रदेश को कोई ऐसा सहनशील और ईमानदार व्यक्ति मिला है, जिसके पास विधायक अपनी मर्जी की बात कह सकता है, तो वह जय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है। विपक्ष का काम तो कहना होता है और किसी ने कहा भी है :

'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई,
जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई।

इस सदन में हमारी सरकार की किसी नीति पर तो अच्छा बोल दो। प्रदेश की जनता आपको देख रही है। अगर हमने कुछ अच्छा नहीं किया, तो हम इस पक्ष में या सरकार में क्यों बैठे? फिर तो आपको बैठना चाहिए था और अगर आपने अच्छा किया होता तो आपको भी जनता ने उधर क्यों बैठाया? परन्तु यह बात याद रखना कि यह पब्लिक है, यह सब जानती है। यह दुनिया सब जानती है। हम जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लें। जनमंच के ऊपर इनको बहुत पीड़ा हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। जब दस पंचायतों में हमारे अधिकारी जाते हैं तो लोगों के फोन आते हैं कि अरे, अधिकारी हमें ढूंढ रहे थे। वे बी.जे.पी. और कांग्रेस वालों के घरों में नहीं जाते। वे गांवों में जाते हैं और पूछते हैं कि किसी की कोई शिकायत है, तो बोलो। जनमंच में कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि यहां कांग्रेस या बीजेपी वाला आ सकता है। वहां खुली जनता अपनी शिकायत लेकर आती है, पूरे क्षेत्र में कोई भी अपनी समस्या ऑन लाईन दर्ज करवाकर अपनी बात वहां रख सकता है और फिर माईक पर बोल सकता है। पहले छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों को जलालत झेलनी पड़ती थी और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इनकी सरकार के समय एक योजना थी जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, 'सरकार आपके दरबार।' सरकार आपके दरबार में आती थी, जनता भी आती थी। परन्तु जब भोजन का समय होता था तो रैस्ट हॉऊस के

ऊपर के कमरे में सरकार बैठी होती थी और नीचे लोग भूख से तड़प रहे होते थे। आज प्रदेश की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है और आज हम यहां बैठे हैं तो उनकी खातिर बैठे हैं जो लोग गांवों में बैठे हैं और अगर उन लोगों को भोजन की व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है तो कहते हैं कि ये लन्च-मन्च था और हमारे मंत्री एवं हमारी आई हुई जनता

06/02/2019/1730/MS/YK/1

एक साथ समस्या सुनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकारों में मंत्रियों के कितने दौरे होते थे, यह सभी को पता है। परन्तु पहली बार प्रदेश में हमारे 65 विधान सभा क्षेत्रों में एक साल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दौरे किए और जो काम किए, उन्हें धरती पर उतारा। इसके अलावा 96 जनमंच हुए और 96 बार मंत्री इन जनमंच में पहुंचे। जनता तो यही चाहती है कि मंत्री आए और हमारी समस्या का समाधान हो। परन्तु हमारे विपक्ष के नेता जो यहां बैठे हैं, ये तो ऊना के चार क्षेत्रों में भी ज्यादा जा नहीं सके, प्रदेश की तो बात छोड़िए। ये केवल अपने ही भवन खड़े करते रहे।

यहां गऊ-सदन के बारे में आशा कुमारी जी बोल रही थीं कि धरती पर कुछ उतरा ही नहीं। पिछली सरकार के समय में उच्च न्यायालय से निर्देश आया कि गौमाता सड़क पर भटक रही है, इसको आश्रय दीजिए लेकिन आपकी सरकार नहीं चेताई और फिर उच्च न्यायालय ने अफसरों को फटकार लगाई। तब जाकर पंचायतों को पैसा दिया गया और छोटे-छोटे गऊ-सदन बने लेकिन उनमें एक भी गाय नहीं बंधी। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक साल में कोटलाबरंग में 1 करोड़ 52 लाख रुपये से जल्दी ही गऊमाता को आश्रय हेतु गऊधाम बनेगा। डमटाल में 3 करोड़ 97 लाख रुपये से गऊधाम बनने जा रहा है और जल्दी ही मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी वहां आएंगे। हांडाकुण्डी में 2 करोड़ 97 लाख रुपये से, थानाकलां में 1 करोड़ 69 लाख रुपये से और गोकुलधाम में 34 करोड़ रुपये से गऊधाम बनेगा। यह किसके राज में हुआ? यह माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी की सोच है कि जिस गऊमाता को कोई आश्रय नहीं दे सकता था, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्रय देकर धरती पर उतारा है।

यहां पर प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी। माननीय विपक्ष के नेता कल गिन रहे थे और कह रहे थे कि आपकी केन्द्र सरकार के 24 दिन शेष रह गए हैं। विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय और सम्माननीय हैं। आप ये दिन गिनना छोड़ दीजिए क्योंकि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर आप भविष्यवाणी करते तो आज हम यहां नहीं होते और आप उधर न होते। नरेन्द्र भाई मोदी जी को 125 करोड़ जनता ने पहले भी चुना था और अब फिर चुनेगी, यह आप तय मान लो। पिछली सरकार में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री थीं जो अब इस सदन में नहीं हैं। उस समय विभाग अफसर चलाते थे। आज हमारे बीच सात बार जीते हुए आई0पी0एच0 मंत्री जब प्रदेश का दौरा करते हैं तो अफसर हमारे काम बिना इनके कहने से ही कर देते हैं। हमें ऐसा मंत्री चाहिए था और हमें मिला भी है। यह हमारा सौभाग्य है। इसी तरह से आपके इलाके में जो फैक्टरी लगी थी जिसमें करोड़ों रुपयों की धांधली थी, उसको आते ही ईमानदारी से बन्द किया। आज हमारे शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। इनके विभागों में भर्तियां हो रही हैं और हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। परन्तु आप कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही है कि विधान सभा में हमने केवल यही बोलना है कि कुछ नहीं हो रहा है तो क्या सरकार अपने आप चल रही है? आने वाले समय में चार लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तो हमने जनता की रैलियां करवाई ही नहीं हैं बल्कि अभी तक तो कार्यकर्त्ताओं की रैलियां हो रही हैं और उन रैलियों में 40-40 हजार की हाजिरी है। जिस दिन जनता के जुलूस निकलेंगे और मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जिस दिन चारों सीटों पर लोकसभा में हम अपने चार सांसद भेजेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक वर्ष में क्या किया है। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं और बाहर जनता भी इनको बधाई दे रही है। मैं तो यह भी कहता हूं कि छः बार हमारे सम्माननीय वीरभद्र सिंह जी को छः बार मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला परन्तु लगातार दुबारा नहीं मिला बल्कि रुक-रुक कर मिला। पांच साल के बाद मौका मिलता रहा परन्तु यह कालखण्ड ऐसा आने वाला है,

06.02.2019/1735/जेके/वाईके/1

मैं यह इस विधान सभा में बोल रहा हूं कि तथ्य है कि अगली बार सरकार यहां से रिपीट होगी, हम फिर यहां होंगे, आप फिर वहां होंगे। अपनी बात को विराम देते हुए मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक कल दिनांक 7 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 6 फरवरी, 2019 **सचिव ।**